चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

06 जनवरी 2014–12 जनवरी 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

कौन कर रहा है मोदी की जय-जय

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

संतोष भारतीय

आइए हम भी नरेंद्र मोदी की जय–जयकार करें. क्योंकि सारे देश में नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही हैं. भीड़ आ रही है और ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे. नरेंद्र मोदी की ताजपोशी में इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई उनकी छवि चमका रहा है, तो वह हिंदुस्तान का मीडिया है. जब हम मीडिया कहते हैं तो उसमें टेलीविज़न न्यूज चैनल पहले होते हैं और कुछ अख़बार बाद में आते हैं. यह नरेंद्र मोदी की होशियारी थी कि उन्होंने तीन साल पहले से अपने को देश में प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी थी. गुजरात के सारे उत्सव चाहे कच्छ के रण का महोत्सव हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की पतंग प्रतियोगिता हो, यह सब देश के लोगों में नरेंद्र मोदी का नाम स्थापित करने की योजना के हिस्से रहे हैं. नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक अमिताभ बच्चन को लेकर खेला. उन्होंने उन्हें गुजरात टूरिज्म और गुजरात की संस्कृति का ब्रांड ऐंबेस्डर बनाया. अमिताभ बच्चन को सचमुच कितनी फ़ीस दी गई, पता नहीं, लेकिन अमिताभ बच्चन के चेहरे ने अचानक नरेंद्र मोदी को देश के सबसे चर्चित शख़्स के रूप में स्थापित कर दिया और देश के लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जो शख़्स अमिताभ बच्चन को गुजरात में लेकर आ सकता है, वह शख़्स देश में क्या नहीं कर सकता.

नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत से मिले, तो उन्होंने मोहन भागवत से सिर्फ़ एक बात कही कि अगर आप मुझे खुला हाथ दें तो मैं देश का प्रधानमंत्री बनकर दिखा सकता हूं. मोहन भागवत ने सारे व्यक्तित्वों के बारे में सोचा और अंततः वह इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे अच्छा चेहरा नरेंद्र मोदी का ही है. नरेंद्र मोदी ने उसके पहले संघ को उसके दायरे में घेर दिया था. इससे मोहन भागवत संघ की खंडित होती प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना चाहते थे. नरेंद्र मोदी के ज़रिए वह लालकृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा या सत्तर साल से ऊपर के सारे लोगों को एक सबक़ सिखाना चाहते थे. दरअसल, लालकृष्ण आडवाणी संघ और भाजपा में सबसे वरिष्ठ हैं. इसलिए संघ का कोई भी आदमी आडवाणी जी के पास जाकर ज्यादा बात नहीं कर पाता था. आडवाणी जी भी संघ के लोगों को इसलिए तरजीह नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये सारे लोग उनके सामने संघ में आए हैं और उन्हें राजनीति के अंदरूनी समीकरणों का कुछ भी ज्ञान नहीं है. इसलिए जब नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत के सामने अपनी ख़्वाहिश रखी कि उन्हें खुली छूट दी जाए या खुला हाथ दिया जाए तो मोहन भागवत ने इसका फ़ैसला कर लिया. जिसके पहले शिकार मुंबई अधिवेशन में संजय जोशी हुए. संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों में रहे हैं, जिनके ऊपर कार्यकर्ताओं का अगाध विश्वास रहा है. संजय जोशी एक कथित सीडी की वजह से भाजपा से हटाए गए. बाद में वह सीडी फेक साबित हुई और लगा कि संजय जोशी फिर से संघ और भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष स्थान पर पहुंचेंगे. पर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के समझौते ने पहली बलि संजय जोशी की ली.

इसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो भी परिवर्तन हुए वो सभी नरेंद्र मोदी की इच्छानुसार हुए. नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के दूसरे शिकार बने. दरअसल, राजनाथ सिंह का अध्यक्ष बनना भी नरेंद्र मोदी की ही इच्छा का परिणाम रहा है. नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया और उन्हें अपने सबसे विश्वस्त व्यक्ति के रूप में गुजरात से निकालकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय राजनीति में ले आए. अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभार नरेंद्र मोदी ने इसलिए दिया, क्योंकि

मोदी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत से मिले, तो उन्होंने मोहन भागवत से सिर्फ़ एक बात कही कि अगर आप मुझे खुला हाथ दें तो मैं देश का प्रधानमंत्री बनकर दिखा सकता हूं. मोहन भागवत ने सारे व्यक्तित्वों के बारे में सोचा और अंततः वह इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे अच्छा चेहरा नरेंद्र मोदी का ही है. नरेंद्र मोदी ने उसके पहले संघ को उसके दायरे में घेर दिया था. इससे मोहन भागवत संघ की खंडित होती प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना चाहते थे. नरेंद्र मोदी के ज़रिए वह लालकृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा या सत्तर साल से ऊपर के सारे लोगों को एक सबक़ सिखाना चाहते थे.

उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश का कोई भी नेता उन्हें धोखा दे सकता है. इसलिए वो अपने सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में इसलिए लाए, क्योंकि वो वहां पर ऐसे उम्मीदवारों की तलाश करना चाहते थे, जिनकी पहली स्वामिभक्ति नरेंद्र मोदी के प्रति हो, संघ या भाजपा के प्रति नहीं.

इसके बाद नरेंद्र मोदी ने देश में सभाओं की धूम मचा दी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जिस एंगल से तस्वीरें खींची गईं वो बताता है कि पटना का गांधी मैदान पूरा भरा था. लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो यह साबित करते हैं कि मैदान आधे से थोड़ा–सा ही ज्यादा ही भरा था, पूरा नहीं भरा था. नरेंद्र मोदी एक कुशल संगठनकर्ता हैं और उन्होंने भव्यता के साथ अपने को भारत का भावी प्रधानमंत्री घोषित करवा लिया. नरेंद्र मोदी हर सभा को भव्यतम तरीक़े से करने के आदी रहे हैं. राज्यों में होनी वाली रैलियों में कितना पैसा ख़र्च हो रहा है, लोग कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किनके द्वारा लाए जा रहे हैं, ये सारे सवाल नेपथ्य में चले गए. नरेंद्र मोदी ने और उनके सिप–हसालारों ने माहौल ऐसा बना दिया है कि जो भीड़ है, वो अल्टीमेट है और ये भीड़ नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहती है. नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री आज ही बन गए दिखाई देते हैं, अगर हम भाजपा के प्रचार तंत्र का चश्मा अपनी आखों पर लगा लें.

इसी बीच दिल्ली के चुनाव आ गए. दिल्ली के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने काफ़ी ताक़त लगाई और पार्टी ने उनकी मीटिंगें उन जगहों पर कराईं, जहां पर उन्हें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है. नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भी सभाएं कीं और छत्तीसगढ़ में भी, यहां तक कि वे मध्य प्रदेश भी गए. इन चुनावों के नतीजे आए और नतीजे आने के बाद सबसे पहले अगर किसी की आंख खुली, तो उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस या संघ के नाम से ज्यादा जानते हैं, के लोगों में आपस में चर्चाएं शुरू हुईं, मंथन शुरू हुआ और विश्लेषण के बाद संघ ने ये माना कि देश में मोदी की लहर या मोदी वेव नहीं है. उन्होंने अपनी इस प्रतीति को छिपाया नहीं, बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर खुलासा किया कि उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी संभवतः अकेले देश में प्रधानमंत्री पद के लिए सीटें लाने में बहुत कारगर साबित नहीं हो पाएंगे और संघ ने इसके पीछे जो विष्लेषण भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कुछ नेताओं के सामने रखा उसका लब्बोलुआब यह था कि छत्तीसगढ़

(शेष पृष्ठ 2 पर)

यह जनविरोधी मॉडल है 03

कॉरपोरेट के कंधे पर सवार मोदी लहर 05

गुजरात : मुसलमान बदहाल, विकास केवल ढकोसला 06

साई की महिमा 12

कौन कर रहा है मोदी की जय-जय

पृष्ठ एक का शेष

में इतनी सभाओं के बाद भी दो तिहाई बहुमत नहीं आया, बल्कि सामान्य बहुमत के लिए भी भाजपा को ऐड़ी-चोटी का ज़ोर लगाना पड़ा. मध्य प्रदेश के बारे में संघ का यह मानना है कि वहां पर कांग्रेस की आपसी लड़ाई की वजह से वह कभी युद्ध में आ ही नहीं पाई. वहां की जीत शिवराज सिंह के चेहरे की और उनके काम की जीत है. संघ ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि कांग्रेस पार्टी न केवल आपस में लड़ रही थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार दिन में सभाओं में रहते थे और रात में वह दिल्ली सोने के लिए चले आते थे. इस बात का प्रचार संघ ने अपने कार्यकर्ताओं के ज़रिए मध्य प्रदेश में कराया. मध्य प्रदेश में कांग्रेस के झगड़ों का हाल इतना उत्तम था कि एक जगह तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकेले जाने की इच्छा को पूरी करने के लिए दिग्विजय सिंह को दरवाज़े से बाहर खड़ा कर दिया. वे दरवाज़ा खटखटाते रहे, लेकिन सिंधिया ने दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलवाया. राजस्थान में संघ का मानना है कि वहां की हार अशोक गहलोत की बेवकूफ़ियों की हार है और वसुंधरा की जीत भी अशोक गहलोत की मूर्खताओं की वजह से हुई जीत है, अन्यथा आजतक राजस्थान में इतना बड़ा बहुमत किसी का आया ही नहीं. कांग्रेस अपने जीवन के निकृष्टतम स्कोर के ऊपर पहुंच गई. दिल्ली में सबसे ज्यादा संघ को इस फ़ैसले पर पहुंचने में मदद की. भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 31 सीटों पर आकर रुक गई. संघ का मानना है कि अगर ये मोदी का करिश्मा होता या उनकी लहर होती तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में दो तिहाई बहुमत हासिल करती, यहां वो सामान्य बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई. यहां तक कि उसने जितने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के वोट काटे, कांग्रेस के नहीं. यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा करते हैं कि दूसरे नंबर पर आई आम आदमी पार्टी के भीतर उसके सात से आठ सदस्य विधानसभा में पहुंच गए हैं.

संघ ने तत्काल नरेंद्र मोदी के साथ आडवाणी जी को भी साधना शुरू कर दिया, क्योंकि मोहन भागवत का यह बयान केवल शिष्टाचार नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा कि आडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं जाना चाहिए. मोहन भागवत चाहते तो ये वक्तव्य अकेले कमरे में बैठकर अपने चार दोस्तों के साथ कह सकते थे. लेकिन उन्होंने सार्वजनिक मंच चुना और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संकेत दिया कि अगर नरेंद्र मोदी 272 सीटें नहीं ला पाते हैं तो आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है. जहां संघ पहले 75 वर्ष से ज्यादा के लोगों को टिकट देने के लिए तैयार नहीं था, जिसमें उसने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह को यह साफ संदेश पहुंचा दिया था कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला. यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा भी इसी श्रेणी के नेता आंके गए. लेकिन अचानक संघ ने अपना फ़ैसला बदला और जसवंत सिंह राजस्थान से और आडवाणी गुजरात से चुनाव लड़ेंगे, इस तरह के समाचार लीक कर दिए. संघ का ये भी आकलन है कि मोदी 80 से 100 सीटें लाने में क़ामयाब होंगे जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आ सकती हैं. बाक़ी की सीटें कहां से आएंगी, इस पर संघ माथा-पच्ची कर रहा है. इसीलिए संघ ने भविष्य के सहयोगियों की तलाश भी शुरू कर दी है. लेकिन इस बार संघ को आशंका है कि भाजपा का सबसे विश्वस्त सहयोगी रहा जनता दल यूनाइटेड इस बार उनका साथ नहीं देगा. सिद्धांतों के आधार पर शरद यादव और नीतीश कुमार ने यह फ़ैसला लिया कि वे अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ नहीं मुड़ेंगे, बल्कि वे देश में एक नई राजनीति का केंद्र बनेंगे. जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी हर जगह बातचीत में कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ़ जाने वाला कोई भी रास्ता अब जेडीयू के सामने नहीं है. उसके सामने एक ही रास्ता है कि दिल्ली में कैसे गैर-भाजपा और गैर-कांग्रेस सरकार बने.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी समस्या आम आदमी पार्टी का दिल्ली में उभरना भी है. भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल को असफल होते देखना चाहती है. उसे ये लगता है कि तीसरा मोर्चा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल भविष्य में यानी चार महीने के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में, भाजपा विरोधी ताक़तों का केंद्र बन सकते हैं. उन्हें ये भी डर सता रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली, पानी और अवैध कालोनियों को नियमित करने के फ़ैसले पर अमल कर लिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने सारे देश में समस्या खड़ी हो जाएगी.

भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी समस्या आम आदमी पार्टी का दिल्ली में उभरना भी है. भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल को असफल होते देखना चाहती है. उसे ये लगता है कि तीसरा मोर्चा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल भविष्य में यानी चार महीने के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में, भाजपा विरोधी ताक़तों का केंद्र बन सकते हैं. उन्हें ये भी डर सता रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली, पानी और अवैध कालोनियों को नियमित करने के फ़ैसले पर अमल कर लिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने सारे देश में समस्या खड़ी हो जाएगी.

संघ इस बात से भी चिंतित है कि जहां एक तरफ़ 272 सीटें न आने की स्थिति में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे. वहीं अगर 200 सीटें भी भाजपा ले आती है, तब भी भाजपा का प्रधानमंत्री बनने की राह में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी खड़े हो सकते हैं. ये दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके मिलने की संभावना भविष्य में दिखाई दे रही है और ये दोनों मिलकर देश में गैर-कांग्रेस और गैर-भाजपा सरकार बनने की संभावना को मज़बूत कर सकते हैं. दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं लड़ेंगे और अगर वक्त आया तो वे किसी तीसरे को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं. दरअसल, इन दोनों मुख्यमंत्रियों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस-दोनों की आर्थिक नीतियां एक हैं और दोनों ही देश में बेरोज़गारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में एक-दूसरे से पीछे नहीं हैं. दोनों ही पार्टियां विकास नहीं चाहतीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करना चाहती हैं. दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने गांव आधारित आर्थिक नीति की वकालत करनी शुरू कर दी है. गांव को मज़बूत करना, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, कृषि आधारित उद्योगों का जाल, नये सिरे से इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना आदि ऐसे विषय हैं, जिनपर दोनों ही मुख्यमंत्री एकमत हैं. संघ की सबसे बड़ी चिंता अन्ना हजारे हैं. अगर कहीं अन्ना हजारे ने इस नई धारा का समर्थन कर दिया तो फिर बीजेपी के हाथ से सत्ता फ़िसल जाएगी. बीजेपी को या संघ को कांग्रेस की चिंता ही नहीं है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि कांग्रेस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की हार से कोई सबक नहीं सीखा है. उनकी चिंता सिर्फ़ ममता बनर्जी और नीतीश कुमार हैं. उनकी सबसे बडी चिंता अन्ना हजारे हैं. इसलिए इस समय संघ ने अपने सारे सूत्रों को अन्ना हजारे के पीछे लगा दिया है, ताकि वे उन्हें ये समझाएं कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो वह अन्ना हजारे की बहुत सारी मांगों को पूरा कर देगी. बीजेपी ग्रामसभा को मज़बूत करने की बात तो करती है, लेकिन वह गांव आधारित आर्थिक नीति बनाने की बात नहीं करती.

जनवरी महीना और फरवरी का पहला हिस्सा देश में नये राजनीतिक गुल खिला सकता है जिसकी जड़ में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का अति उत्साह है. देखते हैं संघ का ये आकलन और संघ का ये डर भविष्य में कितना सच साबित होता है. और यह भी देखना है कि देश को मोदी की जय-जयकार करना नसीब होता है या नहीं. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 44
दिल्ली, 06 जनवरी 2014–12 जनवरी 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

भ्रामक शब्दावली

दिलीप चेरियन

नौकरशाह ऐसे तो मृदु होते हैं, लेकिन उनकी मृदु लगने वाली भाषा के मायने कभी कभी विभागीय लोगों के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं. नौकरशाहों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा में अधिकांशत: वाक्यांश (फ्रेज़) कंपल्सरी वेटिंग का उपयोग होता है, जो पुरस्कार से ज्यादा सज़ा की ओर इंगित करता है. इस वाक्यांश को सिलीगुड़ी के तात्कालिक पुलिस कमिश्नर ते जयरामन के मामले में बेहतर रूप से समझा जा सकता है. जयरामन ने मालदा के जिलाधिकारी जी किरणकुमार (आईएएस) को एक मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें कंपल्सरी वेटिंग (प्रतीक्षा सूची) में डाल दिया गया. इस वाक्यांश का अनुवाद करने पर मतलब निकलता है कि अधिकारी की न ही नियमित तौर पर नियुक्ति की गई है, न ही उसे एक पदाधिकारी के रूप में मिलने वाली सुविधाएं, मसलन कार की सुविधा और बिलों की प्रतिपूर्ति आदि मिलेंगी. अधिकारी को निर्देशित ऑफिस में नियमित सूचना देनी होती है और पद के रिक्त होने तक कार्यभार ग्रहण करने के लिए इंतज़ार करना होता है, इसलिए मृदु दिखने वाला यह वाक्यांश उन लोगों के लिए एक तरह की सज़ा की ओर संकेत करता है. जिन्हें पहले ताक़त दी गई थी, अब वही डरे हुए हैं.■

देर से जागे?

दिल्ली भारतीय राजनयिक देवयानी खोरबोगड़े द्वारा अपनी नौकरानी को ग़लत दस्तावेज़ों की मदद से वीज़ा दिलवाने के आरोप की वजह से भारत और अमेरिका के बीच उपजे राजनयिक विवाद को सुलझाने में जुटी है. लेकिन एक युवा राजनयिक के साथ किए गए व्यवहार के विरोध में भारत द्वारा अप्रत्याशित रूप से की गई कड़ी प्रतिक्रिया ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. इससे पहले की उस प्रक्रिया पर विराम लग गया जिसमें भारत की प्रतिक्रिया को बेहद नाजुक और अपर्याप्त माना जाता था. लेकिन इस बार भारत ने एक कदम आगे बढ़कर अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया है. मगर लोगों को उस भारतीय नौकरानी की चिंता हो रही है, जो इस पूरे विवाद की धुरी है. कुछ लोग इस राजनयिक विवाद को भारतीय विदेश मामलों की स्थापना के अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक अवसर के रूप में देख रहे हैं.■

आंध्र के बंटवारे की तैयारी?

कम से कम लोगों के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी इस बात की आशा जताते दिखते हैं कि प्रदेश का बंटवारा नहीं होगा. हालांकि, मीडिया का कहना है कि तेलंगाना का गठन एक पूर्वनियोजित निर्णय है. इंतज़ार केवल राष्ट्रपति द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल पर दस्तख़त करने का है. राज्य के नौकरशाहों ने राजकीय संपत्ति के बंटवारे की तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों के अनुसार, मुख्य सचिव पी के मोहंती ने सभी विभाग के प्रमुखों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के अधिकारियों से बांटी जा सकने वाली संपत्तियों, कर्मचारियों, अधिकारियों और ज़िम्मेदारियों की सूची तैयार करने के लिए कहा है.

चूंकि राज्य का बंटवारा एक जटिल कार्य होगा, इसलिए मोहंती ने यह मान रहे हैं कि बंटवारे को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है. इसलिए उन्होंने केंद्र के निर्देश पर बंटवारे की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दूसरी ज़रूरतों के मुताबिक़, सरकारी कर्मचारियों से इस बाबत फॉर्म भरवाने भी शुरू कर दिए हैं कि वे बंटवारे के बाद तेलंगाना जाएंगे या सीमांध्र में रहेंगे. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

शर्मा असम पुलिस के प्रमुख बन सकते हैं

1982 बैच के आईपीएस अधिकारी खगेन शर्मा को असम के महानिदेशक (डीजीपी) जयंत नारायण चौधरी के स्थान पर जल्द ही नियुक्त किया जा सकता है. खगेन को 15 सालों तक राज्य पुलिस की विशेष शाखा का मुखिया रहने के बाद इस साल के शुरुआत में महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) नियुक्त गया था.

संतोष एनसीएसटी के प्रमुख होंगे

1990 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी संतोष कुमार को राष्ट्रीय अनुसूचित और जनजातीय आयोग में संयुक्त सचिव के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है. कुमार 1977 बैच के भारतीय आयुध निर्माण सेवा के आदित्य मिश्र का स्थान ग्रहण करेंगे. मिश्र ने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा किया है.

शक्तिकांत सचिव नियुक्त

1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस शक्तिकांत दास को उर्वरक मंत्रालय में अगला सचिव नियुक्त किया गया है. वर्तमान में वह आर्थिक मामलों वाले विभाग (डीईए) में विशेष सचिव के तौर पर सेवारत हैं.

चेतिया यूआईडीएआई के प्रमुख बने

1994 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी पीयुष चेतिया को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सहायक महानिदेशक नियुक्त गया है. चेतिया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में डी खौंड के इस साल कार्यकाल समाप्त होने के बाद लाए गए हैं.

आनंद निदेशक नियुक्त

1997 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (सी और सीई) पी आनंद कुमार को प्रवासी भारतीय मामले वाले मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है. कुमार को (1991 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा) शिव रतन के स्थान पर लाया गया है. शिव रतन को वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में सामूदायिक मामलों (विकास) के काउंसलर के पद पर स्थांतरित किया गया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल

यह जनविरोधी मॉडल है

2014 लोकसभा चुनाव के लिए मोदी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं. सच बात तो यही है कि देश पिछले 20 सालों में आगे जाने की बजाय विकास के सफ़र में पीछे छूट गया है. ग़रीब और ग़रीब हो गए और अमीर पहले कई गुणा ज्यादा अमीर हो गए. किसानों की हालत ख़राब है. वो आत्महत्या कर रहे हैं. खेतों को छोड़ कर शहरों में पलायन कर रहे हैं. दुनिया के सबसे ज्यादा युवा भारत में तो रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि यहां सबसे ज्यादा बेरोज़गार भी रहते हैं. कृषि, उद्योग, खनन और निर्माण क्षेत्र में भारत की स्थिति दयनीय है. कांग्रेस पार्टी की नीतियों का असर पिछले तीन सालों में भारत की जनता न सिर्फ़ देख रही है, बल्कि झेल भी रही है. नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं. तो सवाल यह उठता है कि अर्थव्यवस्था की बदहाली से उबारने का कोई मंत्र क्या नरेंद्र मोदी के पास है. नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गुजरात के मॉडल को वो पूरे देश में लागू करेंगे. तो यह समझना ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी का आर्थिक एजेंडा क्या है?

मनीष कुमार

इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात विकास के ज्यादातर मापदंडों पर दूसरे राज्यों से काफ़ी आगे है. गुजरात में देश की जनसंख्या के सिर्फ़ पांच फ़ीसदी लोग रहते हैं, लेकिन उद्योग में इसका योगदान 16 फ़ीसदी है और देश के निर्यात में गुजरात की हिस्सेदारी 22 फ़ीसदी है. गुजरात की कृषि विकास दर 10 फ़ीसदी की दर से आगे बढ़ रही है, जबकि देश की कृषि विकास दर महज़ तीन फ़ीसदी है. यह भी सच है कि गुजरात के गांवों में 24 घंटे बिजली रहती है. मोदी के शासनकाल में गुजरात ने औसतन 10.5 फ़ीसदी का आर्थिक विकास दर को बरक़रार रखा है. आंकड़ों से तो यही साबित होता है कि मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने बुलंदियों को छुआ है. लेकिन गुजरात की व्यावसायिक वैभव की गाथा कोई नई नहीं है. यह इतिहासकाल में सिल्क और स्पाइस रूट के केंद्र में रहा. अंग्रेजों के ज़माने में सूरत भारत का सबसे अहम बंदरगाह रहा और ब्रिटिश काल के दौरान से ही गुजरात में सरकारी तंत्र देश के बाक़ी राज्यों से बेहतर रहा है. इस दौरान बड़ौदा के रजवाड़े का भी गुजरात को आगे बढ़ाने में अहम रोल रहा. राज्य में केमिकल और दवाइयों के उद्योग की शुरुआत की. गुजरात की गिनती कभी भी पिछड़े राज्यों में नहीं हुई. शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य व अन्य क्षेत्रों में 2001 से पहले से गुजरात देश के अव्वल राज्यों में रहा. यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी को विरासत में एक प्रगतिशील और धनी राज्य मिला, जिसे वो आगे बढ़ाने में कामयाब रहे. मोदी के विकास का मॉडल अदम्य उदारीकरण का नमूना रहा है. उन्होंने सरकारी संस्थानों को मज़बूत करके विकास करने की जगह निजीकरण के ज़रिए विकास का रास्ता चुना है. नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल के दो सिद्धांत हैं. पहला यह कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल व्यापार माहौल बनाना और दूसरा यह कि निवेश को बनाए रखने के लिए ईमानदार, पारदर्शी और प्रभावी शासन का माहौल बनाना. कहने का मतलब यह कि राज्य में निजी पूंजी निवेश का रास्ता साफ करना. मोदी के विकास का मॉडल सरकार और पूंजीवाद के सांठगांठ का आद्वितीय उदाहरण है, इसलिए यह मॉडल कॉरपोरेट जगत को बहुत भाता है. इस मॉडल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि विकास के इस सफर में जनता की हिस्सेदारी नहीं है. यह वही रास्ता है, जिसे मनमोहन सिंह ने 1991 में वित्तमंत्री रहते शुरू की थी. अब सवाल यह है कि क्या विकास का यह मॉडल पूरे देश में लागू किया जा सकता है?

भारत का हर इलाक़ा गुजरात नहीं है. आधा से ज्यादा इलाक़ा पिछड़ेपन की चपेट में हैं. वह कृषि पर आधारित हैं. सरकारी तंत्र लुंजपुंज है. शिक्षा नहीं है. उद्योग के काम आने वाला प्रशिक्षित मानव संसाधन नहीं है. आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं. इसके अलावा कई सामाजिक और राजनीतिक दुविधाएं हैं, जिसकी वजह से ऐसे इलाक़ों में पूंजी निवेश असंभव है. जब निवेश ही नहीं होगा तो इन इलाक़ों में गुजरात मॉडल सफल नहीं हो सकता है. हैरानी इस बात की है कि नरेंद्र मोदी का ध्यान अब तक इन इलाक़ों पर न तो गया है और न ही ऐसे इलाक़ों के लिए विकास का मॉडल क्या हो, इस पर कभी उन्होंने कोई राय दी है. कहने का मतलब यह है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, कश्मीर व उत्तरपूर्वी राज्यों जैसे पिछड़े इलाक़ों के विकास के लिए कोई मॉडल तैयार नहीं है.

जो लोग नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं, वे ऐसे लोग हैं जो नवउदारवाद की जनविरोधी नीतियों को सही मानते हैं. मीडिया में इसे समर्थन इसलिए मिलता है, क्योंकि ज्यादातर मीडिया हाउस उन्हीं औद्योगिक घरानों द्वारा संचालित हैं, जिन्हें नव-उदारवादी नीतियों का लाभ मिल रहा है. नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के दौरान जिस गुजरात मॉडल का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, वह भ्रामक सूचनाओं और झूठ के पिटारे के अलावा कुछ भी नहीं है. इस मॉडल का सबसे ख़तरनाक पहलू यह है कि यह मॉडल सरकार को अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वाह न करने को ही सही मानता है. यह मॉडल शिक्षा, रोज़गार, अवसर और सामाजिक-राजनीतिक विकास के लिए निजीकरण पर आश्रित है. मोदी जी की सरकार की ख़ासियत यह है कि उन्होंने पूरी सरकार का ही निजीकरण कर दिया है. सरकार की नीतियां और सरकार की प्राथमिकता मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध कराने से ज्यादा निजी निवेशकों की पैसे कमाने में मदद करना है. यही वजह है कि विकास का ये मॉडल गुजरात के निवासियों को फ़ायदा पहुंचाने में विफल रहा है. जो भी सड़कें, इंडस्ट्री या सेज की वजह से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, यह असलियत में निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया था.

गुजरात पर नज़र डालें तो यह कहा जा सकता है कि इस मॉडल के तहत चलने वाले प्रशासन में विकास के आंकड़े तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिलता. बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती है, साथ ही इसमें लोगों की कुल आमदनी में मज़दूरी का शेयर कम हो जाता है. इस मॉडल में छोटे किसान, भूमिहीन किसान और सीमांत किसानों की स्थिति बदतर हो जाती है. सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार जिस तरीक़े से भूमि के इस्तेमाल का क़ानून बना देती है, उसके चलते ज़मीन आम किसानों की पहुंच के बाहर होती चली जाती है. गुजरात मॉडल लोकनीति और सरकार द्वारा लोककल्याण कार्यक्रमों में पैसे ख़र्च करने वाला मॉडल नहीं है. इतना ही नहीं, यह मॉडल सामाजिक ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए भी निजी क्षेत्र पर आश्रित होता है. यह एक ऐसा मॉडल है जो समावेशी नहीं है, बल्कि भेदभाव में आकंठ डूबा हुआ है. इसकी वजह से राज्य के अंदर ही अलग-अलग क्षेत्रों में विभेद पैदा हो गया है. जिसका ख़ामियाजा पर्यावरण के साथ-साथ गांव में रहने वाले ग़रीब को झेलना पड़ता है.

निजीकरण व पूंजीनिवेश आधारित विकास मॉडल का सबसे ज्यादा नुकसान सामाजिक विकास पर पड़ता है. अशिक्षा भारत की सबसे बड़ी समस्या है. दुनिया की साक्षरता दर 84 प्रतिशत है, जबकि भारत की साक्षरता दर मात्र 74.04 प्रतिशत पर ही अटकी है. भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा निरक्षर लोग रहते हैं. 2001 से 2011 के बीच राष्ट्रीय साक्षरता दर 9.2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है, लेकिन गुजरात में दशक के हिसाब से साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से नीचे, मात्र 8.89 प्रतिशत है. यही हाल उच्च शिक्षा है. गुजरात में व्यावसायिक और उच्च शिक्षा को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है. प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में इसी उम्र वय के बच्चों पर ग़ौर करें तो महिलाओं, पिछड़े, दलितों, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की पहुंच गुजरात में राष्ट्रीय स्तर से कम रही. कई राज्यों की तुलना में यह पीछे है. जब गुजरात में शिक्षा पर सरकारी ख़र्च में राष्ट्रीय अनुपात की तुलना में भारी कटौती की गई, उस दौरान शिक्षा के लिए सरकारी और स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों पर निर्भरता या तो बढ़ी या उतनी ही बनी रही. ऐसा ख़ासकर ग्रामीण इलाक़ों में हुआ. कहने का मतलब यह है निजी क्षेत्र के महंगे प्राइवेट स्कूल लोगों की शिक्षा संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकने में कामयाब नहीं हैं. संविधान के नज़रिए से सरकार का यह मूल कर्त्तव्य है कि वह लोगों को शिक्षित करे, लेकिन इस नवउदारवादी अर्थव्यवस्था में यह उसकी प्राथमिकता में नहीं है. वजह साफ़ है कि शिक्षा में निवेश का उद्देश्य लोगों को शिक्षित करने के बजाए मुनाफ़ा कमाना होता है. चाहे वो मोदी हों या फिर मनमोहन सिंह, समझने वाली बात यही है कि ऐसी आर्थिक नीतियां जो कि सिर्फ़ निजी फ़ायदे के लिए हैं, वह न सिर्फ़ जनविरोधी हैं, बल्कि संविधान विरोधी भी हैं.

गुजरात के विकास मॉडल का सबसे ख़तरनाक पहलू यह है कि गुजरात में निवेशक सिर्फ़ निवेश ही नहीं करते, बल्कि विकास की दिशा भी तय करते हैं. जिसकी वजह से विकास का लाभ आम लोगों को नहीं मिलता. विकास की दिशा, दशा अब सरकार तय नहीं करती. ये निवेशक, वित्तीय संस्थाएं और कॉरपोरेट तय करते हैं, जिनका उद्देश्य जनसेवा नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कमाना होता है. गुजरात मॉडल का सीधा मतलब ये है कि येन केन प्रकारेण राज्य में पूंजी का निवेश हो. बंदरगाह, सड़क, रेल और बिजली जैसे विभाग जो अब तक सरकार के पास थे, मोदी जी ने इसे भी प्राइवेट कंपनियों और कॉरपोरेट के हवाले कर दिया. दरअसल, गुजरात मॉडल का मतलब है कि सरकार सभी निर्णय संबंधी शक्तियां, कार्यकारी और आर्थिक नियंत्रण को तिलांजलि दे दे. यह कहा जा सकता है कि गुजरात मॉडल पूरी तरह से कॉरपोरेट के विकास का मॉडल है. यह मॉडल निजी निवेशकों का, निजी निवेशकों के द्वारा, निजी निवेशकों के लिए तैयार किया हुआ मॉडल है.

इस मॉडल का असर देश की ग़रीब जनता पर साफ़ नज़र आता है. यह मॉडल अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला मॉडल है. गुजरात में मोदी के शासनकाल में प्रति व्यक्ति ख़र्च 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ा, जबकि पिछले पांच वर्षों में राज्य की अनुसूचित जनजातियों के लिए यही आंकड़ा 0.14 प्रतिशत था. प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में सेड्यूल ट्राइब और अन्य आबादी के बीच का फ़ासला बहुत ज्यादा है. स्वास्थ्य मानकों के आधार पर जैसे शिशु मृत्यु दर, महिला और पुरुष की जीवन प्रत्याशा, टीकाकरण, प्रसवपूर्व देखभाल के मामलें में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में गुजरात का प्रदर्शन सामान्य रहा है. पिछले एक दशक के दौरान ज्यादातर मामलों में गुजरात अन्य विकसित राज्यों, मसलन तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र से तुलनात्मक रूप से पीछे ही रहा है, बावजूद इसके कि वहां की प्रति व्यक्ति आय में इज़ाफ़ा हो रहा है. एक और बात जो चिंताजनक है कि पांच वर्ष के भीतर की शिशु मृत्यु दर के मामले में राष्ट्रीय औसत से भी पीछे है. ऐसी ही स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और महिला मृत्यु दर के संदर्भ में भी है. निश्चित रूप से यह आंकड़े ग़रीब तबके, ख़ासकर अनुसूचित जनजातियों व अन्य के बीच में एक विभाजक रेखा खींचते हैं.

यह बहस का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक आवश्यकता है कि राज्य देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, साथ ही समाज के सभी वर्गों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार तैयार करे. संविधान के मुताबिक़, भारत सरकार के लिए अपरिहार्य विषय है कि वह सर्वांगीण विकास की नीतियां बनाए और अमीर-ग़रीब के बीच के फ़ासले को कम करे. पिछले 23 वर्षों में नवउदारवादी नीतियों ने इसके बिल्कुल विपरीत काम किया है. देश की जनता को बाज़ार की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ऐसी ही नीतियों की वजह से देश के 270 ज़िले पूरी तरह से राज्य की मशीनरी के नियंत्रण से बाहर चले गए हैं. समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अर्थव्यवस्था को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां नव-उदारवाद की नीतियों को एक मात्र उपाय समझा जाने लगा है. दरअसल, नवउदारवाद भारत की आर्थिक व्यवस्था का उपाय नहीं, खतरा है, जो अपने साथ भ्रष्टाचार, संसाधनों की संगठित लूट के साथ-साथ देश की एकता और अखंडता पर संकट लेकर आते हैं. नरेंद्र मोदी का तथाकथित सफल विकास मॉडल दरअसल मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति का सफल क्रियान्वयन है. अफ़सोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी इस ख़तरे से निपटने के बजाय इसे उपाय मानते हैं. ■

manish@chauthiduniya.com

> कश्मीर का भारत में अधिग्रहण ही इस आधार पर हुआ था कि धारा 370 के प्रावधान के तहत जब तक कश्मीर का जनता चाहेगी, वहां पर धारा 370 लागू रहेगी. अगर कश्मीर की जनता चाहेगी कि वह नहीं चाहते कि राज्य में धारा 370 लागू रहे तो कोई ज़बरदस्ती इसे लागू नहीं कर सकता. यह बात सही है कि संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हासिल किया जा सकता है, लेकिन तभी जब इसकी पहल और इसका अनुमोदन जम्मू-कश्मीर की जनता करेगी.

देश में गृहयुद्ध लेकर आएंगे मोदी

नीरज सिंह

इस समय देश में यह बहस का मुद्दा है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के अंदर कैसे हालात बनेंगे. कुछ दिनों पहले आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आंतरिक सुरक्षा के मसले पर एक श्वेत पत्र लाना ज़रूरी है. केवल श्वेत पत्र शब्द से यह समझना पाना थोड़ा मुश्किल है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में मोदी की क्या सोच है. लेकिन नरेंद्र मोदी की जो छवि है, उसे अगर आधार बनाकर देखा जाए तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर उनके विचारों पर सवालिया निशान खड़े करना बेहद आसान है. ज़ाहिर है, इसके पीछे की वजह 2002 के गुजरात दंगों और नरेंद्र मोदी को एक साथ जोड़कर देखना है. मानव विज्ञान की अवधारणाओं पर ध्यान दें, तो व्यक्ति के अतीत से हमेशा ही उसके भविष्य को पारिभाषित नहीं किया जा सकता. इसलिए मोदी की आंतरिक सुरक्षा पर क्या नीति है या क्या होगी, इसे समझने के लिए मोदी के अतीत और मोदी के वर्तमान को अलग-अलग करके समझने की ज़रूरत है.

आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले सांप्रदायिक दंगों की ओर ध्यान जाता है. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक पटल पर बड़ी चर्चा में 2002 के गुजरात दंगों के बाद आए. एक बड़ा सांप्रदायिक दंगा. और तब यह माना गया कि उनकी शिक्षा-दीक्षा उस पाठशाला में हुई है, जहां के पाठ्यक्रम में हिंदुत्व मुख्य विषय है और और गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला. बहुत पीछे न जाकर 80 के दशक से ही देखें, तो गुजरात में हिंदुत्व को मज़बूत बनाने के लिए 1983 में 'गंगाजल एकात्मता यात्रा' और 1990 में लालकृष्ण आडवानी की 'अयोध्या रथयात्रा' सोमनाथ से शुरू हुई. यही वह दौर था, जब मुसलमानों को लेकर समान नागरिक संहिता, कुरान पर रोक लगाने की बात, उनके द्वारा तिरंगा फ़हराने की चर्चा, वंदे मातरम गाने, हज के लिए दी जाने वाली सब्सिडी, पाकिस्तान की वफ़ादारी, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी, मदरसों की पढ़ाई जैसे तमाम मुद्दे बतौर शिगूफ़े फ़ैल रहे थे. लेकिन तब तक यह आरोप नहीं लगा था कि राज्य की व्यवस्था इसमें कहीं शामिल है. तब यह ज़ाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि यह हिंदुत्व को स्थापित करने का उपक्रम है और तब यह सब कुछ एक संगठन, एक पार्टी और एक विचार से जोड़कर देखा जा रहा था. गुजरात दंगों में पहली बार यह आरोप लगा कि यह सरकार द्वारा प्रायोजित है. हालांकि, उन दंगों के बाद अधिकांश जांच कमेटियों और फिर हाल ही में एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी, लेकिन देश के मानस से पूछा जाए तो अभी भी एक बड़ा वर्ग गुजरात दंगों के कलंक का ताज मोदी के माथे ही सजाता है. इसकी बड़ी वजह है कि मोदी अपने विचारों और अपने उपक्रमों से कहीं न कहीं अपनी इस भावना को ज़ाहिर भी कर देते हैं. एक उदाहरण के तौर पर समझें तो आज भी राज्य के अहमदाबाद व सूरत के कुछ हिस्सों में आपको ऐसे साइन बोर्ड टंगे मिल सकते हैं, जिनपर लिखा होगा कि हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है.

गुजरात दंगों को बीते 11 वर्ष हो चुके हैं. इन दंगों के बाद गुजरात में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ. मोदी ने कई बार ख़ुद भी सार्वजनिक मंचों से हिंदू-मुस्लिम सदभाव जताने की कोशिश की. लेकिन सदभाव की इन कोशिशों को आधार मानकर यह नहीं कहा जा सकता कि मोदी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को किनारे रख दिया है. जब मोदी राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के छत्रप के तौर पर उभर रहे थे और देश में यह माहौल बनने लगा था कि मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लगभग तय हैं, तब चौथी दुनिया ने एक स्टोरी की थी. दंगे होने वाले हैं. जिसमें हमने लिखा था कि नरेंद्र मोदी चाहे विकास की बात करें या फिर भविष्य के भारत का कोई हसीन सपना दिखाएं, लेकिन उनके सामने आते ही चुनाव का ध्रुवीकरण होना निश्चित है. यह बात भाजपा और संघ परिवार के रणनीतिकारों को अच्छी तरह मालूम है. इसके बावजूद, भाजपा ने अपने सबसे बड़े नेता के रूप में मोदी को सामने रखकर यह साफ़ कर दिया कि वह 2014 में हिंदू-मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण चाहती है. दरअसल, भाजपा को यही लगता है कि जितना ज़्यादा ध्रुवीकरण होगा, उसे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा. इसलिए इस रणनीति के तहत ही मोदी के हाथों चुनाव की कमान सौंप दी गई है. ऐसी रणनीति पर चुनाव लड़ने का मतलब यही है कि देश में भाईचारा ख़त्म हो जाए, दंगे हो जाएं या फिर लोगों की जानें चली जाएं, पर चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण करना ही एकमात्र रास्ता है. मोदी अब तक विकास की बातें करते आए हैं और इस रणनीति की पुष्टि उन्होंने पठानकोट में कर ही दी. मोदी ने चुनावी अभियान की शुरुआत पठानकोट से की. यहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने एवं धारा 370 ख़त्म करने की बात करके यह स्पष्ट कर दिया कि सदभावना मिशन सिर्फ़ मुसलमानों को बहलाने के लिए है, जबकि उनका असली एजेंडा कुछ और ही है.

चौथी दुनिया का यह पूर्वानुमान सौ फ़ीसदी सही साबित हुआ. अकेले उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो पिछले ढेड़ साल के भीतर राज्य में कुछ छिटपुट 102 दंगे हुए और जिनमें अधिकांश सांप्रदायिक दंगे थे. इन दंगों में राज्य सरकार की क्या भूमिका थी, यहां चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा ज़रूरी है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई किरदार रहा या नहीं. और इसकी पुष्टि गाहे-ब-गाहे पार्टी ख़ुद ही करती रही, जिसका हालिया उदाहरण मुज़फ़्फ़रनगर दंगा रहा. जब नरेंद्र मोदी ने मुज़फ़्फ़रनगर दंगों के आरोपी भाजपा विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा और पार्टी नेता संजीव बालियान को आगरा रैली में 'विजय शंखनाद रैली' में सम्मानित किया. स्पष्ट है कि ब्रज क्षेत्र के आठों जिलों मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फीरोज़ाबाद, मैनपुरी में जाट और क्षत्रिय मतदाता निर्णायक भूमिका में है. ऐसे में संगीत सोम, सुरेश राणा और संजीव बालियान को सम्मान देकर भाजपा इन मतदाताओं के दिल तक पहुंचने की कोशिश में जुटी. लक्ष्य स्पष्ट है ध्रुवीकरण. और उसका सबसे सटीक हथियार है हिंदुत्व को बढ़ावा. हालांकि, मोदी अपनी इस छवि से निकलने की पुरज़ोर कोशिश में हैं. इसीलिए वह चाहते हैं कि उनकी रैलियों में मुस्लिम पुरुष टोपी में और महिलाएं बुर्के में आएं, ताकि लोगों में यह संदेश जाए कि मोदी सांप्रदायिक सदभावना के पक्षधर हैं. लेकिन मोदी ने जब गुजरात में सदभावना मुहिम चलाई थी तो अलग-अलग धर्मों के प्रतिनिधियों में किसी ने मोदी को पारंपरिक पगड़ी-साफा या शॉल पेश की. लेकिन एक मजार के ट्रस्टी जब अपनी जेब से एक गोल टोपी निकालकर मोदी को पहनाने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने ट्रस्टी को टोपी पहनाने से रोक दिया.

आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर दूसरा बड़ा मसला है नक्सलवाद. आंतरिक सुरक्षा को लेकर हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठकें हुई थी. इस बैठक में नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद की समस्या पर कहा था कि यह तिरुपति से लेकर पशुपति तक फैलता जा रहा है और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को दोतरफ़ा रणनीति बनानी होगी. लेकिन गुजरात में जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों को लेकर नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, वह दोतरफ़ा नहीं, पूरी तरह से एकतरफ़ा हैं. यहां अनुसचित जनजातियां- सात प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियां- 15 प्रतिशत, लेकिन राजनीतिक सामाजिक सत्ता में 'पटेल-ब्राहमण-महाजनों' की सत्ता के सामने यह वर्ग कहीं दिखता नहीं है. न ही उनके उत्थान के लिए कोई विशेष प्रयास दिखता है. देशभर में जनजातियों की जागरूकता की जो कोशिशें हुईं, वह गुजरात तक कभी नहीं पहुंची. दक्षिण गुजरात के उकाई बांध से विस्थापितों को कुछ हासिल न हो सका. यहां के आदिवासी सूरत पहुंचे तो यहां की झोपड़पट्टी वाले कहलाए. पहले की सरकारें भूमिहीनों को प्राकृतिक संसाधन देती थीं, घर और सहकारी मंडलों के लिए ज़मीन देती थीं, लेकिन मोदी के राज में इन योजनाओं पर ताला लग गया है. मोदी के राज में सब बंद है. झारखंड व अन्य पूर्वी राज्यों की तरह यहां अभी तक आदिवासियों को अपनी पहचान का राजकीय मौक़ा नहीं मिला. राज्य के अनेक हिस्सों में सिर पर मैला ढोने का रिवाज़ आजतक बरक़रार है. यह वही मसले हैं जिनको लेकर नक्सली लड़ रहे हैं और इन्हीं मांगों को अपने अधिकारों में शामिल कर रहे हैं. हाल के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में मोदी फैक्टर के न चलने की एक वजह यह भी बताई गई कि वहां बड़े पैमाने पर नक्सल प्रभावित इलाक़ों में नोटा का इस्तेमाल हुआ. पांचो राज्यों के हालिया विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग छत्तीसगढ़ में ही हुआ और दंतेवाड़ा और बस्तर जैसे नक्सली इलाक़ों में सबसे अधिक. इसकी बड़ी वजह यह भी है कि नक्सलवाद के ख़ात्मे को लेकर मोदी के अब तक जितने बयान आए हैं, उसमें उनका विजन स्पष्ट है.

छत्तीसगढ़ के झीरमघाटी में जब कांग्रेसी अमले पर बड़ा हमला हुआ था तो मोदी ने स्पष्ट कहा था कि नक्सलवाद जैसी अमानुषिक हिंसा की मानसिकता के ख़िलाफ़ शून्य सहनशीलता (जीरो टॉलरेंस) की नीति अपनाने का समय काफ़ी पहले ही हो चुका है. नक्सलवाद के ख़ात्मे पर क्या नीति अपनाई जाए, यह बहस का मुद्दा है. जीरो टॉलरेंस अगर रास्ता है तो सल्वा जुडूम जैसे ऑपरेशनों का क्या परिणाम निकला है, हमने देखा है. मानवाधिकार इसका पक्ष भी नहीं ले सकता. बातचीत के रास्ते का परिणाम भी कभी सार्थक नहीं दिखा. लेकिन इतना तो तय है कि केवल और केवल जीरो टॉलरेंस देश को एक बड़े ख़तरे की ओर ले जा सकता है. और उससे भी बड़ा ख़तरा है कि मोदी सेना के माध्यम से इसका सफ़ाया करना चाहते हैं, बड़े ऑपरेशनों में इस बात की संभावना ज्यादा रहती है कि उसमें आम नागरिक भी मारे जाएंगे. निर्दोष मारे जाएंगे. इससे स्थिति और बिगड़ सकती है.

नक्सलवाद की ही तर्ज पर देश के सामने एक और बड़ा आंतरिक ख़तरा है अलगाववाद. अलगाववाद को लेकर मोदी की सोच वही है जो जनसंघ की है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज से 50 वर्ष पहले ही अनुच्छेद 370 को संविधान से समाप्त कर कश्मीर घाटी में जनसंख्या का संतुलन स्थापित कर अलगाववादियों को जवाब देते हुए हिंदुस्तानपरस्त ताकतों को सशक्त करने का उपाय सुझाया था. मोदी ने हाल ही में उसी मसले को दोबारा उठाया. मोदी ने कश्मीर में अपनी एक रैली में कहा कि धारा 370 पर सही चर्चा नहीं हो रही है. देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है. धारा 370 की ज़रूरत है या नहीं, इस पर संसद में बहस होनी चाहिए. वास्तव में मोदी सेपरेट नहीं सुपर स्टेट की धारणा में विश्वास करते हैं. लेकिन यह मसला उतना आसान है नहीं, जितना मोदी देख रहे हैं. स्वायत्त कौन नहीं रहना चाहता. राज्य चाहते हैं कि वे और अधिक स्वायत्त बनें, केंद्र का दख़ल कम हो. नगरपालिकाएं और मज़बूती चाहती हैं, पंचायतें और अधिक ताक़तवर बनना चाहती हैं. यह मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है. इसलिए इस मसले को इतनी लापरवाही से देखना कहीं से भी जायज़ नहीं है. दूसरे कश्मीर का भारत में अधिग्रहण ही इस आधार पर हुआ था कि धारा 370 के प्रावधान के तहत जब तक कश्मीर का जनता चाहेगी, वहां पर धारा 370 लागू रहेगी. अगर कश्मीर की जनता चाहेगी कि वह नहीं चाहते कि राज्य में धारा 370 लागू रहे तो कोई ज़बरदस्ती इसे लागू नहीं कर सकता. यह बात सही है कि संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हासिल किया जा सकता है, लेकिन तभी जब इसकी पहल और इसका अनुमोदन जम्मू-कश्मीर की जनता करेगी. इसलिए यह समझना भी जरूरी है कि कश्मीर की जनता क्या चाहती है. जाहिर है कि शायद ही कश्मीर की जनता चाहे कि उसकी स्वायत्ता छीनी जाए. ऐसे में मोदी की यह सोच देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है.

जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे तो एक बार सीमा पर जवानों को संबोधित करने गए. संबोधन के दौरान पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की आवाज़ सुनकर तत्कालीन रक्षामंत्री ने पूछा कि यह क्या है, तो जवानों ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ़ से गोलीबारी हो रही है. मुलायम सिंह ने जवाब दिया कि जब पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है तो आप लोग मेरा भाषण क्यों सुन रहे हैं? जाइए जवाब दीजिए. देश में एक पक्ष ने इसे एक रक्षा मंत्री के दिलेर बयान के तौर पर देखा, लेकिन यह बयान तार्किक भी है, इस पर संदेह है. यही नीति मोदी भी चल रहे हैं. उन सभी बातों पर जोशीले बयान दे रहे हैं जो देश में एक समस्या के तौर पर जानी जा रही है, लेकिन मोदी यह भूल रहे है कि उनके यह बयान और उनकी सोच देश को गृहयुद्ध की ओर ले जा सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> ज़्यादातर मीडिया घरानों के हित व्यावसायिक हैं. जिस मीडिया घराने पर जिन कंपनियों का नियंत्रण है, वे उनके व्यावसायिक हित के लिए काम करते हैं. अब इन मीडिया घरानों का सीधा फ़ायदा नरेंद्र मोदी का समर्थन करने में है, क्योंकि समूचे कॉरपोरेट जगत का मोदी से व्यावसायिक गठबंधन है और वे मोदी का ज़बरदस्त समर्थन कर रहे हैं.

कॉरपोरेट के कंधे पर सवार मोदी लहर

नवंबर में अंग्रेज़ी पत्रिका ओपेन ने टीवी चैनलों पर चलने वाली कुछ ख़बरों का विश्लेषण करते हुए लेख छापा कि कैसे नेटवर्क-18 के सभी चैनलों में काम करने वाले पत्रकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नर्म रुख़ अपनाएं. नेटवर्क-18 पर उद्योगपति मुकेश अंबानी का क़ब्ज़ा है. कई पत्रकारों ने कहा कि उन्हें स्पष्ट निर्देश है कि मोदी के ख़िलाफ़ कुछ न छापें. उनका कहना है कि नेटवर्क-18 मीडिया समूह की पूरी रीति-नीति ऊपर से तय होती है. इस समूह के सभी चैनलों में काम करने वाले सभी पत्रकारों को पता है कि मोदी विरोधी ख़बरों को प्रसारित करने के बजाय ठिकाने लगाना है. इस समूह में काम कर रहे बड़े-बड़े पत्रकार मोदी पर सिर्फ़ मीठा बोलते हैं. अन्य चैनल जैसे-आजतक, टाइम्स नाउ आदि भी किस तरह से मोदी के समर्थन में ही ख़बरें चलाते हैं, पत्रिका इसकी भी पड़ताल करती है. जिन चैनलों पर कॉरपोरेट घरानों का क़ब्ज़ा है, उन्हें भी स्पष्ट निर्देश है कि मोदी के प्रति नरमी बरतें और अधिक से अधिक कवरेज दें, उनकी रैली को बिना काटे हुए सीधे प्रसारित करें. मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, वह किसी एक व्यक्ति या पार्टी के लिए काम करने लगे, तो इसके क्या निहितार्थ हैं?

कृष्णकांत

पिछले कुछ महीनों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नरेंद्र मोदी को अभूतपूर्व जगहें मिली हैं. बहुत सारे दर्शक और पाठकों के मन में यह सवाल उठता होगा कि भारतीय राजनीति में इतने राजनीतिक दलों की मौजूदगी और सक्रिय हस्तक्षेप होने के बावजूद मोदी को ही क्यों इस तरह से दिखाया जा रहा है. आख़िर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन-सा कारनामा किया है कि मीडिया, ख़ासकर टीवी चैनलों पर मोदी ही मोदी नज़र आते हैं? क्या नरेंद्र मोदी के प्रशासन में गुजरात ने समृद्ध और गरिमापूर्ण जीवन के लिए वह सबकुछ प्राप्त कर लिया है, जो एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य होना चाहिए? क्या गुजरात देश के बाक़ी सारे राज्यों से आगे निकल चुका है? क्या सड़क, बिजली और कुछ कॉरपोरेट कंपनियों की चमक-दमक ही विकास है? इन सब सवालों के जवाब नकारात्मक ही होंगे. तो फिर नरेंद्र मोदी का ऐसा गुणगान क्यों किया जा रहा है?

इन सवालों का जवाब बहुत दबे छुपे स्वरूप में मीडिया में उठने लगा है. ओपेन पत्रिका के नवंबर अंक में संदीप भूषण ने एक लेख लिखकर इसका जवाब दिया है. सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं. मोदी पर कॉरपोरेट मीडिया क्यों मेहरबान है, इसके लिए आपको मीडिया की आर्थिकी की पड़ताल करनी चाहिए. ज्यादातर जो बड़े-बड़े मीडिया समूह हैं, उनमें उद्योगपतियों का पैसा लगा है. देश के 27 टीवी समाचार और मनोरंजन चैनलों पर अंबानी समूह का नियंत्रण है. इनमें नेटवर्क-18 समूह के सीएनएन-आइबीएन, आइबीएन लाइव, सीएनबीसी, आइएन-7, आइबीएन लोकमत और और लगभग हर भाषा में प्रसारित होने वाला ईटीवी समूह शामिल है. इसी तरह एक उदाहरण प्रिंट मीडिया का देखते हैं. डीबी कॉर्प समूह का हिंदी अख़बार दैनिक भास्कर है जो 13 राज्यों से चार भाषाओं में प्रकाशित होता है. इसकी पाठक संख्या 75 लाख है. यह समूह 69 अन्य कंपनियां चलाता है, जो खनन, उर्जा, रीयल एस्टेट और कपड़ा उद्योग आदि से जुडी हैं. ये दोनों मात्र दो उदाहरण हैं. यही हालत बाक़ी मीडिया घरानों की भी है. ज्यादातर मीडिया घरानों के हित व्यावसायिक हैं. जिस मीडिया घराने पर जिन कंपनियों का नियंत्रण है, वे उनके व्यावसायिक हित के लिए काम करते हैं. अब इन मीडिया घरानों का सीधा फ़ायदा नरेंद्र मोदी का समर्थन करने में है, क्योंकि समूचे कॉरपोरेट जगत का मोदी से व्यावसायिक गठबंधन है और वे मोदी का ज़बरदस्त समर्थन कर रहे हैं.

ओपेन पत्रिका ने नेटवर्क-18 समूह में काम कर रहे कई पत्रकारों के हवाले से लिखा है कि उन्हें स्पष्ट निर्देश है कि मोदी से जुड़ी नकारात्मक ख़बरें न दिखाई जाएं और उनकी रैलियों का बिना व्यवधान लाइव प्रसारण किया जाए. यह हाल अन्य मीडिया समूहों का भी है. यही कारण है कि मीडिया में मोदी ही मोदी छाए हुए हैं और बाक़ी राजनीतिक दलों की अपेक्षा मोदी को बढ़त दिलाई जा रही है. हाल ही में कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि मीडिया मोदी के पक्ष में खड़ा है और राहुल गांधी और कांग्रेस से जुड़ी ख़बरें नहीं दिखाता है. कांग्रेस का यह आरोप यूं ही नहीं है.

पिछले साल द न्यू यॉर्कर के एक पत्रकार को बेनेट एंड कोलमैन कंपनी के मालिक विनीत जैन ने कहा था कि हमारा अख़बार का व्यवसाय नहीं है. हमारा विज्ञापन का व्यवसाय है. ज़ाहिर है कि कॉरपोरेट समूह अपने हर उद्यमों में फ़ायदा देखते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स अख़बार और टाइम्स नाउ चैनल इसी समूह का है. यह समूह वही बेचता है, जो बिकता है. अभी तक इनकी टीआरपी का साधन अन्ना हजारे थे. अब नरेंद्र मोदी हैं.

कुछ महीने पहले नेटवर्क-18 समूह से बिना कारण बताए 325 पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया गया. इसकी वजह यही है कि मीडिया में कॉरपोरेट विरोधी आवाज़ों को दबाया जाए. जो लोग मीडिया की एजेंडा सेटिंग में समूह के वफ़ादार साबित नहीं हो सकते, उनसे मुक्ति पा ली जाए. मीडिया अब विचार अभिव्यक्ति का माध्यम न होकर शायद कॉरपोरेट हितों का पोषक है. इन समूहों को स्वतंत्र विचारों के पत्रकार नहीं, अपने व्यवसाय और पक्षधरता को मूर्तरूप देने के लिए व्यावसायिक सहयोगी चाहिए. मीडिया के एक धड़े में यह चर्चा है कि उनके यहां काम करने वाले जो भी वाम विचार के लोग हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए. इससे मीडिया और मोदी का गठबंधन सुचारु ढंग से चल सकेगा.

इधर कुछ महीनों में में दुनिया के कई बड़े मीडिया समूहों की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ख़ूब तारीफ़ की गई. वॉल स्ट्रीट जर्नल ने-'धीमे होते भारत का उभरता सितारा' शीर्षक से लेख छापा. विश्वप्रसिद्ध टाइम मैगज़ीन ने भी नरेंद्र मोदी पर कवर स्टोरी छापी-'मोदी मतलब व्यापार'. मोदी के समर्थक इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी और गुजरात की स्वीकार्यता कहते हैं. मोदी के आलोचक कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की मीडिया मशीनरी का कमाल है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी पत्रिकाएं गुजरात की कथित आर्थिक प्रगति और मोदी का गुणगान कर रही हैं. इस का कारण वे कंपनियां हैं जो मोदी के लिए काम करती हैं. नरेंद्र मोदी के लिए क़रीब दो दर्जन कंपनियां काम कर रही हैं, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी और गुजरात मॉडल का प्रचार-प्रसार देखने का काम करती हैं.

वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता के निर्देशन में नीति सेंटर नाम से एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है. इस पर मोदी और भाजपा से जुड़ी खबरें, तस्वीरें, वीडियो, रेडियो कार्यक्रम और मोदी की सभी रैलियों की विस्तृत कवरेज होती हैं. कंचन गुप्ता के अलावा तवलीन सिंह, स्पन्दास गुप्ता, संध्या जैन, जय भट्टाचार्जी समेत दर्जनों पत्रकार और भाजपा के कई बड़े नेता इस पोर्टल के लिए प्रमोशनल लेख लिखते हैं. इस पोर्टल पर कांग्रेस व अन्य दलों से जुड़ी वही ख़बर दिखती है, जिससे उन्हें नुकसान होता हो या एक पार्टी के रूप में उसकी छवि धूमिल होती हो. पोर्टल की घोषणा है कि उसका उद्देश्य 'परिवर्तन' के लिए 'सोच परिवर्तित' करना है.

इसी तरह इंडिया 272+ नाम से एक और वेबसाइट है, जो नरेंद्र मोदी के ऑनलाइन प्रचार का काम कर रही है. इस वेबसाइट का उद्देश्य है, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के मिशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 272 सीट का आंकड़ा जुटाना. यह वेबसाइट भारी संख्या में अभियान चलाकर स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है जो मोदी के लिए ऑनलाइन और ग्राउंड पर प्रचार करेंगे. इस पर मोदी के भाषण, उनके पार्टी नेताओं से जुड़ी ख़बरें और मोदी का गुणगान करने वाली रिपोर्ट लगाई जाती हैं. इस तरह से और भी कई मीडिया समूह हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मोदी के प्रचार अभियान में लगे हैं. ऐसे सभी पोर्टल और वेबसाइट का उद्देश्य है भाजपा कार्यकर्ताओं को मोदी के प्रचार के लिए सामग्री उपलब्ध कराना, ताकि वे सोशल मीडिया समेत अन्य जगहों पर उनका प्रचार-प्रसार कर सकें. इनके माध्यम से मोदी और गुजरात सरकार के बारे में उजले और कई बार भ्रामक आंकड़े पेश कर सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों का ब्रेनवॉश किया जाता है. इस पूरे अभियान के पीछे गोएबल्स का वह फार्मूला काम कर रहा है कि एक झूठ को सौ बार दोहराया जाए तो वह सच में तब्दील हो जाता है.

नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार-प्रसार के लिए दिल्ली की एक जनसंपर्क कंपनी म्युचुअल पीआर को लगाया है जो गुजरात की एक दूसरी जनसंपर्क कंपनी आकृति मीडिया के साथ मिलकर काम करती है. अलग-अलग स्तर पर कई टीमें बनी हुई हैं जो देश-विदेश में मोदी की छवि चमकाने के लिए काम करती हैं. म्युचुअल पीआर में मैनेजिंग पार्टनर हैं कविता दत्ता, जिनकी 18 लोगों की टीम है. इस टीम का काम है कि भारतीय मीडिया में गुजरात सरकार और मोदी के बारे सकारात्मक कवरेज हो. कविता कहती हैं कि उनका प्रयास होता है कि वे गुजरात सरकार की योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां लोगों तक पहुंचाएं.

मोदी भारतीय मीडिया में गुजरात दंगों के बाद से ही मौजूद रहे हैं, लेकिन हाल में उनका अचानक छा जाने की घटना का रहस्य यही कंपनियां हैं जो लगातार मोदी को प्रमोट करने के लिए काम कर रही हैं. मोदी के चारों ओर एक ऐसी टीम है जो सूचना प्रौद्योगिकी को समझती है. उनकी टीम के सदस्य उन्हीं के अंदाज़ में आक्रामक शैली में प्रचार करते हैं.

इन कंपनियों और मोदी की प्रचार शैली का ही कमाल है कि हाल में हुए हर चुनाव और हर सर्वे रिपोर्ट में मोदी का असर ढूंढा जा रहा है. यह भी मीडिया का फैलाया गया मायाजाल है. क्योंकि मोदी के प्रचार से हालिया किसी चुनाव में कोई ख़ास फ़र्क़ पड़ा हो, ऐसा देखने में नहीं आया. हाल में कई बड़े मीडिया हाउसेस के सर्वे के मुताबिक़, आगामी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को मिलने वाली सीटों में सिर्फ़ 15 से 20 सीट का फ़ासला है. 80 के दशक से दोनों पार्टियों के वोट प्रतिशत में मात्र दो-ढाई फ़ीसद का अंतर रहता है. इस बार भी सारे चुनावी अनुमान यही कह रहे हैं. तमाम सर्वे बता रहे हैं कि दोनों बड़ी पार्टियां यानी भाजपा और कांग्रेस 150 सीट के आसपास रहेंगी. राजग और संप्रग में से कोई गठबंधन दो-सवा दो सौ सीटों के पार जाता नहीं दिख रहा है. अब जब कोई पार्टी 543 सीटों में से 150 के आसपास ही पाएगी तो किस लहर का शोर मचाया जा रहा है. इससे साफ़ है कि नरेंद्र मोदी का मीडिया मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि भाजपा को 150 सीट मिलने के अनुमान के बाद भी मोदी नाम की आंधी बताई जा रही है. अगर यह मानें कि सर्वे बहुत बार ग़लत साबित होते हैं तो हालिया चुनावों ने जो संकेत दिया है, वह भी मोदी लहर की हवा निकालता दिख रहा है. चार राज्यों के चुनाव में मोदी का असर कहीं भी नहीं देखा गया. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी. दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस-भाजपा दोनों को धूल चटा दी. राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की ज़बरदस्त जीत की वजह वहां के भाजपा नेता और विपक्ष की कमज़ोरियां हैं. लेकिन प्रोपेगैंडा के तहत मीडिया में मोदी लहर की चर्चा की जा रही है.

विभिन्न सर्वे पर ग़ौर करें तो देश का महज़ 25 प्रतिशत जनता मोदी और भाजपा को वोट देती दिखाई दे रही है. अब सवाल उठ रहा है कि वह कौन सी जनता है जहां मोदी की लहर चल रही है? ज़ाहिर है कि मोदी लहर का हल्ला मचाकर बहुसंख्यक जनता का वोट बटोरने का एजेंडा काम कर रहा है. पूर्वोत्तर में भाजपा का नामोनिशान नहीं है. चार दक्षिण-भारतीय राज्यों में भी भाजपा का खाता खुलने के आसार नहीं है. यूपी, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी क्षेत्रीय पार्टियों का ही वर्चस्व है और आगामी चुनाव में वे कड़ी टक्कर में होंगी. अब सवाल उठता है कि मोदी की लहर कहां है? ज़ाहिर है, हक़ीक़त से परे मोदी का शानदार मीडिया मैनेजमेंट उन्हें सारे देश में लोकप्रिय बता रहा है. मोदी किस तरह मीडिया को साधते हैं, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश की कमान मोदी के घनिष्ट सहयोगी अमित शाह को सौंपी, वे उत्तर प्रदेश में पहुंचते ही अख़बारों के दफ़्तर में भी पहुंचे. आज उत्तर प्रदेश के मीडिया में हवा बदली दिख रही है. यह मोदी के मीडिया मैनेजमेंड का ही कमाल है कि स्वतंत्रता दिवस पर मीडिया ने प्रधानमंत्री के भाषण से ज्यादा मोदी के भाषण को तवज्जो दी. दरअसल, मोदी की नीतियां कॉरपोरेट समर्थन हैं, जिसके कारण कॉरपोरेट मोदी का समर्थन कर रहा है. मोदी भी अपने को पूरी तरह कॉरपोरेट एजेंडे पर चल रहे हैं, जहां मीडिया के द्वारा निजी एजेंडे को पब्लिक एजेंडे में तब्दील करके पेश किया जाता है.

नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के बाद से मीडिया में चर्चा का विषय बने थे. तब से लगातार वे मीडिया में छाए रहे. मीडिया उन्हें गुजरात दंगों का दोषी ठहराता रहा. मोदी से सवाल करता रहा. लेकिन मोदी इस मामले पर लगभग चुप्पी साधे रहे. इस दौरान मोदी की जितनी चर्चा हुई थी, या कहें दंगों की वजह से जितनी कुख्याति मिली थी, उसे उन्होंने अपनी योग्यता में परिवर्तित करने का अभियान चलाया. कॉरपोरेट मीडिया और विज्ञापन कंपनियों की मदद से मोदी ने उस 12 साल की अपनी देशव्यापी आलोचना को अपने पक्ष में मोड़ लिया, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया में जितनी आलोचना हुई, उसे उन्होंने गुजरात बनाम मीडिया बनाया. अपनी आलोचना को मोदी ने गुजराती अस्मिता से जोड़कर जनता की सहानुभूति हासिल की और वहां एक के बाद एक चुनाव जीतकर सत्ता में बने रहे.

मोदी जिस गुजरात के विकास मॉडल का ढोल पीटते हैं, उसमें तमाम मानव विकास सूचकांक और दूसरे पैमाने पर गंभीर ख़ामियां हैं, लेकिन मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाता. मीडिया में सिर्फ़ मोदी से जुड़ी रैलियों और प्रचार अभियान को ही पेश किया जाता है, उनकी आलोचना नहीं. मीडिया मोदी की हर रैली की पूर्व जानकारी देता है कि वे कब, कहां रैली करेंगे. इसके चलते जितनी जनता मोदी की रैली में पहुंचती है, उससे ज्यादा जनता टीवी पर उन्हें सुनती है. चैनल और किसी भी नेता के प्रचार अभियान को इतना कवरेज नहीं दे रहे हैं. मोदी की रैलियों में जुटने वाली भीड़ मीडिया द्वारा मचाए गए शोर का अंजाम है. मोदी पर मीडिया इस तरह से मेहरबान इसलिए है, क्योंकि मोदी ने कॉरपोरेट जगत को गुजरात में काफ़ी स्थान दिया है, जहां पर वे बिना किसी व्यवधान के फल-फूल सकते हैं. प्रधानमंत्री बनने पर वे देश भर में कॉरपोरेट को अधिक स्पेस देने का वादा भी कर रहे हैं. वे बाज़ारवादी नीतियों को और ज्यादा खोलना चाहते हैं. उनके इस वादे पर कॉरपोरेट बाग-बाग है और वह मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है. यह खेल जनता शायद नहीं समझती. अब देखने वाली बात है कि कॉरपोरेट-मोदी और मीडिया का यह गठबंधन कितना रंग लाएगा और जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? ■

> **नरेंद्र मोदी जिस गुजरात के विकास मॉडल का ढोल पीटते हैं, उसमें तमाम मानव विकास सूचकांक और दूसरे पैमाने पर गंभीर ख़ामियां हैं, लेकिन मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाता. मीडिया में सिर्फ़ मोदी से जुड़ी रैलियां और प्रचार को ही पेश किया जाता है, उनकी आलोचना नहीं. मीडिया मोदी की हर रैली की पूर्व जानकारी देता है कि वे कब, कहां रैली करेंगे.**

feedback@chauthiduniya.com

> रोज़गार के मामले में भी गुजरात के मुसलमान हिन्दुओं के मुक़ाबले काफ़ी पिछड़े हैं. गुजरात के 71 प्रतिशत हिन्दुओं में से 61 प्रतिशत के पास रोज़गार हैं, जबकि मुसलमानों में रोज़गार केवल 10 प्रतिशत के पास ही है, इस प्रकार बेरोज़गारी के मामले में गुजरात के मुसलमान सबसे आगे हैं, यहां तक कि पश्चिम बंगाल से भी बदतर हालत उनकी गुजरात में है.

गुजरात : मुसलमान बदहाल, विकास केवल ढकोसला

कल तक नरेन्द्र मोदी केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब वह भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं. कल तक मोदी से घृणा करने वाले मुसलमानों में भी अब उनके प्रति सोच में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन उनके इस सवाल का अब भी कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा है कि क्या मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसलमानों की जान व माल की सुरक्षा की गारंटी देंगे? मोदी की ओर से अब तक ऐसा कोई इशारा नहीं मिला है, जिससे मुसलमानों को यह लगे कि भाजपा को वोट देने से उनका भविष्य इस देश में सुरक्षित रहेगा. आइए देखते हैं कि गुजरात के मुसलमानों की इस समय क्या स्थिति है, ताकि यह बात साफ़ हो सके कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भारत के मुसलमानों पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा.

डॉ. क़मर तबरेज़

यह बात बिल्कुल सही है कि गुजरात में 2002 के बाद कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ और यह भी एक हक़ीक़त है कि 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य के 25 प्रतिशत मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया था और गुजरात के आठ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भाजपा को छह सीटों पर जीत मिली थी. भाजपा इन सबका श्रेय वहां के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेतृत्व में होने वाले विकास को देती है, लेकिन मुसलमानों को अब भी यह गिला है कि मोदी ने अपने राज्य में मुसलमानों के जनसंहार पर अब तक माफ़ी नहीं मांगी. मुसलमानों को यह भी शिकायत है कि नरेन्द्र मोदी अपनी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अपने किसी भी भाषण में मुसलमानों को लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं. मुसलमान यह जानना चाहते हैं कि मोदी के पास इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों को लेकर क्या नीतियां हैं, लेकिन मोदी की ओर इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है. कुछ लोग यह कहते हैं कि मोदी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन क्या इस सच्चाई से इन्कार किया जा सकता है कि 20 करोड़ की आबादी को नज़रअंदाज़ करके देश कभी विकास कर सकता है? इसलिए यह सवाल पूछना लाज़िमी है कि अगर मोदी ने गुजरात में विकास का मॉडल पेश किया है तो देश के मुसलमानों के विकास का कौन सा मॉडल उनके पास है? क्या वह प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर कर देंगे? क्या वह सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व में इज़ाफ़ा करेंगे? क्या वह मुसलमानों की शैक्षणिक बदहाली को दूर कर पाएंगे? अगर मोदी के पास इन सबका जवाब 'हां' में है तो उन्हें आम चुनावों से पूर्व मुसलमानों को लेकर अपने प्रोग्राम की घोषणा ज़रूर कर देनी चाहिए.

गुजरात के मुसलमानों की स्थिति पर अगर ध्यान दें, तो पता चलता है कि वहां के मुसलमान 2002 के दंगों के पहले जितने ख़ुशहाल थे, उतने ख़ुशहाल वे वर्तमान में नहीं हैं. हम सब जानते हैं कि 2002 में गुजरात में केवल डेढ़ हज़ार मुसलमानों का नरसंहार हीं नहीं हुआ था, बल्कि उनकी दुकानों और मकानों को भी आग लगा दी गई थी. उनके कारोबारों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया था. दंगों से पहले उन्हें अपने कारोबार के लिए बैंकों आदि से क़र्ज़ आसानी से मिल जाया करते थे, वे बाद में भेदभाव का शिकार होकर रह गए और सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के सभी रास्ते उनके लिए बंद कर दिए गए. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद केन्द्र की ओर से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए जिन शैक्षणिक छात्रवृत्तियों आदि की व्यवस्था की गई, उसे गुजरात सरकार ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया. पुलिस विभाग को छोड़ दें तो ऐसा कोई भी विभाग नहीं है, जिसमें मुसलमानों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिल रहा हो. इस सच्चाई को भी कोई झुठला नहीं सकता कि गुजरात में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है, पुलिस विभाग में भी किसी बड़े पद पर कोई मुस्लिम दिखाई नहीं देता, गुजरात की नौकरशाही में भी दूर–दूर तक कोई मुस्लिम चेहरा नज़र नहीं आता, दो–चार बड़े मुस्लिम कारोबारी हैं भी, तो उनके नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं. ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि नरेन्द्र मोदी आख़िर कैसे देश के 20 करोड़ मुसलमानों की सुरक्षा व विकास की गारंटी देंगे?

आइए कुछ उदाहरण देखते हैं. गुजरात के अहमदाबाद के चंपनपुरा क्षेत्र से संबंध रखने वाले मेराज अहमद 2002 से पूर्व अपना कढ़ाई का एक कारख़ाना चलाते थे, जिससे प्रतिमाह उनकी 15–20 हज़ार रुपये की आमदनी हो जाती थी. दंगों के दौरान उन्होंने लगभग ढाई लाख रुपये में अपना मकान एक हिन्दू पड़ोसी को बेच दिया और शरणार्थियों के लिए बनाए गए कैंप के क्षेत्र बॉम्बे होटल की ओर भाग गए, जिससे उनकी और उनके परिवार की जान बच गई. अब हालत यह है कि लाख कोशिशों के बाद भी वह अपना कारोबार उचित ढंग से नहीं चला पा रहे हैं और न ही इतना पैसा कमा पाते हैं, जिससे वह अपना और अपने घर वालों का पेट भर पाएं. राज्य सरकार ने दंगों के बाद मुआवज़े के रूप में उन्हें केवल 300 रुपये दिए थे, जिससे न तो वह अपना नया घर ख़रीद सकते थे और न ही अपना नया कारख़ाना खोल सकते थे. यही हाल आशिक अली का है, जो पहले ऑटोरिक्शा चलाकर प्रतिदिन डेढ़ सौ रुपये तक कमा लिया करते थे, लेकिन अब वह एक सुरक्षाकर्मी का काम करते हैं, जिससे उन्हें प्रतिमाह 1800 रुपये मिलते हैं.

अब देखते हैं कि गुजरात के विकास मॉडल का सच क्या है. इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार ने गुजरात के 90 प्रतिशत गांवों में पक्की सड़कें बनवाई हैं, 98 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया है, जहां पर प्रतिदिन 18 घंटे तक बिजली आपूर्ति होती है, पाइप के ज़रिए पानी की आपूर्ति 86 प्रतिशत गांवों तक में है, दूसरे राज्यों की तुलना में फोन कनेक्शन बेहतर हैं, डाकख़ानों की स्थिति बेहतर है, बसें सुचारु रूप से चल रही हैं, लेकिन इन सबके विपरीत यह भी एक सच्चाई है कि दूसरे राज्यों के मुक़ाबले गुजरात में ग़रीबी और भुखमरी तो अधिक है ही, लोगों में सुरक्षा के प्रति ख़ौफ़ का माहौल भी बहुत अधिक है.

क्या 20 करोड़ की आबादी को नज़रअंदाज़ करके देश कभी विकास कर सकता है? अगर मोदी ने गुजरात में विकास का मॉडल पेश किया है तो देश के मुसलमानों के विकास का कौन सा मॉडल उनके पास है? क्या वह प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर कर देंगे? क्या वह सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व में इज़ाफ़ा करेंगे? क्या वह मुसलमानों की शैक्षणिक बदहाली को दूर कर पाएंगे?

एक साल पहले सच्चर कमेटी के सदस्य रह चुके वाशिंगटन में स्थित यूएस–इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट से जुड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अबु सालेह शरीफ़ की गुजरात के विकास को लेकर एक लंबी रिपोर्ट आंखें खोलती है. यह रिपोर्ट मोदी के डेवलपमेंट मॉडल को नकारती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के दूसरे राज्यों के मुक़ाबले गुजरात में प्रति व्यक्ति आय तो अधिक है, लेकिन ओडिशा और बिहार की तरह (जहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है) गुजरात में भी भुखमरी उच्चस्तर पर है. होना तो यह चाहिए था कि आमदनी बढ़ने से लोगों की उम्र में इज़ाफ़ा होता, लिंग अनुपात बेहतर होता, सातवीं क्लास के बाद स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या कम होती, साक्षरता दर में इज़ाफ़ा होता, लेकिन गुजरात में आमदनी बढ़ने से यह सबकुछ नहीं हो रहा है. इसलिए मोदी द्वारा केवल इस बात का प्रचार करना कि गुजरात में लोगों की आय बढ़ रही है, कोई मायने नहीं रखता. इसका प्रभाव जीवन के दूसरे क्षेत्रों पर भी नज़र आना चाहिए.

इसी प्रकार मोदी पूरे देश में यह कहते फिर रहे हैं कि गुजरात में उनकी सरकार देश के शेष हिस्सों के मुक़ाबले सबसे अधिक विदेशी निवेश को लाने और उसे विकसित करने में सबसे आगे है. बकौल अबुल सालेह शरीफ़, यह भी एक बड़ा झूठ है. उनकी तहक़ीक़ात कहती है कि एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के बारे में मोदी सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट के द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2000 से मार्च 2010 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे अधिक महाराष्ट्र में आया, जो 1.75 लाख करोड़ रुपये था. दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां यह निवेश 1.02 लाख करोड़ रुपये का रहा और 31 हज़ार करोड़ रुपये के विदेशी निवेश के साथ कर्नाटक चौथे नंबर पर है. गुजरात तो बस पांचवें नंबर पर है, जहां इस अवधि के दौरान केवल 28 हज़ार करोड़ विदेशी निवेश किया गया है. इस प्रकार यह बात झूठी साबित हो जाती है कि विदेशी सरकारों के लिए भारत में सबसे पसंदीदा जगह गुजरात है.

अब आइए देखते हैं कि गुजरात में मुसलमानों की वर्तमान स्थिति के बारे में अबु सालेह शरीफ़ क्या कहते हैं. उनकी रिपोर्ट कहती है कि गुजराती मुसलमानों में अगड़ी जाति के हिन्दुओं के मुक़ाबले ग़रीबी आठ गुना (800 प्रतिशत) अधिक है, जबकि हिन्दू अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मुक़ाबले यह ग़रीबी 50 प्रतिशत अधिक है. इसी प्रकार इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गुजरात के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली कुल मुस्लिम आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक दृष्टि से गुजरात में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है. दूसरी ओर गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वाले मुस्लिम अगड़ी जाति के हिन्दुओं से दोगुना (200 प्रतिशत) अधिक ग़रीब हैं. इसके अलावा गुजरात के मुसलमानों का उनकी आबादी के अनुपात से बैंकों में खाता है, लेकिन बैंकों से उन्हें केवल 2.6 प्रतिशत कर्ज़ ही मिल पाता है. इसी प्रकार अन्य जातियों के मुक़ाबले मुसलमानों के यहां अधिक चोरी होती है, उनकी लड़कियों से अधिक छेड़छाड़ होती है.

शिक्षा की बात करें, तो गुजरात में दूसरी जातियों की तरह ही मुसलमानों के द्वारा स्कूलों में प्रवेश लेने की दर लगभग 75 प्रतिशत है, लेकिन हाई स्कूल या उससे ऊपर के स्तर पर मुसलमानों के प्रवेश लेने की दर काफ़ी कम है. केवल 26 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे ही हाई स्कूल तक पहुंच पाते हैं, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में यह दर 41 प्रतिशत है. पांचवी कक्षा के बाद मुसलमानों में स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है. उच्च शिक्षा की दर तो मुसलमानों में चिंताजनक स्थिति तक कम है. शिक्षा के विभिन्न चरणों में मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सच्चर कमेटी की अनुशंसाओं पर केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी. केन्द्र सरकार ने गुजरात के लिए 55,000 छात्रवृत्तियां आबंटित की थीं, जिनमें से 53,000 मुस्लिम बच्चें को दी जानी थीं, लेकिन मोदी की गुजरात सरकार ने इसे लेने से इन्कार कर दिया. ज़ाहिर है, इसका सबसे बड़ा नुक़सान गुजरात के मुस्लिम बच्चों को ही हुआ, जो शैक्षणिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं.

रोज़गार के मामले में भी गुजरात के मुसलमान हिन्दुओं के मुक़ाबले काफ़ी पिछड़े हैं. गुजरात के 71 प्रतिशत हिन्दुओं में से 61 प्रतिशत के पास रोज़गार हैं, जबकि मुसलमानों में रोज़गार केवल 10 प्रतिशत के पास ही है, इस प्रकार बेरोज़गारी के मामले में गुजरात के मुसलमान सबसे आगे हैं, यहां तक पश्चिम बंगाल से भी बदतर हालत उनकी गुजरात में है. मुसलमानों के बारे में भारत में आम तौर पर यह बात देखी गई है कि काम के मामले में वह मूल रूप से हुनरमंद और हस्तशिल्प के माहिर होते हैं और दूसरी जातियों के मुक़ाबले उन्हें मकेनिकल और टूल वर्क अधिक आता है, इसीलिए उत्पादन और आर्गनाइज्ड सेक्टर में हिन्दू कामगारों की संख्या अधिक है. गुजरात में भी किसी ज़माने में पॉवरलूमों, टैक्सटाइल मिलों और हैंडलूम मिलों, हीरे की कटाई और पॉलिशिंग इंडस्ट्री में मुसलमानों का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है. पूरे भारत में कपड़ा उद्योग में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 21 प्रतिशत है, लेकिन गुजरात में यह केवल 13 प्रतिशत है, जबकि महाराष्ट्र में इससे कहीं अधिक 25 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 21 प्रतिशत है. गुजरात में पब्लिक सेक्टर में भी मुसलमानों को पूरी तरह नज़र अंदाज़ किया जा चुका है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> नीतीश सरकार में शामिल निर्दलीय विधायक असंतुष्ट हैं और सरकार संवैधानिक संकट के दौर से गुज़र रही है. निर्दलीय विधायकों के सहारे सरकार बचा कर नीतीश ने अपनी मॉरल अथॉरिटी कमज़ोर कर ली है. जोड़–तोड़ की कोशिश भी लगातार जारी है. जिन उम्मीदों से निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया है वो पूरा होता दिख नहीं रहा है. और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री पर लगातार दबाव भी बढ़ता जा रहा है.

सबके प्यारे चौधरी चरण सिंह

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का नतीजा यह हुआ कि चौधरी चरण सिंह अपनी 111वीं जयंती के अवसर पर अनेक खेमों में बंट गए. सपने में भी चौधरी साहब ने यह नहीं सोचा होगा कि उनके नाम का तो सब इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनके सपनों को कोई पूरा करने को लेकर गंभीर नहीं है.

अजय कुमार

पूर्व प्रधानमंत्री और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताकतवर किसान नेता चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत पर किसका पहला हक है, यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है. चौधरी की विरासत को लेकर सभी के अपने–अपने दावे हैं. महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ चौधरी चरण सिंह आगे बढ़े थे, इसलिए उनकी विरासत पर कांग्रेस का सबसे पहला हक़ है. यह बात समाजवादी मानने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि कांग्रेस की नीतियों से दुखी होकर चौधरी अलग हो गए थे. वह कट्टर समाजवादी थे. ज़मींदारी उन्मूलन का ख़ात्मा और भूमि संरक्षण क़ानून उन्हीं की देन थी. मुलायम उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और मानते हैं. उनके बताए मार्ग पर आज भी मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी चल रही है, इसलिए सपा का उन पर पहला अधिकार है. कांग्रेस और सपा दोनों ही ग़लत हैं. असल में भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र ऐसा सियासी दल है, जो चौधरी चरण सिंह की सोच को आगे बढ़ा रहा है. किसानों की चिंता, ग़रीबों का दर्द आज किसी को है, तो सिर्फ़ भाजपा को. इसलिए विचारों से चौधरी साहब भाजपा के क़रीब हैं और तमाम पार्टियों के नेता ग़लतबयानी कर रहे हैं. चौधरी साहब ने किसी को अपनी विरासत का रखवाला नहीं बनाया. राष्ट्रीय लोकदल के चरित्र में चौधरी साहब की विचारधारा समाहित है. अगर चौधरी साहब का सपना किसी नेता ने पूरा किया होता तो मुझे (चौधरी अजित सिंह) लोकदल को खड़ा नहीं करना पड़ता. मैं यह बात चौधरी चरण सिंह का पुत्र होने के नाते नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह कड़वी सच्चाई है. चौधरी चरण सिंह के नाम पर तमाम नेताओं ने वोट तो ख़ूब बटोरे, लेकिन उनके सपनों को किसी ने साकार किया होता तो आज किसानों और ग़रीबों की यह दशा न होती. वह तिल–तिल मरने को मजबूर न होता.

तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की परस्पर विरोधी सोच का ही नतीजा था कि हर दिल अजीज़ चौधरी चरण सिंह अपनी 111वीं जयंती के अवसर पर अनेक खेमों में बंट गए. सपने में भी चौधरी साहब ने यह नहीं सोचा होगा कि उनके नाम का तो सब इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने को लेकर कोई गंभीर नहीं है. बसपा को छोड़कर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं दिखी, जो चौधरी चरण सिंह का वोट बैंक हथियाने को लालायित न हो. सपा और रालोद में तो चौधरी की विरासत को लेकर एक तरह से तलवारें ही खिंच गईं. कभी साथ–साथ चलने वाले दोनों ही दल 2014 के लोकसभा चुनाव में चौधरी साहब का नाम और काम भुनाने की फ़िक्र में नज़र आए. मुलायम एंड पार्टी तथा चौधरी अजित सिंह एंड पार्टी में चरण सिंह को लेकर ग़ज़ब का उतावलापन देखने को मिला. इसी का नतीजा था कि लखनऊ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और वहां से लेकर दिल्ली तक में जगह–जगह चरण सिंह की जयंती पर तमाम कार्यक्रम देखने को मिले. उनकी जयंती पर छुट्टी सहित जाटों को आरक्षण का भी पासा फेंका गया. सपा, उत्तर प्रदेश की सत्ता में है, इसलिए समाजवादी सरकार ने चौधरी साहब की जयंती पर छुट्टी घोषित कर उनके प्रति आस्था का तानाबाना बुना. वहीं केन्द्रीय मंत्री छोटे चौधरी अजित सिंह की मंशा को पूरा करते हुए केन्द्र की मनमोहन सरकार ने जाटों को आरक्षण देने की घोषणा कर दी. कांग्रेस और चौधरी अजित सिंह ने इशारों–इशारों में चौधरी की विरासत पर अपना अधिकार होने का मैसेज दिया तो लखनऊ में चौधरी साहब की प्रतिमा पर पहले माला पहनाने को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं के बीच होड़ सी लगी रही.

सपा प्रमुख मुलायम अपने दम पर चौधरी चरण सिंह की विरासत के लिए दावेदारी ठोंक रहे थे तो मेरठ में रालोद की संकल्प रैली में छोटे चौधरी अजित सिंह, सांसद जयंत चौधरी, जदयू शरद यादव, केसी त्यागी, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा नज़र आए. छोटे चौधरी अजित सिंह ने अपनी संकल्प रैली में मुलायम सिंह को बुलाने की ज़रूरत नहीं समझी, जो ख़ुद को चौधरी साहब का असली उत्तराधिकारी बताते हैं. मुलायम और अजित दोनों ही तरफ़ से इस मौक़े पर यह पहल नहीं हुई कि विरासत को बांटने की कोशिश करने के बजाय एक साथ इसे संभाला जाए.

वरिष्ठ पत्रकार और पूरे घटनाक्रम के साक्षी रहे विक्रम राव कहते हैं कि बेटा होने के कारण अजित सिंह चौधरी चरण सिंह का उत्तराधिकारी है तो कर्म के आधार पर मुलायम सिंह यादव का पलड़ा भारी पड़ता है. वैसे भी यह झगड़ा नया नहीं है. वर्ष 1989 में प्रदेश में जनता दल को बहुमत मिलने के साथ ही इसकी नींव पड़ गई थी, जब नेता विधानमंडल दल या मुख्यमंत्री का नाम वोट से तय हो पाया था. चौधरी अजित सिंह और मुलायम सिंह यादव के बीच मतदान से फैसला हो पाया. अजित सिंह एक या दो वोट से मुलायम से हार गए थे. राव कहते हैं कि तय तो जनता को करना है कि वह किसे चौधरी साहब का असली वारिस मानती है, पर आज चौधरी अजित सिंह से मेरे जैसे लोग इस सवाल का जवाब ज़रूर चाहते हैं कि उन्होंने अपने पिता की राह पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के किसानों और आम लोगों की भलाई के लिए कौन–कौन से ज़मीनी काम किए. ■

feedback@chauthiduniya.com

निर्दलीय विधायक न घर के न घाट के

शशि सागर

विधानसभा का सत्र दोपहर एक बजे तक के लिये स्थगित कर दिया गया था. कुछ विधायक आपस में हंसी–मज़ाक कर रहे थे. बीजेपी के एक विधायक ज्योतिषीय अंदाज़ में एक निर्दलीय विधायक का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि लाइए आपका भविष्य बताते हैं. हाथ की रेखाओं को देखते हुए कहते हैं, अरे महराज आपका भविष्य तो उज्ज्वल है. रेखाएं बता रही हैं कि आप जल्द ही दिल्ली की राजनीति करेंगे. इतना कहना था कि सभी लोग हंसने लगते हैं और पास ही खड़े जदयू के एक मंत्री कहते हैं कि आप हमारे समर्थक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं पंडित जी. लेकिन बात वहीं आई गई हो जाती है. इसी तरह का नज़ारा एक निर्दलीय विधायक के आवास पर देखने को मिलता है. विधायक जी के सामने एक अख़बार रखा होता है जिसके पहले पन्ने पर मुख्यमंत्री नीतीश की तस्वीर छपी होती है. विधायक जी तस्वीर को देखते हुए कहते हैं कि जल्दी मंत्री बनाइए हमें नीतीश जी, न तो चल जाएंगे बीजेपी में. बुला रहा है हमको लोकसभा चुनाव लड़ने को.

बात भले ही हंसी–मज़ाक में कही गई हो, लेकिन इसके संकेत बड़े साफ हैं. जिन निर्दलीय विधायकों ने समर्थन देकर सरकार बचाई, उनके बीच निराशा के भाव साफ दिख रहे हैं. वहीं भाजपा यह कोशिश भी करती नज़र आ रही है कि जिन चारों ने सरकार बचाई है, उन्हें किसी भी प्रकार से भाजपा के पाले में लाया जाय. बहरहाल जदयू–भाजपा के अलगाव के बाद नीतीश के सामने सत्ता को बचाए रखने का संकट था. 243 विधानसभा सीट वाले बिहार में नीतीश के पास 118 विधायक थे. ऐसे में उन्हें विश्वासमत हासिल करने के लिए चार विधायकों की आवश्यकता थी. ऐसे में जदयू के आला नेताओं ने पहले निर्दलीय विधायकों को साधने की कोशिश की. साथ ही राजद और भाजपा के विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश की गई. बताते चलें कि फ़िलहाल बिहार में छह निर्दलीय विधायक हैं. इनमें से चार विधायकों– दुलालचंद्र गोस्वामी, बिनय बिहारी, सोमप्रकाश व पवन जायसवाल ने नीतीश को समर्थन दिया. इस दौरान सरकार पर निर्दलीय विधायकों की ख़रीद–फरोख़्त का भी इल्ज़ाम लगा था. इस दौरान पश्चिम चंपारण के सिकटा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक दिलीप वर्मा ने यह आरोप भी लगाया था कि उन्हें जदयू के एक नेता के द्वारा कहा गया कि आप मिनिस्टर पद ले लीजिए और आपको 2014 में लोकसभा का टिकट भी दिया जाएगा, लेकिन आप सरकार का समर्थन कर दीजिए. कुछ ऐसे ही आरोप राजद और भाजपा की तरफ से भी लगाए गए थे कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. इस बीच जदयू को कांग्रेस अपने चार विधायकों के साथ तो सीपीआई ने भी अपने एक विधायक के साथ समर्थन दिया.

सरकार तो बच गई. भाजपा के कोटे के 11 मंत्रियों का विभाग भी मुख्यमंत्री ख़ुद देख रहे हैं. इस बीच सीएम पर लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि उनपर काम का दबाव बढ़ गया है और क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है. निर्दलीय विधायक भले ये कहें कि उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया था, लेकिन वे गाहे–ब–गाहे यह जताने की कोशिश भी करते रहते हैं कि वे मंत्री पद की ज़िम्मेवारियों को सम्भालने के तैयार हैं. पिछले दिनों सत्तापक्ष के विधायक दल की बैठक से समर्थन दे रहे चारों निर्दलीय विधायक नदारद थे. जिस दौरान विधायक दल की बैठक चल रही थी, चारों निर्दलीय विधायक बिहार गृह रक्षा वाहिनी के धरने को समर्थन देने पहुंचे थे. पुलिस अधिकारी से विधायक बने और सरकार को समर्थन दे रहे सोमप्रकाश ने इस दौरान सरकार की आलोचना भी की और कहा कि यह पहला राज्य है जहां समान कार्य के लिए अलग–अलग वेतन और भत्ता दिया जाता है. साथ ही यह भी कहा कि अगर सरकार गृहरक्षकों की मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो गृहरक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और ठप विधि–व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ज़िम्मेवार होगी. वैसे सोमप्रकाश यह भी कहते हैं कि उन्होंने सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया है और उन्हें मंत्री पद की लालसा नहीं है. निर्दलीय मीडिया के ज़रिये अपनी मंशा जता रहे हैं. यही वजह है कि सरकार अब विकल्प तलाशने में भी जुट गई है. सूत्र बताते हैं कि जदयू की तरफ से राजद के कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. जदयू के एक नेता कहते हैं कि राजद के लगभग दस विधायक जदयू से संपर्क में हैं.

ढाका के निर्दलीय विधायक पवन जायसवाल कहते हैं कि समर्थन देने से पहले भी हमने यह नहीं कहा था कि हमें मंत्री बनाया जाय. यह पूछने पर कि आप तो सत्तापक्ष के विरोध में जीत कर आए थे. ऐसे में बिना शर्त समर्थन का आधार क्या बनता है. जायसवाल कहते हैं कि हम निर्दलीय विधायकों का यह सोचना था कि बिहार मध्यावधि चुनाव न झेले और विकास का काम बाधित न हो, इसलिए सरकार को गिरने से बचाया. जायसवाल यह भी कहते हैं कि मंत्री बनना किसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और देखना यह है कि वह किसे किस आधार पर मंत्री पद देते हैं. लेकिन जब मैंने उन्हें समर्थन दिया है तो इतना तो जरूर चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में विकास का काम तेज़ी से हो. जायसवाल यह तो कहते हैं कि सरकार पर काम का कोई बोझ नहीं है और वे सरकार के काम से संतुष्ट हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि एनडीए–वन की सरकार एनडीए–टू से बहुत ही बेहतर थी. वैसे मंत्रिमंडल का विस्तार तो बहुत पहले हो जाना था. सूत्र बताते हैं कि जिन्हें–जिन्हें मंत्री बनाया जाना है और जिनसे मंत्रिमंडल वापस लिया जाना है, ये पूरी लिस्ट तय है. इसको लेकर मुख्यमंत्री दो बार राज्यपाल से मुलाक़ात भी कर चुके हैं. लेकिन लगातार हुई कई घटनाओं की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार का मामला अटकता चला गया.

एक निर्दलीय विधायक अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहते हैं कि यह हमारी कार्यकुशलता पर ही सवाल है. लोग यह मामने लगे हैं कि निर्दलीय मंत्रिमंडल का भार उठाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है या फिर उन्होंने पैसे लेकर समर्थन दिया होगा. उन्हें इस बात का दुख है कि वे समर्थन देकर जनता के बीच अपनी ही साख़ पर बट्टा लगवा रहे हैं. बलरामपुर विधानसभा से दुलालचंद्र गोस्वामी निर्दलीय विधायक हैं. इससे पहले वे बीजेपी से विधायक रह चुके हैं. गोस्वामी कहते हैं कि हमने सरकार को समर्थन दिया, इसमें कोई वादा व छुपा हुआ इरादा नहीं था. समर्थन देने के पीछे मात्र यह तर्क था कि बिहार के विकास की गति अवरुद्ध न हो और राज्य की जनता पर असमय आर्थिक बोझ न बढ़े. वैसे हर कोई अपना बेहतर भविष्य देखता है और अगर कोई ज़िम्मेवारी मिलती है तो इसे मज़बूती से निभाउंगा भी. लेकिन इसके लिए कोई बेचैनी नहीं है. मुख्यमंत्री के एक क़रीबी बताते हैं कि दो निर्दलीय विधायकों का मंत्री बनना तय है और यह जल्द ही हो जाएगा. जदयू के प्रदेश महासचिव व बांका विधानसभा के प्रभारी उदयशंकर कहते हैं कि निर्दलीय विधायकों में कहीं से कोई निराशा नहीं है और काम भी आसानी से हो रहा है. रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की तो वो भी सामाजिक समीकरण और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कर दिया जाएगा. लेकिन प्रोफेशर नवल किशोर चौधरी इन बातों से इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं. नवल कहते हैं कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि निर्दलीय असंतुष्ट हैं और सरकार संवैधानिक संकट के दौर से गुज़र रही है. निर्दलीय विधायकों के सहारे सरकार बचा कर नीतीश ने अपनी मॉरल अथॉरिटी कमज़ोर कर ली है. जोड़–तोड़ की कोशिश भी लगातार जारी है. जिन उम्मीदों से निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया है वो पूरा होता दिख नहीं रहा है. और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री पर लगातार दबाव भी बढ़ता जा रहा है. और रही बात जल्द से जल्द मंत्रिमंडल के विस्तार की तो इसके बाद जदयू खेमे में उठा–पटक मचना भी तय है. अब देखना है कि सुशासन के मुखिया इस परेशानी से कैसे पार पाते हैं. ■

www.chauthiduniya.com चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

राजनीतिक हवाओं के रुख़ को समझिए

आम आदमी पार्टी एक नया प्रयोग है, जिसे हम सभी ने बेहद क़रीब से देखा. पार्टी के जो भी पांच-छह मंत्री पदस्थ होंगे, यदि वे भ्रष्ट नहीं हैं, तो यह नौकरशाही के लिए एक संदेश होगा. नौकरशाही निर्लज्जता के स्तर पर पहुंच चुकी है, बेशक उसमें कमी आएगी. चूंकि आज वे जानते हैं कि ऊपर बैठे लोग भ्रष्ट हैं, इसीलिए नौकरशाह केवल पैसे बनाने की फ़िराक़ में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जांच करने वाला कोई नहीं है. देश की नीतियों को बेहतर बनाने के संदर्भ में आम आदमी पार्टी जो सबसे बड़ा योगदान दे सकती है, वह है नौकरशाही में भय पैदा करना.

कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है. उसकी मौजूदगी देश के हर हिस्से में दर्ज है. पार्टी के पास एक सशक्त नेतृत्व है, लेकिन ज़ाहिर तौर पर जो लोग निर्णय ले रहे हैं वो परिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं हैं, जिस पर कांग्रेस हमेशा से शेखी बघारती रही है. नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय हैं, इस बात को कोई नहीं नकारता है. निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी पार्टी के चुनाव प्रचार में मददगार साबित हुए हैं, लेकिन दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों का क्या, जहां भाजपा का वजूद नहीं है? यहां रातभर में भाजपा को स्थापित कर पाना संभव नहीं है.

देश में राजनीतिक घटनाएं विविध रूपों में आकार लेती दिखाई पड़ रही हैं. दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से आप पार्टी की सरकार बनी और तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया, जबकि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा. बावजूद इसके, एक बात अभी तक साफ़ तौर पर समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस के दिमाग़ में क्या चल रहा है? कोई भी राजनीतिक दल जिसे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो और जिसे विधानसभा की 70 सीटों में से केवल आठ सीटें मिली हों, वह किसी दूसरी पार्टी को बिना शर्त समर्थन कैसे दे सकता है, जबकि उनसे किसी ने समर्थन न मांगा हो. निश्चित तौर पर उन्होंने भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए ही आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया, यह बेहद बचकाना और अपरिपक्व निर्णय है.

जो भी हो, आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया यह चुनाव वास्तव में कांग्रेस के पिछले 15 वर्ष के शासन के विरोध में है. लोगों का मत चाहे जो भी हो, लेकिन परिणाम तो यही ज़ाहिर करते हैं कि कांग्रेस की चार राज्यों में बुरी तरह हुई पराजय की वजह वहां पर भाजपा की लोकप्रियता नहीं, बल्कि कांग्रेस की नकारात्मक छवि रही. जहां कहीं भी लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, वहां उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट किया. जहां उनके पास विकल्प मौजूद था, वहां उन्होंने तीसरे विकल्प के पक्ष में वोट किया. अब स्थिति को सुधारने के बजाए, वे बीजेपी के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि बीजेपी ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हो. कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनके अंदर ही है. जब तक वो अपनी छवि नहीं सुधारेंगे, जब तक वे घोटाले करके पैसे बनाने वाले और झूठे वादे करने की छवि से बाहर नहीं आएंगे, तब तक वे अपना चुनावी परिप्रेक्ष्य कैसे बदल पाएंगे?

कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है. उसकी मौजूदगी देश के हर हिस्से में दर्ज है. पार्टी के पास एक सशक्त नेतृत्व है, लेकिन ज़ाहिर तौर पर जो लोग निर्णय ले रहे हैं वो परिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं हैं, जिस पर कांग्रेस हमेशा से शेखी बघारती रही है. नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय हैं, इस बात को कोई नहीं नकारता है. निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी पार्टी के चुनाव प्रचार में मददगार साबित हुए हैं, लेकिन दक्षिण भारत और देश के पूर्वोत्तर राज्यों का क्या, जहां भाजपा का वजूद नहीं है? यहां रातभर में भाजपा को स्थापित कर पाना संभव नहीं है. वहां तीसरी ताक़तें होंगी. दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय नेता होंगे और वे चुनाव में कई सीटों पर विजयी भी होंगे.

कांग्रेस को अपनी भाजपा विरोधी नीति को बदलकर स्व-हितैशी बनाना होगा. पार्टी को फिर से रूपरेखा तैयार करनी होगी कि कांग्रेस के होने का मतलब क्या है? यदि वह चुनाव जीतती है या फिर गठबंधन की सरकार का गठन करती है, तो पार्टी के पास जनहित के लिए कौन-सी योजनाएं हैं. यदि विश्लेषक सारी चीज़ों का विश्लेषण करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कांग्रेस और भाजपा की नीतियों में बमुश्किल ही कोई अंतर है. आर्थिक नीतियों के मसले पर दोनों ही दल अमीरों और अमेरिका की पक्षधरता के हिमायती हैं. वे सुधारों की, उदारीकरण की और कॉरपोरेट क्षेत्र को फ़ायदा पहुंचाने की पैरवी करते हैं. अगर दोनों की विचारधारा यही है, तो फिर दोनों पार्टियों में अंतर क्या है? एक पार्टी घोटालों में लिप्त है तो दूसरी पिछले दस वर्षों से सत्ता हासिल करने की जुगत में है. इसलिए निश्चित तौर पर सरकार विरोधी लहर मौजूद है, जिसका कुछ हद तक फ़ायदा भाजपा को मिलेगा.

आम आदमी पार्टी एक नया प्रयोग है, जिसे हम सभी ने बेहद क़रीब से देखा. पार्टी के जो भी पांच-छह मंत्री पदस्थ होंगे, यदि वे भ्रष्ट नहीं है, तो यह नौकरशाही के लिए एक संदेश होगा. नौकरशाही निर्लज्जता के स्तर पर पहुंच चुकी है, बेशक उसमें कमी आएगी. चूंकि आज वे जानते हैं कि ऊपर बैठे लोग भ्रष्ट हैं, इसीलिए नौकरशाह केवल पैसे बनाने की फ़िराक़ में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जांच करने वाला कोई नहीं है. देश की नीतियों को बेहतर बनाने के संदर्भ में आम आदमी पार्टी जो सबसे बड़ा योगदान दे सकती है, वह है नौकरशाही में भय पैदा करना. उन्हें जनता की सेवा करने के लिए तनख़्वाह मिलती है. वे तनख़्वाह के अलावा हर एक काम के लिए पैसों की मांग नहीं कर सकते. लेकिन ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि वह हर काम के लिए पैसा मांगते हैं. यह समाप्त होना चाहिए.

आम आदमी पार्टी ने बिजली और पानी की दरों को कम करने की बात की है, अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वे भ्रष्टाचार कम करने में सफल हुए तो यही उनकी असली सफलता होगी. भ्रष्टाचार कम करना इतना आसान नहीं है. अगर वे ऊंचे स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को कम करने में सफल होते हैं, तो देश की राजनीति के यह एक नया मोड़ साबित होगा.

मैं नहीं जानता कि अन्ना हजारे इस मसले पर क्या सोच रहे हैं, लेकिन यदि लोकसभा चुनावों तक अन्ना हजारे कुछ अच्छे उम्मीदवारों को अपना समर्थन देते हैं तो यह बेहतर होगा, क्योंकि यह ज़रूरी है कि अच्छे लोग आएं और देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं. इस पूरे माहौल में इस बात की भी बेहद ज़रूरत है कि तीसरे मोर्चे के लोग साथ हों, लेकिन तीसरे मोर्चे के नेता किसी विकल्प के तौर पर आगे आने के लिए जल्दी में नहीं दिख रहे हैं. हर कोई चुनाव परिणामों का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि असली सौदेबाज़ी उसी के बाद शुरू होगी. यह अच्छा चलन नहीं हैं. गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई नेताओं को साथ में मिलकर एक सक्षम तीसरे मोर्चे की स्थापना करनी चाहिए, जो कि देश की सरकार चलाए. देखिए, आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्र का पुनर्निर्माण उसके लाखों गांवों का पुनर्निर्माण

ठाकुर दास बंग

बुनियादी समस्याओं के हल न होने तथा राष्ट्र को सही दिशा न मिलने के कारण अपने विविध रूपों में हिंसा समाज के जीवन को घेरती जा रही है. ऐसा लगता है जैसे किसी समस्या का शांतिपूर्ण समाधान न समाज के पास है रह गया है, न सरकार के पास. जबकि सच्चाई यह है कि स्थाई समाधान शांति की ही शक्ति से संभव है. बढ़ती हुई सामाजिक हिंसा के कारण राज्य की हिंसा को शांति सुरक्षा और विभिन्न हितों की रक्षा के नाम में, व्यापक और नृशंस दमन का औचित्य और अवसर मिल जाता है. ऐसी स्थिति में आतंकित जनता का मनोबल टूटता है और वह राज्य सत्ता की नृशंसता को स्वीकार कर लेती है. इस स्थिति को तत्काल रोकना चाहिए, अन्यथा देश को अराजकता और निरंकुश शासन की चपेट में पड़ने से बचाना अत्यंत कठिन हो जाएगा.

ये लक्ष्य कैसे सधेंगे? ये तभी सधेंगे, जब केंद्रीय राज्य सत्ता के बढ़ते फौलादी पंजे रुकेंगे, जब राष्ट्र के पुनिर्माण का एक देशव्यापी, लोकशक्ति आधारित आंदोलन होगा. राष्ट्र के विकास में राज्य निर्माण का पर्व समाप्त हो चुका है, अब राष्ट्र निर्माण का नया पर्व प्रारम्भ होना चाहिए. राष्ट्र निर्माण में राज्य-सत्ता का कुछ क्षेत्रों में मुख्य स्थान होगा, लेकिन जहां तक दैनन्दिन जन जीवन का संबंध है, उसका रोल पूरक ही होना चाहिए, आज की तरह जनता के सीने पर सवार रहने का नहीं. राष्ट्र की शक्ति क्षीण होती जाये तो राज्य-सत्ता का भी दिनों दिन क्षय और पतन होना अनिवार्य है. आज हम राष्ट्र और राज्य दोनों की शक्ति का क्षय होते देख रहे हैं. इससे बड़ा संकट दूसरा क्या होगा? राष्ट्र का पुनर्निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है. एक-एक सीढ़ी ऊपर उठने की आरोहण की. इसके लिए, जैसा गांधी जी ने कहा था, गांव-गांव और नगर-नगर में बसी हुई जनता को संगठित होकर स्वराज्य के अपने जन्मसिद्ध अधिकार की घोषणा करनी पड़ेगी और उसका प्रयोग शुरू करना पड़ेगा. यह करके ही जनता अपने दैनन्दिन जीवन में राज्य-सत्ता के अनुचित हस्तक्षेप पर रोक लगा सकती है. राज्य-सत्ता को सीमित करने का लक्ष्य दूर की बात नहीं है, बल्कि पहले कदम में करने की चीज है. यदि हम राज्य-सत्ता के विष भरे प्रवाह से बचना चाहते हैं तो गांव और नगर में स्वायत्तता की ठोस दीवार खड़ी करना जरूरी है. इसी दृष्टि से हमारा आग्रह है कि सत्ता विकेंद्रित हो और जनता को सौंपी जाय. ताकि वह लोकतांत्रिक पद्धति से अपने सामान्य जीवन का नियमन और संचालन अपने निर्णय से कर सके, तथा अधिकारियों द्वारा अधिकार के दुरुपयोग से अपने को मुक्त रख सकें.

राष्ट्र का पुनर्निर्माण मुख्यत: उसके पांच लाख गांवों का पुनर्निर्माण है. हमारे गांव या नगर मात्र घरों के समूह नहीं हैं. वे इकाइयां हैं जिन्हें सदियों में विकसित परंपरा ने अस्मिता और चरित्र प्रदान किया है. ये लाखों गांव और नगर इकाई के रूप में संगठित रहकर ही केंद्रित सत्ता-राजनैतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दमन और शोषण से अपने हितों और अपने अस्तित्व की भी रक्षा कर सकते हैं.

राष्ट्र का पुनर्निर्माण मुख्यत: उसके पांच लाख गांवों का पुनर्निर्माण है. हमारे गांव या नगर मात्र घरों के समूह नहीं हैं. वे इकाइयां हैं जिन्हें सदियों में विकसित परंपरा ने अस्मिता और चरित्र प्रदान किया है. ये लाखों गांव और नगर इकाई के रूप में संगठित रहकर ही केंद्रित सत्ता-राजनैतिक, आर्थिक और प्रशासनिक के दमन और शोषण से अपने हितों, हितों ही नहीं, अपने अस्तित्व की भी रक्षा कर सकते हैं. आज गांव के जीवन में दरारें अनेक हैं, लेकिन वे पाटी जा सकती है. बशर्ते दरिद्रीकरण की प्रक्रियाएं समाप्त हों और समाज विरोधी तत्वों को पुलिस, कानून और विकास की योजनाओं आदि के द्वारा राज्य-सत्ता का प्रश्रय मिलना बंद हो जाय. शोषण और दमन के तत्वों का किसी-न-किसी रूप में सरकार और बाजार के साथ गठबंधन है. यह गंठबंधन तभी टूटेगा, जब गांव एक होकर अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए खड़ा होगा तथा खेती-उद्योग पशु पालन के आधार पर एक नई, एग्रो-इंडस्ट्रियल, ग्रामीण, सहकारी अर्थ-नीति विकसित करेगा. जिसमें गांव का हर व्यक्ति उत्पादक भी होगा और उपभोक्ता भी. ऐसी ठोस अर्थनीति की, जिसमें सब ग्रामवासियों की बुनियादी आवश्यकताओं पर सबसे पहले ध्यान देना होगा, नींव पर गांव का स्वायत्त, स्वाश्रयी सह-जीवन विकसित होगा. जीवन की ऐसी रचना कैसे चलेगी और क्यों चलने दी जाएगी, जिसमें परिवार में स्त्री को, उत्पादन में श्रमिक को, समाज में हरिजन को विवशता का जीवन बिताना पड़े? गांव के पुनर्निर्माण का अर्थ है नए संबंधों, नए साधनों और नए संगठनों का विकास-एक नई जीवन पद्धति का विकास. इस दिशा में गांवों के पुनर्निर्माण के अभियान का शुभारम्भ करना है. इस अभियान को राष्ट्र के पुनर्निर्माण के देशव्यापी आंदोलन के बुनियादी अंग के रूप में चलाना पड़ेगा तभी इसमें गति आएगी और इसकी दिशा स्पष्ट होगी. गांव में खेतिहर हैं, मजदूर हैं, दस्तकार हैं. आज इनके हित भिन्न ही नहीं, परस्पर-विरोधी दिखाई देते हैं, लेकिन सीलिंग और परोक्ष स्वामित्व के प्रश्नों को जो विवाद से परे हैं, अलग रख दें, तो इन तीनों के हित मूलत: समान हैं और गांव सहकारी अर्थनीति में तीनों के लिए तुल्य पारिश्रमिक और समान संरक्षण के लिए पूरा स्थान है. आज तो स्थिति ऐसी है कि बाजार की शोषणमूलक अर्थनीति में खेतिहर को उसके अन्न या कच्चे माल का उचित मूल्य नहीं मिलता, मजदूर को मेहनत की उचित मजदूरी नहीं मिलती और दस्तकार के बनाए माल का उचित दाम नहीं मिलता. उचित दाम की बात अलग, तीनों में किसी को सालभर काम नहीं मिलता, इसके अलावा ग्राहक को बिचौलिए की मुनाफाखोरी के कारण उचित से कहीं अधिक दाम देना पड़ता है. उत्पादकों और ग्राहकों के शोषण की यह दारुण स्थिति कब तक चलेगी और इसके चलते क्या परिवर्तन होगा, कैसे होगा? इसलिए गांव की मुक्ति लड़ाई का एक जबरदस्त मोर्चा उचित मूल्य का प्रश्न बन सकता है और बनना चाहिए. इसके लिए परिस्थिति परिपक्व है. ■

feedback@chauthiduniya.com

जीवन की ऐसी रचना कैसे चलेगी और क्यों चलने दी जाएगी, जिसमें परिवार में स्त्री को, उत्पादन में श्रमिक को, समाज में हरिजन को विवशता का जीवन बिताना पड़े? गांव के पुनर्निर्माण का अर्थ है नए संबंधों, नए साधनों और नए संगठनों का विकास-एक नई जीवन पद्धति का विकास. इस दिशा में गांवों के पुनर्निर्माण के अभियान का शुभारम्भ करना है. इस अभियान को राष्ट्र के पुनर्निर्माण के देशव्यापी आंदोलन के बुनियादी अंग के रूप में चलाना पड़ेगा तभी इसमें गति आएगी और इसकी दिशा स्पष्ट होगी.

पाठकों की दुनिया

आज के हालात

देश का एक आदमी यह बता सकता है कि कौन अफसर किस नेता की राह पर चलता है. हमारे यहां अफसरशाही का एक हिस्सा राजनीतिक दलों में साफ-साफ बंटा नजर आता है. कोई राज्यसभा में जाने के लालच में अपने आकाओं के हितों के लिए जनता के हितों को सूली पर चढ़ा रहा है, तो कोई बेहतर पोस्टिंग के लिए. वैसे एक असलियत यह भी है कि यदि कोई अफसर नेताओं की राह पर नहीं चलता तो उसे हटाने के लिए सभी हथकंडे अपनाए जाते हैं. देश गरीबी की कैद में है और गरीब फाइलों के कैद में है. फाइलें अफसरों के कैद में है अफसर नेताओं के कैद में हैं. नेता न किसी के कैद में है न रहेंगे. शायद लोकतंत्र की यही उल्टी परिभाषा रचने में राजनीति काफी हद तक कामयाब हो गई है. महात्मा गांधी ने कहा-जहां समाज सोया हुआ, आलसी, बेफिक्र, या स्वार्थी है, वहां पर दम्भी-लुच्चे मनमानी करने लगते हैं. लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की बदौलत ही आज की दुनिया इतनी तरक्की कर सकी है. बावजूद इसके अगर भारतीय लोकतंत्र की सफलता की बात की जाय तो सबसे पहले समाज के विभिन्न वर्गों की तरक्की की पड़ताल करनी होगी. लोकतांत्रिक मूल्य व्यवहारिक रूप से कितने असरदार साबित हुए हैं, यह विचार का विषय है. लोकतंत्र की पूर्ण सफलता सुनिश्चित होना अभी बाकी है.

अशोक निर्मोही, *दरभंगा*

अन्ना ने जीती जंग

आखिरकार अन्ना ने अपनी जनलोकपाल की जंग जीत ही ली. यह वो जंग थी जिसके लिए अन्ना ने रामलीला मैदान में13 दिन का उपवास किया, जिसका गवाह पूरा भारत और दिल्ली के रामलीला मैदान की जनता बनी थी. इसके बाद अन्ना ने 28 हजार किलोमीटर की यात्रा की. सरकार केवल अन्ना को आश्वासन पर आश्वासन देती रही. इसमें दो वर्ष से भी अधिक का समय बीत गया, लेकिन जब अन्ना ने अपने गांव रालेगण सिद्धी में फिर से अनशन शुरू किया तो सरकार भी सकते में पड़ गई तथा कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे राज्यसभा में जल्दी-से-जल्दी पास करवाने का आश्वासन दिया और आखिरकार 17 दिसंबर को यह बिल राज्यसभा में पास हुआ. अन्ना के गांव रालेगण सिद्धी में हजारों कार्यकर्ता खुशी से झूमने-नाचने लगे. आखिरकार अन्ना व पूरे भारतवासियों ने इस जन-लोकपाल बिल के पास होते ही राहत की सांस ली तथा अन्ना ने भी इस बिल का समर्थन किया. आखिरकार अन्ना ने अपनी जिद के आगे सरकार को झुका ही दिया तथा राहुल गांधी ने जनलोकपाल बिल पास होने का श्रेय अन्ना हजारे को दिया.

राजीव कुमार, *बीकानेर*

शारीरिक और मानसिक शोषण

बीते कुछ अर्से से देश में ऐसी घटनांए घटीं हैं, जिसने लोंगो को शर्मिंदा किया है. जैसे तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के अपने साथी महिला पत्रकार के साथ यौन उत्पीड़न का मामला. ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की खामियां अत्याचार और शोषण को बढ़ावा दे रहीं हैं. व्यक्तिवादी वर्चस्व बढ़ता जा रहा है. रसूख वाले लोग पद के नशे में चूर होकर अपने से नीचे लोगों पर हुकुम ही नहीं चला रहे हैं उनका शारीरिक और मानसिक शोषण भी कर रहे हैं. एक सासंद के घर में भी नौकरानी को पीट-पीट कर मार डाला गया. आसाराम बापू और उनके बेटे पर भी यौन शोषण का आरोप है. ये तथाकथित लोग खुद अपनी कमियां और कुंठाओं से बाहर निकल नहीं पाए हैं. दूसरों की बखिया उधेड़ने वाले और समाज में पाक-साफ छवि लेकर चलने वाले लोग आज खूद कानून के शिकंजे में फंस रहे हैं. लोकतंत्र में भी कमजोर और मजबूत, मालिक और नौकर की स्पष्ट विभाजित रेखा है. इसके रहते सामाजिक गतिरोध दूर नहीं किया जा सकता.

विकास कुमार पाटनी, *कोडरमा*

भ्रष्टाचार पर एक सोच

पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम ने कहा था कि भ्रष्टाचार को कोई कानून समाप्त नहीं कर सकता. इसको केवल तीन लोग समाप्त कर सकते हैं. मां-बाप और प्राथमिक शिक्षक. उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप अपने बच्चों को भ्रष्टाचार से कमाए धन से पालते हैं तो वे मन ही मन आप पर हंसते हैं. वे सब समझते हैं. आपके पितृत्व का मुखौटा इतना हल्का होता है कि बच्चों की आपके प्रति घृणा छिप नहीं सकती. यदि इस समस्या को मिलने वाली सामाजिक स्वीकृति खत्म हो जाए तो अपने आप ही यह दम तोड़ देगा. आज सुविधाभोगी मानसिकता से भरे नेतृत्व के प्रति समाज का भाव धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है. कथनी करनी का भेद नेतृत्व के प्रति आस्था को क्षीण करता है. कैसे मुमकिन है कि प्रजातंत्र की प्रजा दिनों-दिन निर्धन होती जाए और उसका तंत्र करोड़ो में खेलें. दिल्ली में कांग्रेस भ्रष्टाचार की वजह से हारी है यह सर्वविदित है. लोकतंत्र देखने, सुनने, समझने और महसूस करने में जितना आदर्श और प्रेरक लगता है, इतना ही नहीं. लोकतंत्र में शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों की शुचिता, नैतिकता, चरित्र, निष्ठा और जवाबदेही में आए क्षरण का असर सबसे निचले स्तर तक देखा जा सकता है. इकोनॉमिक्स इंटेलीजेंस यूनिट द्वारा हर वर्ष तैयार किए जाने वाले लोकतंत्र सूचकांक में हमे ऐसे देशों के साथ शामिल किया गया है, जहां पूर्ण लोकतंत्र नहीं हैं. कारण स्पष्ट है भ्रष्टाचार. हर वर्ष जारी किए जाने वाले भ्रष्टाचार सूचकांक में हम निचले पायदान पर जगह बनाते रहे हैं. सोचना हमें है हम देश से हैं, देश हमसे नहीं.

गौरव निर्मोही, *दरभंगा*

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

इस दौर में सजग रहना ज़रूरी है

अब स्टिंग ऑपरेशन के नए पात्रों के बारे में जानिए. मेरे पास एक फोन आता है. फोन करने वाला व्यक्ति ख़ुद को ओडिशा का इंडस्ट्री मिनिस्टर बद्री पात्रा बताता है और कहता है कि हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं. इसके बाद वह व्यक्ति कहता है कि आपने अन्ना हजारे जी का बहुत साथ दिया और अन्ना जी के अनशन के बाद जिस तरह से लोकपाल बिल पास हुआ और उसमें आपने जो भूमिका निभाई उसे लेकर हम सब आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं. उसने फिर दोहराया कि नवीन जी आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं. मैंने कहा, लोकपाल बिल तो सांसदों के माध्यम से पास हुआ. इसमें ससंद की भूमिका है, मेरा क्या रोल है? मैंने कहा, रही बात नवीन पटनायक जी से बात करने की, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उनसे बात करूंगा. तब उस व्यक्ति ने कहा कि नवीन पटनायक जी जनरल वी. के. सिंह से बात करना चाहते हैं. मैंने कहा कि तो फिर आप जनरल वी. के. सिंह को फोन करिए. इस पर उन महाशय ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि आप अगर जनरल साहब को फोन करके यह संदेश दे देते कि नवीन पटनायक किसी व्यक्तिगत काम के लिए उनसे बात करना चाहते हैं तो बेहतर रहता. मैंने कहा कि ठीक है अगर नवीन पटनायक को जनरल वी. के. सिंह से व्यक्तिगत काम है तो मैं उनसे कह दूंगा.

मैंने जनरल वी. के. सिंह को फोन लगाया. वी. के. सिंह जी उस समय श्री श्री रविशंकर के पास बेंगलुरु में थे. मैंने जनरल साहब से कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का आपसे कोई व्यक्तिगत काम है, वह आपसे बात करना चाहते हैं. ओडिशा के उद्योग मंत्री ने मुझे फोन करके यह कहा है कि मुख्यमंत्री जी को कोई बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए वे चाहते हैं कि आप उन्हें फोन कर लें. अब तक मेरे दिमाग़ में कोई संशय नहीं आया था. रात के आठ बजे दोबारा उस व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा कि मैं ओडिशा का उद्योग मंत्री बद्री पात्रा बोल रहा हूं, लीजिए नवीन पटनायक साहब से बात करिए. पटनायक साहब ने मुझसे कहा कि संतोष जी, लोकपाल के लिए आपने जो रोल प्ले किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई. हम लोग लोकपाल के पक्ष में हैं. फिर उन्होंने कहा कि मेरा एक व्यक्तिगत काम जनरल वी. के. सिंह से है. मैंने कहा कि आप बताएं क्या काम है, अगर हम लोग कुछ मदद कर सकते हों तो? उन्होंने कहा कि मेरे एक रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है आंध्र प्रदेश में और वहां पर समझौते की बात करनी है. मैं ख़ुद कोई बात नहीं कर सकता. जनरल वी. के. सिंह बड़े आदमी हैं. अगर उनका कोई आदमी वहां हो तो वो समझौते की बात कर लें और अगर कोई लेन-देन का मसला हो तो वो भी कराया जा सकता है, पर इस केस को दबाना है. यहां से मेरा माथा ठनका. मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी आपके पास लोग हैं. आप चाहें तो उन्हें भेज सकते हैं. उधर से जवाब मिला कि नहीं, मैं भेज सकता तो ज़रूर भेजता. किरण कुमार रेड्डी से मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते या मैं उन्हें पसंद नहीं करता, इसलिए मैं चाहता हूं कि जनरल वी. के. सिंह जी इस काम को करवा दें. मैंने कहा, मैंने बद्री पात्रा जी को उनका नंबर दे दिया है आप सीधे जनरल साहब से ही बात कर लीजिए.

पहला संशय तो यह था कि एक मुख्यमंत्री बिना-जान पहचान के संतोष भारतीय के माध्यम से जनरल वी. के. सिंह से क्यों संपर्क करना चाह रहा है. और दूसरा नवीन पटनायक की जो आवाज़ मैंने टीवी पर सुनी है, वह मैंने कभी हिंदी में नहीं सुनी है. वह अंग्रेज़ी में सुनी है या उड़िया में सुनी है. नवीन पटनायक की आदत हिंदी में बात करने की नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति मुझसे नवीन पटनायक बनकर बात कर रहा था, वह शुद्ध हिंदी में बात कर रहा था, भले ही वह उड़िया हिंदी थी.

मैंने फौरन वी. के. सिंह साहब को फोन किया और कहा कि जनरल साहब आप उन लोगों से लैंडलाइन पर फोन करने को कहिएगा, क्योंकि मुझे यह कोई फ्रॉड लग रहा है. शायद यह कोई ट्रैप है, जिसमें वह कुछ भी पूछकर फंसाना चाहता है. यह ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नहीं है. जनरल साहब ने कहा कि बिल्कुल! अगर फोन आता है तो मैं यही कहूंगा. जनरल साहब ने कहा और फिर मेरा इससे क्या वास्ता? मैं तो साधारण आदमी हूं, आंध्र से मेरा क्या लेना-देना? उसके बाद फिर उस व्यक्ति का फोन आता है जो ख़ुद को ओडिशा का उद्योग मंत्री बताता है. उसने कहा कि चलिए कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हो सकता तो बहुत सारे ठेकेदार हैं, जो मंत्रालय के माध्यम से जुड़े हैं. मैं उनसे इस काम को कराता हूं. मैंने कहा कि आप जिससे भी चाहते हों, अपना काम कराएं और हम लोग तो दिल्ली में हैं, साधारण लोग हैं.

सवाल यह खड़ा होता है कि यह कौन लोग कर रहे हैं और उन्होंने क्यों एक एक्सीडेंट के समझौते में काम आने के लिए मेरे ज़रिए जनरल वी. के. सिंह से बातचीत करनी चाही. शायद ये लोग जनरल वी. के. सिंह का और मेरी आवाज़ का नमूना लेना चाहते थे. आवाज़ का नमूना लेने के बाद आप उस आवाज़ में किसी अच्छे आर्टिस्ट या कंप्यूटर के ज़रिए से इस आवाज़ को किसी भी बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं. या इसके पीछे कोई और भी उद्देश्य हो सकता है, जो मुझे समझ में नहीं आया. इसके बाद मैंने अपने ओडिशा संवाददाता से बद्री पात्रा का नंबर मांगा, तो पता चला कि बद्री पात्रा ओडिशा के इंडस्ट्रिएल मिनिस्टर न होकर उच्च शिक्षा मंत्री हैं. जब मैंने उन्हें फोन किया तो उधर से एक बुजुर्ग आवाज़ आई. जबकि पहले जो आवाज़ थी वह किसी जवान व्यक्ति की आवाज़ थी. मैंने बद्री पात्रा से कहा कि मैं संतोष भारतीय बोल रहा हूं तो उन्होंने कहा कि हां, बताइए. मैंने पूछा, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे शायद बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर भी आप मुझे बताइए अगर कोई बात हो तो. मैंने कहा कि नहीं, फ़िलहाल तो कोई बात नहीं, अगर होगी तो मैं आपको फोन करूंगा. मैंने फिर से अपने ओडिशा संवाददाता को फोन किया और कहा कि आप इस नंबर पर फोन करके पता करिए कि यह कौन है. जब मेरे संवाददाता ने फोन किया तो उधर से थोड़े सख़्त लहजे में जवाब मिला और जब संवाददाता ने पता लगाया कि यह कहां का फोन है तो पता चला कि यह फोन गोवा में रजिस्टर है और दिगंबर कामत के नाम पर है. दिगंबर कामत गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं.

इस घटना ने मुझे थोड़ा चिंतित कर दिया. मुझे यह लगा कि स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर या तो इंटेलीजेंस एजेंसीज या हिंदुस्तान के वो लोग जो पत्रकारिता को या जनरल वी. के. सिंह को बदनाम करना चाहते हैं, उनकी यह सोची-समझी साज़िश है. दरअसल, यह कोशिश आवाज़ का नमूना लेने की थी, इसमें कोई संदेह नहीं. इससे एक सीख़ मिलती है कि आप से अगर कोई फोन करके कहता है कि मैं अमुक व्यक्ति बोल रहा हूं, जिससे सामान्यत: आपकी बातचीत न होती हो, तो उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और उस फोन को किसी और व्यक्ति से सत्यापित करवा लेना चाहिए. पिछले दिनों देश में स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर बहुत सारी भड़ैंती हुई है और अब एक नए तरह का स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है ताकि जनरल वी. के. सिंह या फिर मैं सवालों के घेरे में आ जाएं.

कौन लोग हो सकते हैं? या तो हथियारों के दलालों की लॉबी है जो जनरल वी. के. सिंह की सारी इज़्ज़त के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करना चाहती है या फिर पत्रकारिता में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो पीआर जर्नलिज्म करते हैं और जो लोग अंग्रेजी कहावत मोर लॉयल दैन किंग के आधार पर कुछ न कुछ उन लोगों के हित में खड़े दिखाई देते हैं जो सही पत्रकारिता को पसंद नहीं करते और तीसरे शायद इंटेलीजेंस एजेंसीज़ हो सकती हैं जो हम लोगों के फोन दिन-रात टेप कर रही हैं. इसको देखकर मुझे यह चिंता होती है कि निकट भविष्य में कुछ ऐसा होगा जो पुन: इज़्ज़त के ऊपर कीचड़ फेंकने जैसा होगा. मैं यह नहीं मानता कि इसमें किसी विदेशी एजेंसी का हाथ हो सकता है, लेकिन मेरा यह मानना ज़रूर है कि किसी न किसी एजेंसी ने कुछ लोगों को हायर किया है ताकि वो जनरल वी. के. सिंह और मेरे ख़िलाफ़ एक बड़ी साज़िश रच सकें और उस साज़िश में हमें फंसा सकें. पर सच्चाई, सच्चाई रहती है. मैं ख़ुद तो कोई एफआईआर नहीं करा रहा हूं, लेकिन इस प्रकरण को सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूं, ताकि अगर कोई एजेंसी इस पर नोटिस ले तो मेरे पास वह नंबर मौजूद है, जिस नंबर पर मेरी बातचीत उस व्यक्ति से हुई थी. जनरल वी. के. सिंह के पास भी वह नंबर मौजूद है, जिससे उस व्यक्ति ने इंडस्ट्री मिनिस्टर बनकर बात की थी. हम जानते हैं कि इंटेलीजेंस एजेंसी के पास जनरल वी. के. सिंह या मेरे ख़िलाफ़ होने वाले किसी षडयंत्र के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण काम में उलझे हुए हैं. पर हम अपना कर्त्तव्य इस समूचे प्रकरण को पाठकों के सामने लाकर पूरा करने की दिशा में एक क़दम तो उठा रहे ही हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

दो औरतों की कहानी

कई सेनानिवृत्त अधिकारियों के बयानों पर ग़ौर किया जाए तो यह बात सामने आती है कि भारतीय सरकार वीज़ा आवेदनों में होने वाली इस हेराफेरी से वाक़िफ़ होती है. यह भी बात सामने आती है कि सरकार अपने अधिकारियों को उस तरह की जीवनशैली विदेशों में दे पाने नाकाम रही है जैसी कि वे अपने देश में जीते हैं.

देवयानी खोबरागड़े को गिरफ़्तार किए जाने को लेकर भारत ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी. एक सुरक्षित रास्ता अख़्तियार करते हुए भारतीय सरकार और नौकरशाह अमेरिका के ख़िलाफ़ लगभग युद्ध छेड़ने को तैयार हो गए थे. पहले भी हुए इसी तरह के कई अपमानों की लंबी फ़ेहरिस्त भी उनके साथ थी. बीते समय में राजदूत रह चुके कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं समाचार चैनलों पर भी दीं. भारत ने तीखी प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकी राजनयिकों के अधिकारों और सुविधाओं पर अंकुश लगा दिया था.

लेकिन यह सब किसके लिए किया गया? एक ऐसी महिला के लिए जो दूतावास में तैनात है और जिसपर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लगे हैं. अमेरिकी अधिकारियों यह कार्रवाई देवयानी की नौकरानी की तन्ख़्वाह और उसके साथ बर्ताव को लेकर की गई थी. वह भी एक भारतीय महिला ही है. देवयानी के बचाव के चक्कर में हम संगीता रिचर्ड को भूल ही गए. यह बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि देवयानी एक आईएफएस अधिकारी हैं और संगीता एक घरेलू नौकर. न्यूयॉर्क में रहने वाली एक अकेली भारतीय नौकरानी के पास आख़िर कितने अधिकार हो भी सकते हैं? उसे इस बात के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि उसे देवयानी के घर में काम करने का मौक़ा मिला. उसे वहां काम करने के लिए रहने और खाने के अलावा 30,000 रुपये बच्चों की देखभाल के लिए भी मिलते थे.

लेकिन वास्तविक स्थिति पूरी तरह अलग है. मामले में अमेरिकी क़ानूनी दस्तावेज़ों के मुताबिक़, संगीता को सप्ताह में 40 घंटे काम करने के लिए 30,000 रुपये दिए जाते थे, मगर वीज़ा एप्लिकेशन में संगीता का वेतन 575 डॉलर यानी कि 30,000 रुपये की बजाए 45,00 डॉलर दिखाया गया था. संगीता को इस बात की ताक़ीद की गई थी कि वह वीज़ा में अपने वेतन के बारे में झूठ बोले. इस तरह देवयानी ने जानबूझकर एक आधिकारिक दस्तावेज़ में हेराफरी की. इसके अलावा सिर्फ़ 3.31 डॉलर प्रति घंटे के काम लिए देना अमेरिका में न्यूनतम मज़दूरी से भी कम है. इस तरह जो वेतन संगीता को दिया जा रहा था, वह वीजा में बताए गए वेतन से सात गुना कम था. अब सिर्फ़ इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह वेतन न्यूनतम मज़दूरी से भी कितना कम था.

इस मामले में अमेरिकी क़ानूनी दस्तावेज़ों को पढ़े जाने की ज़रूरत है. यह बहुत विस्तृत रूप में इसकी जानकारी देता है. इस मामले में यह बात भी ग़ौर करने वाली है कि देवयानी को 15 साल तक के कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है. किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम मज़दूरी से भी कम वेतन देना एक अपराध है. इस मामले में एक भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन एक आईएफएस अधिकारी के द्वारा ही किया गया है. संसद में किसी ने भी इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला. ऐसा हो सकता है कि देवयानी दलित जाति की हों (हालांकि क्रीमी लेयर के नियमों के मुताबिक़ ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास मुंबई में आदर्श कॉम्प्लेक्स में फ्लैट है) लेकिन संगीता भी आदिवासी हैं. यहां दोनों के अधिकारों को लेकर बात की जानी चाहिए थी.

अमेरिकी मार्शल सर्विस के अधिकारी लोगों के साथ बेहतर व्यवहार के लिए नहीं जाने जाते, विशेष रूप से उन मामलों में जब वे किसी को गिरफ़्तार करने जा रहे हों. वे जब किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो उसे अपराधी ही मानते हैं. दस्तावज़ों के मुताबिक़, अमेरिकी अधिकारी देवयानी के राजनयिक होने के बारे में जानते थे, लेकिन देवयानी के अपराधों को देखकर उन्होंने इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया.

अमेरिकी मार्शल सर्विस के अधिकारी लोगों के साथ बेहतर व्यवहार के लिए नहीं जाने जाते, विशेष रूप से उन मामलों में जब वे किसी को गिरफ़्तार करने जा रहे हों. वे जब किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो उसे अपराधी ही मानते हैं. दस्तावज़ों के मुताबिक़, अमेरिकी अधिकारी देवयानी के राजनयिक होने के बारे में जानते थे, लेकिन देवयानी के अपराधों को देखकर उन्होंने इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया. लेकिन अधिकारियों को देवयानी की निर्वस्त्र कर जांच नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया था, जिसमें हिंसा की गई हो. उनके पास कोई हथियार भी नहीं था. इसके अलावा देवयानी के द्वारा ड्रग के इस्तेमाल के भी कोई सुबूत नहीं मिले हैं. इस मामले में गिरफ़्तार करने और जांच करने के तरीक़े पर माफ़ी मांगी जानी चाहिए, इस बात को लेकर नहीं कि उन्होंने जो ग़लती की है, उसपर कोई केस न चलाया जाए.

इस मामले में सीखने वाली बात यह कि इससे पहले कि पूरा सिस्टम ख़ुद को सही साबित करने वाली हिस्टीरिया से पीड़ित हो जाए, हमें यह पूछना चाहिए कि आख़िर इस पूरे प्रकरण में कुछ ख़ास बात है या नहीं. कई सेनानिवृत्त अधिकारियों के बयानों पर ग़ौर किया जाए तो यह बात सामने आती है कि भारतीय सरकार वीज़ा आवेदनों में होने वाली इस हेराफेरी से वाक़िफ़ होती है. यह भी बात सामने आती है कि सरकार अपने अधिकारियों को उस तरह की जीवनशैली विदेशों में दे पाने नाकाम रही है जैसी कि वे अपने देश में जीते हैं. अगर न्यूयॉर्क में घरेलू नौकर रखना दिल्ली से सात गुना महंगा है, तो सरकार को अपने अधिकारियों को यह बताना चाहिए कि वे घरेलू नौकर की सुविधा के बिना रहें, जैसा कि ज्यादातर अमेरिकी करते हैं.

मामले में भारत का जो रुख़ था, वह अपनी शक्ति के प्रदर्शन को लेकर नहीं, बल्कि एक तरह के चिड़चिड़ेपन में लिया गया था. जब खोबरागड़े का तबादला संयुक्त राष्ट्र में कर दिया गया, तब सरकार ने उसकी ग़लती मानी. लेकिन अभी संगीता जैसी कई और घरेलू नौकरों के साथ अधिकारियों द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, उसे सुलझाया जाना अभी भी बाक़ी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सूचना का अधिकार ज़रूरी है

चौथी दुनिया ब्यूरो

सूचना क़ानून को लागू हुए क़रीब पांच साल हो गए. इस दौरान सूचना क़ानून ने आम आदमी को कितना शक्तिशाली बनाया, आम आदमी कैसे सवाल पूछकर व्यवस्था में लगी दशकों पुरानी जंग छुड़ाने में सफल रहा, अपने अधिकार को पाने में सफल रहा आदि बिंदुओं से जुड़े चंद उदाहरण इस अंक में दिए जा रहे हैं, ताकि आप सभी सूचना क़ानून की ताक़त को जान सकें और इसके इस्तेमाल के लिए दूसरों को भी प्रेरित कर सकें.

बिना रिश्वत नौकरी

आरटीआई अब लोगों को बिना रिश्वत दिए नौकरी और प्रमोशन भी दिला रहा है. रेवाड़ी की सपना यादव ने गुड़गांव ग्रामीण बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी पद के लिए आवेदन किया था. चयन नहीं हो पाया तो आरटीआई के तहत सपना ने चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे. मामला सीआईसी गया, बैंक ने सूचना तो उपलब्ध नहीं कराई, अलबत्ता सपना को फोन कर प्रोबेशनरी अधिकारी के तौर पर बैंक ज्वाइन करने का अनुरोध ज़रूर किया. बिहार के मधुबनी ज़िले के चंद्रशेखर ने जब पंचायत शिक्षक नियुक्ति के लिए घूस नहीं दी तो उन्हें यह कहकर नियुक्त नहीं किया गया कि जिस महाविद्यालय से उन्होंने प्रशिक्षण हासिल किया है, वह फ़र्ज़ी है. जबकि उसी महाविद्यालय से प्रशिक्षित अन्य लोगों की नियुक्ति कर दी गई. चंद्रशेखर ने जब प्रखंड विकास अधिकारी से इस मामले में सवाल किए तो उनकी नियुक्ति पंचायत शिक्षक के रूप में कर दी गई. उड़ीसा वन विकास निगम में सेक्शनल सुपरवाइज़र के पद पर कार्यरत गणपति बहरा को वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन नहीं दिया गया, जबकि उनके कनिष्ठों को प्रमोशन दे दिया गया. इस संबंध में आरटीआई आवेदन डालने पर उन्हें सेक्शनल सुपरवाइज़र से सब डिवीज़न मैनेजर के पद पर प्रमोट कर दिया गया.

पेंशन की टेंशन नहीं

बुज़ुर्गों के लिए भी आरटीआई जादू की छड़ी साबित हुआ है. उड़ीसा की 70 वर्षीय कनकलता त्रिपाठी की 13 सालों से लटकी पेंशन आरटीआई आवेदन डालने के बाद एक महीने में ही मिल गई. बिहार के मधुबनी ज़िले की गंगापुर पंचायत के 200 पेंशनार्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने के लिए उप डाकघर में खाता खुलवाने हेतु महीनों चक्कर लगाते रहे. आरटीआई के तहत लोगों ने आरटीआई आवेदन डालकर मधुबनी के डाक अधीक्षक से इस बारे में सवाल पूछे. डाक अधीक्षक ने मामले की जांच की. दोषी पोस्टमास्टर गणेश सिंह को तत्काल निलंबित करते हुए सभी पेंशनधारियों का खाता दूसरे डाकघर में खुलवा दिया गया.

राशन दुकानदारों की ख़बर

राशन चोरी और राशनकार्ड न बनना, ये दो समस्याएं हमारे देश में आम हैं, लेकिन जन वितरण प्रणाली में लगे घुन को भी आरटीआई ने धीरे-धीरे साफ़ किया है. दिल्ली में तो इसके सैकड़ों उदाहरण हैं. पुरी की अनासारा गांव की 68 वर्षीय जनातुन बेगम और उनके पति को अंत्योदय योजना के तहत मिलने वाला अनाज आरटीआई की वजह से दोबारा मिलने लगा. जहानाबाद ज़िले के कताई बिगहा गांव में ग्रामीणों को सही मात्रा में राशन और मिट्टी का तेल मिलने लगा है.

मिड डे मील में सुधार

अहमदाबाद में मिड डे मील योजना के तहत स्कूली बच्चों को दोयम दर्जे का भोजन मिलता था. भोजन में कई बार तो कीड़े भी पाए गए. भोजन की गुणवत्ता की जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी. इस मामले में इंदुपुरी गोसाई ने आरटीआई के तहत

जवाब-तलब किया तो न केवल लेबोरेट्री में भोजन की जांच हुई, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी सुधरी और निगरानी की समुचित व्यवस्था हुई. यह सब एक सप्ताह के भीतर हो गया. इस तरह के अनेक मामले सामने आए हैं, जिनमें आरटीआई की बदौलत मिड डे मील व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हो सका है.

पब्लिक स्कूल में एडमिशन

सूचना क़ानून का ही कमाल है कि दिल्ली की पुनर्वास बस्ती सुंदर नगरी में रहने वाला मोहन अब अर्वाचीन पब्लिक स्कूल में पढ़ता है. आरटीआई की बदौलत ही मोहन का दाखिला इस स्कूल में फ्रीशिप कोटे के तहत हो पाया है. दिल्ली में इस तरह के हज़ारों उदाहरण हैं. कल्याणपुरी में रहने वाली सुनीता ने तो सूचना के अधिकार का सहारा लेकर स्कूल की सभी छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाई. सुनीता ने आरटीआई के तहत छात्रवृत्ति न मिलने का कारण पूछा. दो दिनों बाद ही अधिकारी स्कूल में इस संबंध में जांच करने आए. सुनीता ने बेबाकी से प्रिंसिपल की शिक़ायत की. इसके कुछ दिनों बाद स्कूल की सभी छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित कर दी गई. इसी तरह हरियाणा के सोनीपत ज़िले के सिलरपुर मेहता गांव की साठ वर्षीय सुमित्रा देवी ने आरटीआई की मदद से न सिर्फ़ प्रशासन की लापरवाही उजागर की, बल्कि ग़रीब स्कूली लड़कियों के लिए साइकिल वितरण की सरकारी योजना और सर्वशिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली स्कूल ड्रेस का लाभ भी छात्र-छात्राओं को पहुंचाया.

सड़क भी बनवाता है आरटीआई

देश के कई हिस्सों में सूचना के अधिकार ने सड़क निर्माण और मरम्मत में अहम भूमिका निभाई है. दिल्ली के मॉडल टाउन में रहने वाले मोहित अपने इलाक़े की सड़कों की दुर्दशा से परेशान थे. दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर डालने के लिए उनके घर के आगे सड़क खोद दी थी. एमसीडी से इसी लापरवाही का जवाब मांगने के लिए मोहित ने आरटीआई दायर दी. आरटीआई की अर्जी आते ही एमसीडी हरकत में आया और सड़क मरम्मत का कार्य एक महीने से भी कम समय में संपन्न हो गया. उड़ीसा में भी ऐसी ही एक मिसाल देखी गई. पुरी ज़िले के कोणार्क क्षेत्र के करमंगा गांव में आरटीआई की बदौलत रातोंरात सड़क बनवा दी गई.

पहले फेल, फिर पास

मलयनाथ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे. परीक्षा में फेल होने पर उन्होंने आरटीआई के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन से अपनी उत्तर पुस्तिका दिखाने की मांग की. उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच की गई तो पता चला कि वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)

आपको प्रत्येक जगहों से खुशी की खबर प्राप्त होगी. इस सप्ताह कोई भी निवेश सोच समझ कर करें. सामाजिक और पारिवारिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. क्रोध में आकर कोई कार्य न करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें. नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों लोग अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)

आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी. किसी जरूरत मंद की मदद करेंगे. व्यापारी वर्ग आर्थिक दृष्टि से खुश रहेंगे और नए कार्यों की तलाश में सफल होंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. इस सप्ताह नए मित्र बनेंगे जो आपके लिए मददगार साबित होंगे.

मिथुन (21 मई से 20 जून)

अपने कार्यस्थल पर किसी भी विवाद में न पड़े. जमीन-जायदाद या वाहन खरीदने की संभावना है. परिवार और कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाकर रखें. संतान सुख अच्छा रहेगा.आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों को चिंता हो सकती है, लेकिन व्यापरी खुश रहेंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)

यह आपके लिए सफलताओं वाला सप्ताह रहेगा. आप नए कार्य कर अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कोई खास योजना पूरी होगी. कठिनाईयों के बावजूद आपको धन कमी नहीं होगी. संतान को लेकर चिंता रहेगी. नए अतिथियों का आगमन हो सकता है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)

व्यवसाय में उतार चढाव महसूस करेंगे. जमीन जायदाद खरीदने की योजना बनेगी. अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है. खान-पान में सावधानी बरतें नहीं तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है. आर्थिक रूप से कुल मिलाकर समय अच्छा रहेगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)

मित्रों के कारण आपको फायदा होगा. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. किसी कार्य के पूरा होने पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. विद्यार्थी को प्रतियोगी परिक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी. इस सप्ताह किसी पर विश्वास न करें और न ही कोई निर्णय लें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)

शुभ समाचार प्राप्त होगा और पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा. व्यापारी अपने व्यापार को लेकर चिंतित होंगे. दौड़-भाग रहेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. विद्यार्थी को पढ़ाई के कारण तनाव हो सकता है. लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)

नौकरीपेशा लोगों की दौड़-भाग बढ़ेगी और मेहनत ज्यादा करनी होगी. आर्थिक दृष्टिकोण से आप खर्चे को लेकर चिंतित रहेंगे. विद्यार्थी के लिए समय अच्छा रहेगा. आप क्रोध पर नियंत्रण रखें अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है. व्यापारी नई साझेदारी कर सकते हैं. विद्यार्थी की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)

शत्रु हावी रहेंगे परेशान न हों. नोकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा. आपकी कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. आपकी कार्यशैली और कार्यक्षमता में सुधार होगा. किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आने धन की हानि होगी.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)

आर्थिक मामलों में रणनीति बनाएंगे. सपंत्ति खरीदने से बचें अभी उचित समय नहीं है. सफलता प्राप्त होने में देरी हो सकती है विचलित न हों. दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होगा. इस सप्ताह कोई मित्र मदद करेगा. इस सप्ताह सोच समझकर ऋण लें.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)

मित्रों के सहयोग से आपका का कार्य पूर्ण होगा. इस सप्ताह खर्च बढ़ेंगे. क्रोध पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आप चिंतित रहेंगे. आप अपनी गोपनीय बातें गैर लोगों से शयर न करें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)

जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय न लें. दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा. किसी विषय को लेकर परेशान न हों. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. नौकरीपेशा लोग अपने कार्य को लेकर परेशान हो सकते हैं.

csastrologer@gmail.com

ज़रा हट के

लगातार 86 घंटे दौड़ी महिला

मनुष्य बिना नींद के नहीं रह सकता यदि वह एक रात न सोए तो वह दिन में एक घंटे भी काम नहीं कर पाएगा और उसकी पलकें पूरे दिन झपकती रहती हैं. न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में रहने वाली 47 वर्षीय एक महिला ने बिना नींद लिए 86 घंटे लगातार दौड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. महिला का नाम किम एलेन है और वह चार बच्चों की मां है. किम एलेन ने एक प्रतियोगिता दौड़ के पहले 486 किलोमीटर के रिकॉर्ड को पूरा कर लिया. लेकिन वह महिला अपनी दौड़ में इतनी मशगूल थी उसे पता ही नहीं चला कि वह कब 12 मैराथन के बराबर दौड़ चुकी

है. किम ने 86 घंटों में कुल 500 किलोमीटर दौड़ लगाई. किम की टीम ने उसे रुकने को इसलिए नहीं कहा, क्योंकि वह उस समय एक विश्व कीर्तिमान रच रही थी. अपनी दौड़ के अंतिम पड़ाव में पहुंचने पर उसकी टीम की एक सदस्य ने एक स्थानीय रिपोर्टर को इसकी जानकारी दी. दौड़ लगाते समय किम के पेट में दर्द भी हुआ, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया. पैरों में दर्द से निजात पाने के लिए उसने अपने जूतों में आगे की ओर छेद कर लिया, ताकि पैरों की उंगलियों में दर्द से आराम मिले. ■

कुत्ता कहने से पहले सोच लेना

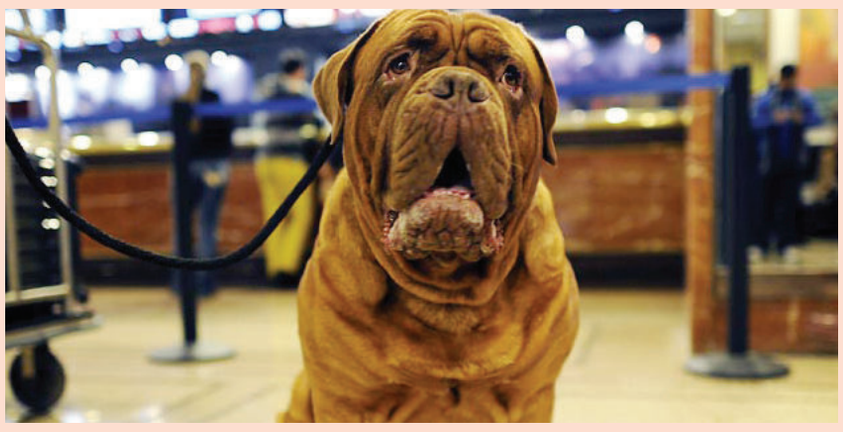

आप ने शायद इतने शाही कुत्ते के बारे में न सुना हो. इस कुत्ते के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे. अमृतसर में आयोजित डॉग शो में देश-विदेश के लगभग पांच सौ कुत्तों ने भाग लिया. कोई कुत्ता जहाज से आया था तो कोई ऑडी से और कोई मर्सडीज से. दुनिया के हर एक नस्ल के कुत्तों का जमावड़ा देखने को मिला. हैदराबाद से अभिमन्यु रेड्डी अपने चालीस लाख के कुत्ते एरिन को लेकर फ्लाइट से दिल्ली से अमृतसर पहुंचे थे. एरिन दुनिया में रैंकिंग में टॉप टेन में शामिल है, तीन हजार के शैंपू से नहाता है. उसको आने जाने के लिए ऑडी गाड़ी है और दुनिया के पच्चीस मुल्कों का वीजा उसके पासपोर्ट पर लगा है. विदेशी डॉक्टर एरिन के डाइटिंग का ख्याल रखते हैं और योग करवाने के लिए योग टीचर है. उसका ड्राइंग रूम पचास लाख का है. एरिन के पास पांच सुरक्षा कर्मी भी हैं जो हमेशा रखवाली करते हैं. एरिन के लिए अमृतसर के एक नामचीन होटल में कमरा बुक था. एरिन को कड़ी सुरक्षा के बीच होटल पहुंचाया गया. उस दिन सर्दी अधिक होने के कारण उसे 70 लाख की गाड़ी से प्रतियोगिता के समय ही उतारा गया. रेड्डी बताते हैं कि एरिन के लिए 24 घंटे डॉक्टर दो शिफ्ट में उसका ख्याल रखते हैं. सुबह चार बजे योग के लिए योग टीचर है. नहलाने के लिए अलग स्टाफ है.

यही नहीं ऐरिन की पसंद का ख्याल रखने के लिए बेहतरीन कुक रखे गए हैं. ऐरिन इंटरनेशनल आल ब्रीड डॉग चैंपियनशिप में टॉप टेन का खिताब हासिल कर चुका है और इंडिया का नंबर वन डॉग भी है. डॉग शो करवाने वाले अमृतसर कैनाइन क्लब के चेयरमैन एआइएस भिंडर कहते हैं कि इस शो में दुनिया के बेहतरीन नस्लों के कुत्ते आए हैं, इसलिए डेनमार्क से जजमेंट के लिए विदेशी जज चेनवेंग वोह पहुंचे थे. ■

चश्मे ने बचाई जान

आम तौर पर लोग तेज धूप और तेज रोशनी से आंखों को बचाने के लिए चश्में का प्रयोग करते हैं. हम कभी सोच भी नहीं सकते है कि चश्मा हमें मरने से बचा सकता है कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका में गोलीबारी के समय एक लड़की की जान चश्में के कारण बच गई. सीटल में एक लडकी अपने घर में काउच पर सो रही थी तभी उसके चश्में से टकराकर गोली दिशा बदल गई और उसे केवल मामूली

चोट आई है. पुलिस का कहना है कि भारतीय समयानुसार 11 बजकर 10 मिनट पर एक कार में आए कुछ हमलावर उसके घर पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए निकले. उसी दौरान कुछ गोलियां दीवारों से टकराईं, लेकिन एक गोली खिड़की से अंदर आकर लड़की की चश्में से टकरा गई. एक स्थानीय अस्पताल में उसका इलाज कराया गया है. पुलिस के प्रवक्ता मार्क जेमिसन ने बताया कि वह बहुत भाग्यशाली है. पुलिस गोलीबारी को गैंगवार का परिणाम बता रही है. हालांकि उसका कहना है कि लड़की हमलावारों के निशाने पर नहीं थी. ■

बांग्लादेश एक बार फिर 1971 के रास्ते पर लौट आया है, जहां हर तरफ खून–खराबा और अस्थिरता का माहौल है. बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना देश को स्थिर बनाने और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं. जब–जब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार रही, वहां आतंकवाद को बढ़ावा मिलता रहा, जिसका असर भारत पर भी रहा.

कैसी होगी मोदी की विदेश नीति

मनमोहन सिंह पिछले 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं और इन 10 सालों में भारत की विदेश नीति गर्त में चली गई है. वे एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, जो न तो देश की आंतरिक समस्याओं का निदान ढूंढ़ पाए और न ही विदेश नीति के तहत भारत की प्रतिष्ठा को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित कर सके. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में विश्व के सुपर पावर अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस से भारत को कोई खास फायदा भी नहीं हुआ, साथ ही पड़ोसी राष्ट्र चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव और नेपाल से रिश्ते भी बिगड़ गए.

राजीव रंजन

इ बीजेपी के शासन के बाद वो दिन कभी नहीं आया, जब हम अमेरिका के समक्ष सिर उठाकर खड़े रहे. जब भाजपा के नेता जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे, तो वे अमेरिका के साथ संबंधों को काफी हद तक पटरी पर लाए. इसके पीछे पार्टी की किसी भी देश के सामने न झुकने की कठोर विदेश नीति थी. पिछले दिनों 2002 के गुजरात दंगा मामले में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई. इसके बावजूद उनके लिए अमेरिकी वीजा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ. तो पहला सवाल यही है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अमेरिका के प्रति उनकी नीति सख्त होगी? दूसरा सवाल है कि जिस समर्पण के साथ यूपीए सरकार ने अपने प्रथम कार्यकाल में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करने में दिखाई थी, विपक्ष के दबाव की वजह से मजबूत न्यूक्लियर बिल लाना पड़ा. आज यही बिल न्यूक्लियर रिएक्टरों की स्थापना में रोड़ा साबित हो रहा है. भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वे न्यूक्लियर रिएक्टरों की स्थापना कर एनर्जी सेक्टर को सुदृढ़ कर पाएंगे, ताकि भारत को बिजली की आपूर्ति भरपूर रूप से हो सके, वो भी तब जब भारत में नये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की स्थापना का विरोध हो रहा है.

भारत एक उभरता हुआ शक्ति है. अगर उसे सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता मिल जाती है, तो वह विश्व के ताकतवर देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा. अब मोदी के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि वे सुरक्षा परिषद में भारत के लिए जगह पाने के लिए अमेरिका का समर्थन कैसे हासिल करेंगे. इसके अलावा आईएमएफ में रिफॉर्म्स को मुर्त रूप देने के लिए अमेरिका पर किस तरह से दबाव बनाएंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा हमेशा से भारत को एक चुनौती के रूप में देखते रहे हैं. उन्होंने कई बार अमेरिकी नागरिकों की जॉब भारतीयों द्वारा छीन जाने की आशंका जताई है. इसी को देखते हुए ओबामा ने आउटसोर्सिंग कंपनियों को अपने यहां टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है और भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की वीजा नियमों को सख्त बना दिया है, जिसका टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस जैसी प्रमुख भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां विरोध करती रही हैं. मोदी आखिर क्या कदम उठाएंगे जिससे भारतीय कंपनियां अमेरिका जाने की बजाए अपने यहां ही लोगों को रोजगार दें या यूरोपीय देशों की तरफ रुख करें, ताकि उन कंपनियों की अमेरिका पर निर्भरता भी कम हो जाए? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर होने के साथ–साथ भारत के लिए भी सबसे बड़ा आर्म्स का सप्लायर है. मोदी के सामने बड़ी चुनौती इस बात की होगी कि वे किस प्रकार से भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाते हुए अमेरिकी सहयोग से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के समक्ष खुद को सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित कर सके, ताकि भारत किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे. विश्व एक बार फिर दो ध्रुवीय होने की दिशा में अग्रसर है. चीन दूसरे ध्रुव के रूप में उभर रहा है. ऐसे में जब नैम जैसे गुटों की उपयोगिता खत्म हो चुकी है, तब भारत मोदी से क्या अपेक्षा करेगा?

इजराइल हमेशा से ही भारत का सहयोगी रहा है. यह अमेरिका का भी सहयोगी रहा है. सैन्य उपकरणों के मामलों में भी यह हमेशा भारत का सहयोग करता रहा है. यह आरोप हमेशा से लगते रहे हैं कि इजराइली खुफिया एजेंसी मोसाद भारत में भाजपा की हिंदूवादी सरकार बनवाना चाहता है, ताकि मुस्लिम देशों के विरुद्ध कार्रवाई करने के दौरान वह भारत का सहयोग हासिल कर सके. 26 /11 हमले के बाद जांच में इजराइल ने भारत का बहुत सहयोग किया. मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर भारत–इजराइल संबंधों में कितना प्रगाढ़ता लाएंगे, यह देखने वाली बात होगी.

रूस और भारत के बीच खटास का कारण बने एडमिरल गोर्शकोव अंततः भारत को मिल गया, जिसकी कीमत में कई बार बढ़ोतरी की गई. रूस हमेशा से ही भारत का हर स्तर पर सहयोग करता रहा है. सुरक्षा परिषद में भी वह भारत की दावेदारी का समर्थन करता है. भारत आज भी अपने नीतिगत सैन्य हथियार रूस से ही खरीदता है. वह रूस के साथ मिलकर पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों का भी निर्माण कर रहा है. न्यूक्लियर पावर के मसले पर वह भारत का बहुत पुराना साथी है. ऐसे में जब कुडनकुलम में रूस द्वारा निर्माण किए जाने वाले परमाणु रिएक्टरों का संसद में विरोध न करना यही दिखाता है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी रूस भारत का अभिन्न सहयोगी बना रहेगा.

अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल के दौरान परमाणु परीक्षण को देखते हुए दुनिया के अधिकांश देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन फ्रांस एक अच्छे मित्र के रूप में भारत के साथ इन दिनों खड़ा रहा और भारत के परमाणु परीक्षण को सही ठहराया. क्या मोदी फ्रांस के साथ संबंधों को नया आयाम देंगे और वाजपेयी की विरासत को आगे ले जाएंगे? वह भी तब जब फ्रांस में इस समय समाजवादी सरकार सत्ता में है.

पिछले कुछ सालों में जापान में कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन सभी के कार्यकाल में जापान का भारत से रिश्ते मधुर ही रहे. भारत, जापान की आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) पाने वाला सबसे बड़ा देश है. 2013 के मार्च महीने में जापान ने भारत को 2.32 अरब डॉलर रुपये आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए दिए थे. हाल ही में भारत यात्रा पर आए जापान के सम्राट अखिहितो और रानी मिचिको की अगवानी के लिए भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे थे. इससे जापान और भारत के रिश्तों की अहमियत का अंदाजा हो जाता है. भारत में दिल्ली

मेट्रो की तर्ज पर देश के कई प्रमुख शहरों में मेट्रो की शुरुआत होनी है, जिसमें जापान सहयोग कर रहा है. बुलेट ट्रेनों की भी भारत में शुरुआत होनी है, जिसमें जापान भारत का सहयोग करेगा. चूंकि मोदी हमेशा ही अपने भाषणों में विकास के मुद्दे पर जोर देते रहे हैं, इसलिए उनके लिए जापान का सहयोग पाना और उसे बनाए रखना एक चुनौती होगी, क्योंकि बिना आधारभुत सरंचना के कोई भी निवेशक भारत में बड़े पैमाने पर निवेश नहीं करेगा. इस लिहाज से भारत के लिए जापान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है. भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी की परिकल्पना जापान और उसके पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई थी.

मोदी इस नीति को एक अलग स्तर तक ले जाने के लिए बाध्य होंगे. पाकिस्तान एक बार फिर से लोकतंत्र के रास्ते पर है और देश में भाजपा की सरकार बनने की संभावना तब जताई जा रही है, जब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं. अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अमन की आशा में लाहौर तक बस यात्रा की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद करगिल में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ के कारण हमें मुंह की खानी पड़ी थी. ऐसे में क्या मोदी प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके सिर पर कांटों का ताज सजने जा रहा है. मोदी कभी पाकिस्तान को विकास की सलाह देते हैं, वहीं अपने भाषणों में वे पाकिस्तान के मसले पर जिस तरह से आक्रामक हो जाते हैं, उससे भविष्य में दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख होने की संभावना प्रबल हो जाती है और ऐसे में यदि युद्ध की आशंकाएं जन्म लेने लगें, तो मोदी के विकास मॉडल को धराशायी होने में तनिक भी समय नहीं लगेगा. ऐसे में यह मोदी की हार होगी या भारत की जीत? गुजरात चुनाव के दौरान मोदी सरक्रिक विवाद को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और सोनिया गांधी की खिंचाई करते रहे और हाल ही में जम्मू में एक रैली के दौरान उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 पर पुनर्विचार करने की बात कही थी.

> **चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन कर उभरा है. भारत अभी भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में संघर्ष कर रहा है. भारत और चीन के बीच द्वीपक्षीय व्यापार 20 बिलियन डॉलर से अधिक का है, जिसमें आयात ज्यादा और निर्यात कम है. मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके लिए सबसे पहले जरूरत इस बात की होगी कि वह चीन से आयातित वस्तुओं की मात्रा कम करें और निर्यात को प्रोत्साहित करें. इसके लिए उन्हें तकनीक का आयात करना होगा, जिससे भारत में फैक्ट्रियों का निर्माण हो और लोगों को काम मिले.**

चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन कर उभरा है. भारत अभी भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में संघर्ष कर रहा है. भारत और चीन के बीच द्वीपक्षीय व्यापार 20 बिलियन डॉलर से अधिक का है, जिसमें आयात ज्यादा और निर्यात कम है. मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके लिए सबसे पहले जरूरत इस बात की होगी कि वह चीन से आयातित वस्तुओं की मात्रा कम करें और निर्यात को प्रोत्साहित करें. इसके लिए उन्हें तकनीक का आयात करना होगा, जिससे भारत में फैक्ट्रियों का निर्माण हो और लोगों को काम मिले. दूसरी समस्या भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर है. अरुणाचल पर अक्सर चीन अपने अधिकार की बात करता है. तवांग को लेकर भी चीन दावा पेश करता रहा है. इसके अतिरिक्त चीनी सैनिक आए दिन भारतीय सीमाओं में घुसपैठ कर भारतीय क्षेत्र को अपना बताते हैं. चीन ने भारत के एक बहुत बड़े भाग पर कब्जा किया है. तिब्बत की समस्या है, सो अलग. मोदी के समक्ष इन सभी समस्याओं से निपटने की चुनौती होगी.

नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है. अब वह संविधान निर्माण की दिशा में अग्रसर है. नक्सलवाद भारत की एक गंभीर समस्या है, जिसको काफी हद तक नेपाली माओवादियों से संरक्षण मिलता रहा है. मोदी किस तरह से इस समस्या को दूर करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है. भारत हमेशा से एक स्थाई लोकतंत्र की स्थापना का पक्षधर रहा है. पर क्या मोदी भारत में माओवाद के जड़ से खात्मे के लिए नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे? क्या यह नेपाल की संप्रभुता के खिलाफ नहीं होगा? अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें इन सवालों से रू–ब–रू होना पड़ेगा.

बांग्लादेश एक बार फिर 1971 के रास्ते पर लौट आया है, जहां हर तरफ खून–खराबा और अस्थिरता का माहौल है. बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना देश को स्थिर बनाने और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं. जब–जब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार रही, वहां आतंकवाद को बढ़ावा मिलता रहा, जिसका असर भारत पर भी रहा. दूसरी तरफ जब वहां शेख हसीना की सरकार रही, तो कट्टरपंथ और हूजी जैसे आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर विराम लग गया. मोदी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह नई सरकार के साथ किस तरह से तालमेल बैठाएंगे? भारत ऐसे भी पड़ोसियों के बीच रिंग ऑफ फायर में फंसा हुआ है. अगर पड़ोसी मुल्क मजबूत और स्थिर नहीं होंगे तो भारत विश्व की एक बड़ी ताकत के रूप में खुद को नहीं स्थापित कर सकता.

श्रीलंका में लिट्टे के खात्मे के लिए सरकार पर बड़े पैमाने पर तमिलों के नरसंहार के आरोप लगते रहे हैं. श्रीलंकाई तमिलों का भारत के तमिलनाडु के तमिलों के साथ पारिवारिक संबंध रहे हैं. भारत हमेशा से श्रीलंका में तमिलों के अधिकारों का पैरवी करता रहा है, लेकिन हाल ही में राष्ट्रप्रमुखों के सम्मेलन में दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु के संगठनों के विरोध के बाद भारतीय प्रधानमंत्री का वहां न जाना यह बताता है कि भारत की क्षेत्रीय राजनीति विदेश नीति को प्रभावित कर रही है. मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तमिलनाडु की वर्तमान मुख्यमंत्री जयललिता समर्थन करती रही हैं. यदि भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में एआईडीएमके के समर्थन की दरकार मोदी को होगी और ऐसे में अगले पांच सालों तक तमिल मुद्दा भारत–श्रीलंका संबंधों को प्रभावित करता रहेगा. ऐसे में मोदी क्या रास्ता निकालते हैं, यह देखने वाली बात होगी. ■

साई

इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा. मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है. मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूं. बाबा के एक भक्त थे भीमा जी पाटिल जिनको एक बार भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षयरोग में बदल हो गया. उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, लेकिन लाभ कुछ न हुआ. अन्त में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण. हे प्रभु . मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो

एक बार...

जिसका कोई नहीं उसके साई

चौथी दुनिया ब्यूरो

बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण रहते थे और सदा निश्चिंत और निर्भय रहते थे. वह कहते थे कि मैं फकीर हूं, न तो मेरी स्त्री ही है और न घर–द्वार ही है. सब चिंताओं को त्याग कर, मैं एक ही स्थान पर रहता हूं. फिर भी माया मुझे कष्ट पहुंचाया करती है. मैं स्वयं को तो भूल चुका हूं, लेकिन माया को कदापि नहीं भूल सकता, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है. श्रीहरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती, फिर मुझ सरीखे फकीर का तो कहना ही क्या है, लेकिन जो हरि की शरण लेंगे, वे उनकी कृपा से मायाजाल से मुक्त हो जाएंगे. इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया. भगवान श्रीकृष्ण भागवत में उधव से कहते कि सन्त मेरे ही जीवित स्वरुप हैं और बाबा का भी कहना यही था कि वे भाग्यशाली, जिनके समस्त पाप नष्ट हो गए हों, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं, यदि तुम केवल साई का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा. इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा. मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है. मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूं. बाबा के एक भक्त थे भीमा जी पाटिल जिनको एक बार भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षयरोग में परिणत हो गया. उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, लेकिन लाभ कुछ न हुआ. अन्त में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो. यह तो विदित ही है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवान का स्मरण नहीं करते, लेकिन जब भी कोई विपत्ति आती है और बुरे दिन आते है, तभी हमें भगवान की याद आती है. इसीलिए भक्त ने भी भगवान को पुकारा. उन्हें विचार आया कि क्यों न साई बाबा के परम भक्त नानासाहब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की .उत्तर में उन्होंने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है और वह है साई बाबा के चरणकमलों की शरणागति. उनके वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी–प्रस्थान की तैयारी की. उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया. नानासाहेब और शामा भी उस समय वहीं उपस्थित थे. बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है. इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता. यह सुनकर रोगी अत्यन्त निराश होकर करुणा–पूर्ण स्वर में बोला कि मैं बिल्कुल असहाय हूं और अन्तिम आशा लेकर आपके चरणों में आया हूं. आपसे दया की भीख मांगता हूं. हे दीनों को शरण देने वाले मुझ पर दया करो. इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो आया और वे बोले कि अच्छा, ठहरो. चिन्ता मत करो. तुम्हारे दु:खों का अन्त शीघ्र होगा. कोई कितना भी दु:खित और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है, वह सुखी हो जाता हैं. मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी दूर कर देगा. वह तो सब लोंगों पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता हैं. रोगी को हर पांचवे मिनट पर खून की उल्टियां हुआ करती थीं, लेकिन बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी न हुई. जिस समय से बाबा ने अपने मुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उक्त उद्गार प्रगट किए, उसी समय से रोग भी ठीक होने लगा. बाबा ने रोगी को भीमाबाई के घर में ठहरने को कहा. यह स्थान इस प्रकार के रोगी के लिए सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो न था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था? वहां पर रहते हुए बाबा ने दो स्वप्न देकर उसका रोग हरण कर लिया. पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता न सुना सकने के दण्ड स्वरुप बेतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है. दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे असहाय पीड़ा हो रही है. स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया. फिर वह कभी–कभी शिरडी आता और साई बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता था. बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा न रखते थे. वे तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे. महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष या प्रतिमास सदैव सत्यनारायण का व्रत किया करते हैं, लेकिन अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर एक नया ही सत्य साई व्रत प्रारम्भ कर दिया.

साई बाबा की जीवनी सर्व प्रकार से प्राकृतिक और मधुर हैं. उनके अन्य कार्य भी जैसे भोजन, चलना–फिरना तथा स्वाभाविक अमृत से भरा उपदेश बड़े ही मधुर हैं. वे आनन्द के अवतार है. पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरुप ही यह देह प्राप्त हुआ है और उसकी सार्थकता तभी है, जब उसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकें. हमें अपने अन्त और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए.

यदि हम साई की लीलाओं का श्रवण करेंगे तो हमे उनका सदैव दर्शन होता रहेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई बाबा का जीवन सर्व प्रकार से प्राकृतिक और मधुर हैं. उनके अन्य कार्य भी, जैसे भोजन, चलना–फिरना तथा स्वाभाविक अमृत से भरा उपदेश, बड़े ही मधुर हैं. वे आनन्द के अवतार हैं. पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरुप ही यह देह प्राप्त हुई है और उसकी सार्थकता तभी है, जब उसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकें. हमें अपने अन्त और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव सावधान तथा तत्पर रहना चाहिए. यदि हम साई की लीलाओं का श्रवण करेंगे तो हमें उनका सदैव दर्शन होता रहेगा.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

प्रत्यक्ष काम नुकसानदायक नहीं

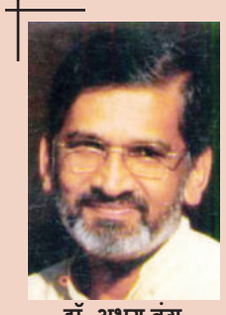

डॉ. अभय बंग

मन के प्रशिक्षण के लिए एक पद्धति सूझती है. जैसे योगासन करने से शरीर धीरे–धीरे मुड़ने और झुकने लगता है, वैसे ही मन को बदलने के लिए ऐसा कोई काम रोज करें, जिसका मुझे कोई फल नहीं मिलनेवाला हो. अर्थात प्रतिदिन त्याग की आदत डालूं. रोज निरर्थक कर्म करूं. क्या ऐसा करने से मैं थोड़ा निष्काम हो पाऊंगा?

हृदयरोग के विषय में आज की वैज्ञानिक समझ कैसे विकसित हुई, इस पर चुनिन्दा अध्यनों को पढ़ने पर गीता एवं ईशावास्योपनिषद के जिस रास्ते से जाने की मैं उम्मीद कर रहा था, उसकी वैज्ञानिकता मुझे अधिकाधिक समझ में आने लगी. हमारी व्यावसायिक कामों से उत्पन्न तनाव हृदयरोग का कारण बन सकता है. अमेरिका के राष्ट्रीय (हेल्थ एक्जामिनेशन सर्वे और हेल्थ ऐंड न्यूट्रिशन एक्जामिनेशन सर्वे) इन दो प्रसिद्ध सर्वेक्षणों के विश्लेषण में ऐसा देखा गया कि जिन्हें काम का तनाव अधिक था उन्हें हार्टअटैक चार गुना अधिक आए, लेकिन तनाव होता किस चीज से है? वैज्ञानिकों को ऐसा ज्ञात हुआ कि ज्यादा काम से तनाव नहीं होता है. तनाव होता है जिम्मेदारी से, समय के अभाव से काम के बारे में कोई मदद न मिलने से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था काम में नियत्रंण व स्वतंत्रता का. नियंत्रण जिनके स्वयं के हाथ में था, कैसा व कितना काम करें इसकी स्वतंत्रता थी, उन्हें तनाव कम था. जो परावलंबी थे, पर नियंत्रित थे उन्हें अधिक तनाव होता पाया गया. काम में तनाव के घटक समझ में आने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्यक्ष काम नुकसानदायक नहीं है, लेकिन काम के कारण निर्मित होनेवाली फल की अकांक्षा आदमी पर जिम्मेदारी एवं समय का बोझ बढ़ाती है. निष्काम कर्म स्वाभाविक रूप से ही तनावरिहत होगा. जब काम में किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है, कार्य करने की अथवा निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती तब तनाव का निर्माण होता है. बड़े–बड़े उद्योगों, कंपनियों अथवा सरकारी प्रशासन का एक पुर्जा होकर जो मनुष्य काम करता है उसे स्वतंत्रता खोने का तनाव होता है. अतएव काम के नियोजन में यह देखना होगा कि प्रत्येक को काम में स्वतंत्रता और स्वाबलंबन हो. साथ ही काम की जगह मैत्रीपूर्ण वातावरण हो तो तनाव नहीं होगा. अर्थात काम के दौरान भी मनुष्य को प्रेम एवं संबंधों की आवश्यकता होती है. काम मनुष्य को नहीं मारता आधुनिक औद्योगिक संस्कृति में जिस प्रकार व जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है. वे परिस्थितियां मनुष्य को मार डालती हैं. फ्रीडमैन एवं रोझमैन ने मनुष्य

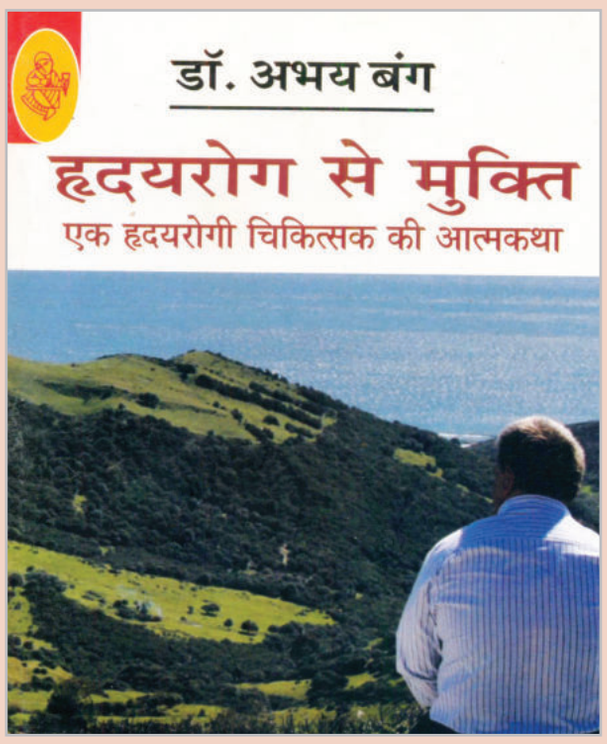

के व्यक्तित्व का हृदयरोग से क्या संबंध है इस पर खोज की. इससे टाइप ए एवं टाइप बी ये दो व्यक्तित्वों के ध्रुव समझ में आए. टाइप ए स्वभाव के मनुष्य हृदयरोग के अधिक शिकार होते हैं टाइप ए लोग कैसे होते हैं? उनकी पहचान के चिंह निम्न हैं.

1–अस्पष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करने की कल्पना से प्रेरित

2–यश,प्रगति, सामाजिक मान्यता कि प्रबल इच्छा

3–स्पर्धा से ग्रस्त

4–शीघ्रता की इच्छा सदैव बने रहना

5–हॉस्टिलिटी(बैर), क्रोध, शत्रुत्व से भरे.

संक्षेप में कहें तो आज का एक्जीक्यूटिव

आगे चलकर उन्होंने टाइप ए व्यक्तित्व के दो अंग अथवा घटक सबसे खतरनाक पाए. हास्टिलिटी व निराशावादी दृष्टिकोण ये कैसे प्रगट होते है संसार अथवा लोग बुरे हैं. ऐसा बार–बार कहना, दूसरों के प्रति अविश्वास की भावना, नकारात्मक भावना, बारंबार प्रकट होने वाला संताप और आक्रामकता इन रूपों में ये सामने आते हैं. ये सब मृत्यु के दूत हैं.

ग्रौसार्थ एवं मैटिसेक नामक दो शोधकर्ताओं ने ऐसा पाया कि तर्क एवं बुद्धि पर अधिक जोर देने वाले एवं अपनी भावनाओं को नकराने वाले मनुष्यों को हृदयरोग दस गुना अधिक होता है. इन्हें कैंसर भी सर्वाधिक अधिक होता है. कुल मिलाकर मन एवं स्वभाव का शरीर पर, विशेषत: हृदय पर, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है. शारीरिक हृदय एवं भावनिक हृदय इनका अति निकट का संबंध है. इसलिए अपना मन और भावना जांचे बगैर और उन्हें शुद्ध किए गए बगैर हृदयरोग से मुक्ति नहीं.

अरे, ये तो आध्यात्मिक और संतों द्वारा कही बात ही हो गई, योग, अध्यात्म व भक्ति ये व्यक्तित्व बदलने का एवं चित्तशुद्धि के मार्ग ही तो हैं. हृदयरोग होने के बाद भी यह परिवर्तन किया जा सकता है, यह आर्निश के अध्ययन से सिद्ध हुआ. टाइप ए पद्धति का व्यक्तित्व बदलने के व उससे हृदयरोग का खतरा कम होने के अन्य प्रयोग भी हुए हैं. आर्निश की ग्रुप उपचार–पद्धति में आहार, स्वभाव, धूम्रपान व व्यायाम की आदतें बदलने के अतिरिक्त, श्वासन, तनाव का विसर्जन, ध्यान, छोटे समूह में अपनी भावनाओं का अनुभव करना एवं नाते–रिश्ते का निर्माण करना ये अनेक घटक होने के कारण कुल प्रभावी रहा.

पाश्चात्य संशोधनकर्ताओं ने हृदयरोग के अनेक कारण ढूंढ़ निकाले हैं. कुछ कारण व्यक्तित्व के अंदर छिपे होते हैं और कुछ बाहर समाज में छिपे होते हैं और कुछ बाहर समाज से पैदा होते हैं. कुछ आंतरिक, कुछ बाह्य सामाजिक. क्या एक–एक कारण के लिए अलग–अलग उपाय किएं जाएं? प्रत्येक टुकड़े लिए अलग गोली, अलग औषधि, अलग उपाय? ऐसे टुकड़ो के बजाय एक भिन्न जीवन दर्शन की , समाज रचना की व समग्र जीवनशैली की आवश्यकता है. गांधी जी के मार्ग से अथवा आर्निश की उपचार–पद्धति से, कहीं से भी शुरू करें, अंत में भोगप्रिय इंद्रियों को संयमित करके नैसर्गिक आहार व शरीर–श्रम पर जोर देनेवाली, निष्काम कर्म कहनेवाली, अन्य मनुष्यों से प्रेम व कर्तव्य के रिश्तों से जोड़नेवाली, यौगिक आध्यात्मिक समग्र जीवनशैली–यही उपाय मुझे दिखाई दे रहा था. ■

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

गुरु और शिष्य

अपनी इस विधा पर धनुर्धर फूला नहीं समा रहा था. सफलता सिर चढ़कर बोलने लगी. अब वह कहने लगा कि वह गुरुजी से बढ़िया धनुर्धर हो गया है. गुरुजी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. एक बार गुरुजी को किसी काम से दूसरे गांव जाना था. उन्होंने अपने इसी शिष्य को बुलाया और साथ चलने को कहा. गुरु–शिष्य दोनों जब रास्ते से चले तो बीच में एक जगह खाई दिखी. गुरु ने देखा, खाई में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए एक पेड़ के तने का पुल बना हुआ है. गुरु उस पेड़ के तने पर पैर रखते हुए आगे बढ़े और पुल के बीच में पहुंच गए. वहां पहुंचकर उन्होंने शिष्य की तरफ देखा और पूछा कि बताओ कहां निशाना लगाना है. शिष्य ने कहा कि वो जो सामने पतला–सा पेड़ दिख रहा है उसके तने पर निशाना साधिए. गुरु ने तत्काल निशाना लगाकर बता दिया. इसके बाद उन्होंने शिष्य से ऐसा करके दिखाने को कहा. शिष्य ने जैसे ही पुल पर पैर रखा, वह घबरा गया. पुल पर अपना वजन संभालकर आगे बढ़ना मुश्किल काम था. शिष्य जैसे–तैसे पुल के बीच में पहुंचा. गुरु ने कहा–तुम भी उसी पेड़ के तने पर निशान साधकर बताओ. शिष्य ने जैसे ही धनुष उठाया, संतुलन बिगड़ने लगा और वह तीर ही नहीं चला पाया. वह चिल्लाने लगा–गुरुजी बचाइए वरना मैं खाई में गिर जाऊंगा. गुरुजी पुल पर गए और शिष्य को उतार लाए. दोनों ने यहां से चुपचाप गांव तक का सफर तय किया. शिष्य के समझ में बात आ गई थी कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है. ■

शिक्षा–कभी अपनी श्रेष्ठता का घमंड नहीं करना चाहिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

आज़ादी के बाद जब अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो आम जनता का वो सपना दरकने लगा. इस सपने के टूटने और विश्वास के दरकने की कहानी है मृदुला गर्ग का उपन्यास–मिलजुल मन. इस उपन्यास में गुल और मोगरा के बहाने मृदुला गर्ग ने आज़ादी के बाद के दशकों में लोगों की ज़िंदगी और समाज में आने वाले बदलाव की पड़ताल करने की कोशिश भी की है.

पुरस्कार से हासिल होगी साख?

अनंत विजय

हाल के वर्षों में ये पहली बार देखने को मिला कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के ऐलान के बाद हिंदी साहित्य में किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ. कहीं से कोई विरोध का स्वर नहीं उठा और न ही चयन पर किसी ने उंगली उठाई. इस बार हिंदी साहित्य के लिए अकादमी ने वरिष्ठ उपन्यासकार मृदुला गर्ग को सम्मानित करने का फैसला लिया. उनकी औपन्यासिक कृति मिलजुल मन के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया. मृदुला गर्ग की छवि एक ऐसी लेखिका की है, जो साहित्य की जोड़–तोड़ की राजनीति से दूर रहकर रचनाकर्म में लगी रहती हैं. जब प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने तो साहित्यिक हलके में ये कयास लगने लगे थे कि इस बार का अकादमी पुरस्कार दिल्ली में रहने वाले हिंदी के एक बुजुर्ग लेखक को दिया जाएगा. इस चर्चा को तब पंख लगे, जब प्रोफेसर सूर्य प्रकाश दीक्षित को हिंदी भाषा का संयोजक बनाया गया था. बाद में इस चर्चा में एक आलोचक का नाम भी शामिल हुआ. लेकिन पिछले सालों में जिस तरह से साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बंदरबांट हुई थी, उसके बाद से साहित्य जगत में भी इस पुरस्कार को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा था. ज़ाहिर सी बात है जिसको लेकर उत्साह नहीं होगा, उसकी चर्चा या उस पर विमर्श नहीं होगा. लेकिन इस बार बग़ैर शोर–शराबे के और बग़ैर किसी पक्षपात के ज्यूरी के सदस्यों ने मृदुला गर्ग का चयन कर एक नई शुरुआत के संकेत दे दिए हैं. इस बात के लिए साहित्य अकादमी के अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी समेत ज्यूरी के सदस्यों को बधाई दी जानी चाहिए कि अकादमी की खोई हुई विश्वसनीयता को बहाल करने की दिशा में उन्होंने एक क़दम उठाया. हालांकि, यह प्रोफेसर तिवारी के कार्यकाल का पहला ही पुरस्कार है, लिहाज़ा हमें जल्दबाज़ी में नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए. हम तो बस संकेत की सराहना कर रहे हैं.

मृदुला गर्ग लगभग चार दशक से लेखन में सक्रिय हैं. कहानी और उपन्यास के अलावा पत्र–पत्रिकाओं में भी उन्होंने विपुल लेखन किया है. उन्होंने कहानियों और उपन्यास के अलावा बेहद पठनीय तरीके से यात्रा वृत्तांत भी लिखा है. सबसे बड़ी बात यह है कि मृदुला गर्ग किसी तरह की ख़ेमेबाज़ी और लेखिकाओं की राजनीति से भी मुक्त रहती हैं. आजतक साहित्य जगत ने उन्हें किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत और हल्की टिप्पणी करते न तो देखा और न ही सुना है. इस तरह के व्यवहार से साहित्य जगत में उनकी एक प्रतिष्ठा और गरिमा दोनों बनी है. मृदुला गर्ग का उपन्यास मिलजुल मन, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था. मृदुला गर्ग के दो उपन्यास– चितकोबरा और कठगुलाब की साहित्यिक जगत में ख़ासी चर्चा हुई थी और लेखिका को प्रसिद्धि भी मिली थी. चितकोबरा के प्रकाशन के बाद उस वक्त साहित्य में उसकी विषय वस्तु और भाषा को लेकर काफ़ी विमर्श हुआ था. चितकोबरा में जो संवेदनशील स्त्री अपने नीरस जीवन से उकताकर सेक्स के प्रति असामान्य आकर्षण दिखाती है वो कठगुलाब तक पहुंचकर संवेदना के स्तर पर अधिक प्रौढ़ नज़र आती है. और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत इस उपन्यास मिलजुल मन में वो और भी मैच्योरिटी के साथ सामने आती है. मिलजुल मन की नायिका गुलमोहर और उसकी बहन मोगरा है. इस उपन्यास में लेखिका ने आज़ादी के बाद के दशकों में लोगों के मोहभंग को शिद्दत के साथ उठाया है. एक ख़ुशनुमा ज़िंदगी और समाज की उन्नति और बेहतरी का सपना देख रहे लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सबकुछ त्याग कर संघर्ष में हिस्सा लिया था. आज़ादी के बाद जब अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो आम जनता का वो सपना दरकने लगा. इस सपने के टूटने और विश्वास के दरकने की कहानी है मृदुला गर्ग का उपन्यास–मिलजुल मन. इस उपन्यास में गुल और मोगरा के बहाने मृदुला गर्ग ने आज़ादी के बाद के दशकों में लोगों की ज़िंदगी और समाज में आने वाले बदलाव की पड़ताल करने की कोशिश भी की है. मोगरा के पिता बैजनाथ जैन के अलावा डॉ. कर्ण सिंह, मामा जी, बाबा, दादी और कनकलता के चरित्र–चित्रण के बीच गुल बड़ी होती है और इस परिवेश का उसके मन पर जो मनोवैज्ञानिक असर होता है, उसका भी लेखिका ने कथानक में इस्तेमाल किया है.

मृदुला गर्ग लगभग चार दशक से लेखन में सक्रिय हैं. कहानी और उपन्यास के अलावा पत्र-पत्रिकाओं में भी उन्होंने विपुल लेखन किया है. उन्होंने कहानियों और उपन्यास के अलावा बेहद पठनीय तरीके से यात्रा वृतांत भी लिखा है. सबसे बड़ी बात यह है कि मृदुला गर्ग किसी तरह की ख़ेमेबाज़ी और लेखिकाओं की राजनीति से भी मुक्त रहती हैं.

इस उपन्यास में मृदुला गर्ग अपने पात्रों के माध्यम से हिंदी के लेखकों पर बेहद ही कठोर टिप्पणी करती हैं– तभी हिंदी के लेखक शराब पीकर फूहड़ मज़ाक से आगे नहीं बढ़ पाते. मैं सोचा करती थी, लिक्खाड़ हैं, सोच–विचार करने वाले दानिशमंद. पश्चिम के अदीबों की मानिंद, पी कर गहरी बातें क्यों नहीं करते, अदब की, मिसाइल की, इन्सानी सरोकार की. अब समझी वहां दावतों में अपनी शराब ख़ुद ख़रीदने का रिवाज क्यों है. न मुफ़्त की पियो और न सहने की ताक़त से आगे जाकर उड़ाओ. अपने यहां मुफ़्त की पीते हैं और तब तक चढ़ाते हैं जबतक अंदर बैठा फूहड़ मर्द बाहर न निकल आए. मृदुला गर्ग जब यह टिप्पणी करती हैं तो हिंदी साहित्य की एक ऐसी तस्वीर पाठकों के सामने आती है जो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है. मैं जब अपने शहर जमालपुर से दिल्ली आया था तो साहित्यकारों को महामानव माना करता था. धीरे–धीरे जब उनके साथ उठने–बैठने का मौक़ा मिला तो ज्यादातर महामानव लघुमानव भी नहीं रह पाए. मृदुला गर्ग ने साफ़–साफ़ हिंदी के लेखकों को अपने इस उपन्यास में बेनक़ाब किया है. इस उपन्यास की भाषा में रवानगी तो है, लेकिन ख़ालिस उर्दू के शब्दों के ज्यादा प्रयोग से वो गाहे–ब–गाहे बाधित होता है. उर्दू नहीं जानने वाले हिंदी के पाठकों को इससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है. लेकिन उपन्यास में जिस काल का वर्णन है, ऐसा प्रतीत होता है कि लेखिका उस काल की भाषा को उठाना चाहती हैं. उपन्यास को लेखिका ने जिस बड़े फलक पर उठाया है, उसको संभालने में काफ़ी मशक्कत भी की है. अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि मृदुला गर्ग को सम्मानित करने का फ़ैसला कर साहित्य अकादमी से और बेहतर की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं. अकादमी से अपेक्षाएं तो और भी हैं कि उसको रवींद्र भवन और चंद लेखकों के चंगुल से मुक्त करवाकर आम पाठकों के बीच ले जाने की कवायद की जानी चाहिए. कुछ चुनिंदा लेखकों की गुलामी की ज़ंजीर से अगर साहित्य अकादमी को मुक्त करवाया जा सका तो विश्वनाथ तिवारी का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, वरना वो भी अध्यक्ष के कक्ष में लगी पूर्व अध्यक्षों की सूची में एक और नाम भर बनकर रह जाएंगे. उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले पांच साल में साहित्य अकादमी अपने गठन के समय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करेगी और बगैर किसी भेदभाव के सभी लेखकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करेगी. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)

anant.ibn@gmail.com

कविता

पहचान

ज्योतिमा शुक्ला 'रश्मि'

यह भीड़ मैं पहचानती हूं
हर-एक चेहरे को जानती हूं
पर उभरता है अचानक
सामने वालों की आंखों में
एक अनजानापन
यह क्या है, बस इसे नहीं पहचानती
शायद यहां अब तक ख़ामोशी है
या कोई उदासी है
या फिर दुनिया की वही पुरानी कहानी है
कुछ भी हो, बस यही वह कैफियत है
जिससे नहीं उबर पाती हूं
हंसती हूं, मिलती हूं सबसे
पहले की तरह
बाते भी करती हूं, लेकिन अचानक
बीच में आ जाता ठहराव
महसूस करती हूं मैं, लेकिन
यह क्या है, बस इसे नहीं पहचानती
भीड़ में लगने लगती हूं अकेली
उठने लगते हैं मन में सवाल कई
क्या ये वही चेहरे है?
या फिर मेरी आंखें
धोखा देती हैं बार-बार
कर देती हैं फिर से परेशान
बातें करते-करते जिससे रुक जाती हूं मैं
देखती उन चेहरों को ढूंढती नज़रों से
शायद चेहरों के पीछे से अजनबी
चेहरा दिख जाए, मैं दूर हो जाऊं
भीड़ को अजनबी समझकर
लेकिन कैसे?
इन चेहरों को तो मैं पहचानती हूं
ये तो वही चेहरे है, जो मुझे
मुझसे ज्यादा जानते हैं
मेरी साफ़गोई को पहचानते हैं
पर क्या मैं अब भी नहीं पहचानी
मैं बन गई अनजानी
बस पहचान सिर्फ़ चेहरों की
भावनाओं का जुड़ाव ख़त्म हो चुका
औपचारिकता शेष रह गई
और रह गया ये सवाल
चेहरों को पहचानती हूं
लेकिन इन पहचाने चेहरों का अनजानापन
यह क्या है, बस इसे नहीं पहचानती. ■

समीक्षा

किस्सा-ए-कुलगुरु : ब्रह्मांड विश्वविद्यालय

रचना सिंह

सराज़ युद्ध की समाप्ति पर विजय पक्ष के सेनानायक ने एक सवाल के जवाब में कहा–दुनिया वालों से कह दो कि बूढ़ा अंग्रेजी भूल गया है. कहने के पीछे आधार यह था कि किसी भी देश का उसका अपना झंडा, अपनी भाषा होनी चाहिए. तभी से उस देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई. कुछ नेताओं की दृष्टि में हिंदी में मौलिक चिंतन–लेखन का अभाव था. सो तय हुआ कि इसकी महती ज़िम्मेदारी किसी विवि को सौंप देनी चाहिए. अचानक किसी के मन में यह कौंधा कि क्यों न देश के 'ज़ीरो माइल' पर एक ब्रह्मांड विश्वविद्यालय खोला जाए. दो दशकों की सहमति–असहमति के बाद ब्रह्मांड विश्वविद्यालय खुलने की अनुमति मिल गई. कुलगुरु के चयन हेतु खोज समिति बनी, जिसमें मोदी–भय से देश छोड़कर जाने की चाहत रखने वाले एक ख्यातिलब्ध साहित्यकार और 'प्रव्रज्या–योग' के साधक साहित्यकार का नाम था. नारद–यात्रा के दौरान रास्ते में उनकी निगाह कटि प्रदेश के सागर किनारे जाकर अटक गई. उन्होंने वहां देखा कि रौबइंडिया का कुर्ता पहने एक सुकुमार बुजुर्ग वृक्ष के नीचे बैठकर कविता पाठ कर रहा है. सदस्यों ने पूछा– अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? शोकाकुल ने जबाब दिया–क्या करूं? हिंदी वालों को जीवन भर सरकारी ख़र्चे पर यात्रा कराने के बावजूद मुझे कवि नहीं माना गया. उधर एक–दो पुरस्कार क्या झटका कि प्रमोशन ही रोक दिया गया. खैराती जीवन जीने वाले साहित्यकारों ने उनकी हालत पर तरस खाते हुए ब्रह्मांड विश्वविद्यालय के प्रथम कुलगुरु के लिए तैयार किए जाने वाले पैनल में शोकाकुल का नाम डाल दिया. 'शंकर' का आशीर्वाद और चित्रगुप्त के दरबार में अपनी पकड़ के चलते उन्होंने उस पद को प्राप्त किया. पुरानी सेवा के दौरान 'भव्य–भारत' के सहयोग से ये अपने को कला–संस्कृति मर्मज्ञ के रूप में स्थापित करने में सफल हुए थे. कुलगुरु होते ही हिंदी–साहित्य के तमाम गिरे–पड़े साहित्यकारों को यात्रा और रसरंजन का सुख दिलाने के लिए धन की गठरी खोल दी. हिंदी साहित्य जगत वाह–वाह कर उठा. पांडु–पुत्र के सहयोग से कार्य–परिषद भी मनमाफिक मिली. कोर्स डिजाइन को लेकर लंबी–लंबी बैठकें होने लगीं. पैसा पानी की तरह बहने लगा. अष्टछाप के कवि दोनों हाथों से 'मानदेय' पकड़ने लगे. ताक़त के गुमान में वाजिदअली शाह का यह पुरस्कर्ता दिल्ली के तख़्त–ए–ताऊस पर बैठकर विवि को चलाने की ज़िद कर बैठा. विवि की स्थापना 'ज़ीरो माइल' पर होनी थी. पर शोकाकुल ने 'ऐयाश केंद्र' से 15 किमी की त्रिज्या के आधार पर एक वृत्त खींचा और वहीं स्थापित करने के लिए अपनी पूरी ताक़त झोंक दी. इस बीच इन्होंने 'सत्यवचन' नामक एक पत्रिका का विमोचन भी पाताल में कराया. कहते हैं कि लोग लौटते समय 'सत्यवचन' की प्रतियों को वहीं पाताल लोक के हवाई अड्डे पर ही छोड़ आए.

कोर्स एवं ज़मीन के चक्कर में 3–4 वर्ष गुज़र गए. अब विवि है तो कुछ तो पठन–पाठन कराना ही पड़ेगा. शोकाकुल ठहरे कवि को आलोचक की ज़रूरत होती है. उन्हें कविता के एक 'किशोर' आलोचक दिखे. किशोर 'आनंद' के लिए परेशान हाल थे. शोकाकुल ने ब्रह्मांड विवि के लिए 'अपूर्व–आनंद' की व्यवस्था कर दी. विवि में आनंद तभी है, जब वहां बेहतरीन ग्रंथालय हो. इसके लिए शोकाकुल ने आनंद को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी. आजकल भारतीय विवि में एक बड़ी मज़ेदार व्यवस्था हो गई है. यहां जूता और पुस्तक ख़रीद में ख़ास अंतर नहीं रह गया है. प्रकाशकों ने अध्यापकों का बोझ न्यूनतम कर दिया है. वे स्वयं तय कर देते हैं कि किन पुस्तकों की आपको ज़रूरत है. ब्रह्मांड विवि में भी यही हुआ. यहां वाणी का साम्राज्य ऐसा फैला कि कमल भी शरमाने लगे. पांच वर्ष बाद फिर नए कुलगुरु की खोज शुरू हुई. इस बार खोज समिति में साहित्य–इतिहास का गठजोड़ था. द्विजद्वय ने अपने–अपने राम के तर्ज पर वाक–सत्य का नाम आगे बढ़ाया. पर दो द्विजों की लड़ाई में प्रोफेसर मैराथन ने बाज़ी मारी. संत मैराथन ने आते ही विवि को ज़ीरो माइल पर स्थापित करने का निर्णय लिया. तख़्त–ए–ताज को तय जगह पर लगाया. विवि शनैः–शनैः आगे बढ़ना शुरू हुआ. पर शोकाकुल के आकाशमार्गी सहयात्रियों को यह पचा नहीं. गतिशील कार्यपरिषद ने इसमे टांग अड़ाना शुरू कर दिया. डगरते–मगरते इनका कार्यकाल भी ख़त्म हुआ. अब तीसरे कुलगुरु की खोज शुरू हुई. इस बार की खोज समिति में शोकाकुल के एक जूनियर भी थे. खेल खुलकर चला. पांडु–पुत्र की विशेष रुचि के बावजूद बटेर भभूति के हाथ लगी. हाशिए पर बैठे शशि–भास्कर, नाग–कैरत सब सक्रिय हो गए. 'समय' का ज़ोर चला–हिन्दी समय, लोक समय, विमर्श समय, ब्लाग समय और न जाने कौन–कौन सा समय. समय ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए. ब्रह्मांड विवि के चौथे कुलगुरु की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई. इस बार की खोज समिति में शोकाकुल बतौर एक सदस्य शामिल हैं. स्वप्नदर्शी शोकाकुल को पुनः एक बार अवसर मिल गया अपने पुराने अरमानों को अमली जामा पहनाने का. खोज समिति ने कुछ लोगों का नाम सुझाते हुए चित्रगुप्त के मातहतों को बंद लिफ़ाफ़ा दे दिया और अपने–अपने काम में जुट गए. पर शोकाकुल को चैन कहां? बैठक ख़त्म होते ही वे सक्रिय हो गए. शाम होते–2 उन्होंने अपनी कारस्तानी को जगज़ाहिर कर दिया. उन्होंने कुछ सूत्र पकड़े और उन्हें अपने काम पर लगा दिया. अख़बार घरसत्ता ने उनका साथ दिया और देश की सबसे बड़ी समस्या के रूप में ब्रह्मांड विवि उभर कर सामने आया. घरसत्ता के मुखपृष्ठ पर अंदर की बात को ख़ास तरीक़े से छापा गया. चित्रगुप्त के दरबारी हक्का–बक्का. लिफ़ाफ़ा उनके यहां खुलना था, पर मजमून पहले ही बाहर. शोकाकुल के कारनामें यहीं नहीं ख़त्म हुए. उन्होंने ब्रह्मांड विवि को बचाने के लिए तत्काल दो ख़त मजा फाउंडेशन के लेटर पैड पर लिखे. एक विरोध में और दूसरा पक्ष में. खोज समिति के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि कोई सदस्य खुले तौर पर अपनी व्यतिगत राग–द्वेष को अमली जामा पहना रहा हो. पहले पत्र में शोकाकुल ने अपनी चाल को और मज़बूती प्रदान करने के लिए खांग्रेसी अंदाज़ में संविधान को भी धता बताने की कोशिश की. उधर ग्रेवाल त्रयी ने भी अपना काम शुरू कर दिया. उत्तम पुरुष के लिए ब्रह्मा के 'अन्याय मंत्रालय' ने साफ तौर पर कह दिया है कि विश्वविद्यालयों पर चित्रगुप्त मंत्रालय का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है. शोकाकुल का दूसरा पत्र संवेदन लिए हुए हैं. कबीर मोदी अकादमी से पुरस्कृत शोकाकुल को इस बात का दर्द है कि देश–विदेश की तमाम यात्राओं और कुछेक मानद उपाधि झटकने के बावजूद उन्हें सांस्कृतिक प्रबंधक कहा जा रहा है. ब्रह्मांड विश्वविद्यालय के कुलगुरु का खेल अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चला है. इधर मनुष्य और देवता, भाग्य और पुरुषार्थ के बीच सूर्योदय के साथ ही वैभव–प्राप्ति के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है. उधर गोपी वल्लभ अपनी काव्योपम बांसुरी पर राग नामवरी का तान छेड़े हुए हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई–मेल: feedback@chauthiduniya.com

> टीवीएस ने इस नए स्कूटर को लाउड स्टाइल डिजाइन दी है जिससे यह स्कूटर ज्यादा बड़े सेगमेंट को टारगेट कर सके. इसमें युवाओं से लेकर महिलाएं और ज्यादा उम्र के लोग भी शामिल हैं. इसकी डिजाइन पहले के डिजाइनों से ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न है.

कॉल अन्ना को सफल बनाया बिग वी टेलीकॉम ने

अन्ना हजारे द्वारा लड़ी गई जनलोकपाल की निर्णायक लड़ाई के दौरान समूचे देश को अन्ना से जोड़ने और उनके विचारों को सुनने के लिए कॉल अन्ना सुविधा ने भी निर्णायक भूमिका निभाई. कॉल अन्ना एक कॉल सेंटर है जिसके माध्यम से न केवल देश, बल्कि विदेशों से भी अन्ना के समर्थक उनसे जुड़े और अपना संदेश उन तक पहुंचाते रहे. कॉल अन्ना के माध्यम से इस अन्ना के आंदोलन को वैश्विक बनाने में बिग वी टेलिकॉम ने भूमिका निभाई. कैसे काम करता है यह पूरा सिस्टम और क्या है बिग वी टेलीकॉम का विजन यह जानने के लिए हमने बात की बिग वी टेलिकॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर किशोर डागा से. बिग वी टेलिकॉम टेली कॉलिंग सेक्टर की पहली कंपनी है जो टाटा इलेक्सी के माध्यम से संचालित है. टाटा इलेक्सी टाटा समूह की कंपनी है जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग के क्षेत्र में सक्रिय है.

सबसे पहले बताइए कि एक सामान्य बीपीओ और आपके कॉल सेंटर में क्या फर्क है.

देखिए, कोई भी क्षेत्र हो चाहे वह उद्योग जगत हो, शिक्षा जगत हो, समाजसेवा हो या फिर अन्य कोई भी सेक्टर, आपको लोगों तक पहुंचने के लिए अपना मैसेज उन्हें देना होता है. कॉल सेंटर के माध्यम से हम यही करते हैं कि आपकी बात लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग आपसे क्या जानना चाहते हैं, इसका माध्यम बनते हैं. लेकिन अब तक कॉल सेंटर की अवधारणा थी कि बड़े औद्योगिक घराने या जिनका बड़ा बिजनेस मॉडल है वही इसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यह कॉल सेंटर पूरी तरह से ह्यूमन इंटरैक्शन बेस्ड होते हैं. जो स्मॉल एंड मिडिल एंटरप्राइजेज (एसएमई) हैं उनके लिए इतना बड़ा सेटअप काफी खर्चीला होता है. हम उनके लिए एक विकल्प हैं, क्योंकि ऑटोमोटिव व रिकॉर्डेट सिस्टम पर चलते हैं जो एसएमई के लिए बेहद किफायती है. पिछले दिनों जब अन्ना हजारे रालेगणसिद्धी में अनशन पर थे तो कॉल अन्ना काफी लोकप्रिय हुआ.

आप इस मिशन से कैसे जुड़े?

अन्ना हजारे और जनलोकपाल मिशन से जुड़ना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का अंग है और हम जनलोकपाल पारित हो जाने के बाद भी अन्ना हजारे से जुड़े हुए हैं. वास्तव में अन्ना हजारे एक ऐसे नेता है जो देश और काल की सीमा में नहीं बंधे हैं और कई सामाजिक आंदोलन के नेता रहे हैं इसलिए हम उनके साथ जुड़े. कॉल अन्ना में एक सप्ताह के भीतर ही देश–विदेश से हजारों लोगों ने हमारे माध्यम से उन्हें सुना, उनको समर्थन दिया.

अन्ना हजारे से बातचीत करते बिग वी टेलीकॉम के एमडी किशोर डागा

और किन–किन सेक्टर में आपकी सुविधा लोग ले रहे हैं?

तकरीबन हर सेक्टर के लोग हमारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक ही नंबर से सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं. हम एजुकेशनल सेक्टर में बड़े पैमाने पर हैं, एटवरटाइजिंग में हैं. सोशल सेक्टर में है. इसका दायरा बढ़ रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में हर किसी को अपने एक कॉल सेंटर की जरूरत पड़ेगी. नौकरी खोजने वाले लोग, मैट्रीमोनियल या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र लें यह सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह सबकुछ बस एक फोन कॉल की रीच पर होगा. हम अपने क्लाइंट को वेब लॉग के माध्यम से एक रिच डेटा भी देते हैं जो उनके बिजनेस के लिए अपने टारगेट क्लाइंट को पहचानने के लिए बेहद फायदेमंद है.

क्या आप राजनीतिक व दूसरे सोशल सेक्टर को भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं?

बिल्कुल कई राजनेताओं के साथ हम जुड़े हैं वे हमारी सेवाएं ले रहे हैं. जनसंवाद के नाम से यह सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं. चूंकि देश में इस समय राजनीतिक माहौल है. अभी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कई सारे नेताओं ने हमारी सेवाएं ली. लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोग कई राजनीतिक दलों से लोग हमारी इस सेवा का लाभ लेने के लिए संपर्क में हैं.

भविष्य की क्या योजनाएं हैं?

अभी देश के अधिकांश शहरों में हम अपनी फ्रेंचाइजी के माध्यम से पहुंच रहे हैं. हम अपने इस नेटवर्क को और विस्तार दे रहे हैं. जल्द ही हम समूचे भारत में मौजूद होंगे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

निसान की सस्ती कारें मचाएंगी धूम

जानी-मानी कार कंपनी निसान ग्राहकों और बाजार में अपना दबदबा कायम करना चाहती है. इसलिए ही अब कम कीमत की कारें बाजार में उतारने जा रही है. कंपनी विकासशील देशों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगी, जिसके लिए निसान ने डैटसन ब्रांड की तैयारी की है. भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और रूस जैसे देशों में लोग हाईटेक और महगी कारों की बजाए कम बजट वाली कारें अधिक पसंद करते हैं. गो हैचबैक कैटगरी में डैटसन की कार होगी जो भारत में इस साल लॉन्च होंगी और इसके बाद गो+ एमपीवी जो इस साल के अंत तक आएगी. निसान 2016 तक अपने 7 प्रोडक्टस लॉन्च करेगी, जिनमें 3 मॉडल पर डैटसन की मोहर होगी. डैटसन का तीसरा मॉडल एक छोटी कार होगी. जिसकी कीमत 2–3 लाख रुपये तक होगी. कंपनी ने इस छोटी कार की एक महीने में 8–9 हजार यूनिट बेचने का लक्ष्य रखा है. निसान मोटर इंडिया के वाइस प्रेसीडेंट अजय रघुवंशी का कहना है कि पहली कार गो लॉन्च होगी फिर गो+ और इसके बाद एक और छोटी कार लॉन्च होगी जो अल्टो के सेगमेंट में होगी. लेकिन ये सब डैटसन गो की बिक्री पर भी निर्भर करता है. ■

टीवीएस का नया स्कूटर जुपिटर लॉन्च

भारत में ऑटोमैटिक स्कूटरों के तेजी से बढ़ते हुए चलन को देखकर लगभग सभी टू–व्हीलर कंपनी के प्रोडक्ट(स्कूटर) बाजार में मौजूद हैं. टीवीएस ने इसी में आगे बढ़ते हुए अपना नया स्कूटर जुपिटर पेश किया है. टीवीएस ने इस नए स्कूटर को लाउड स्टाइल डिजाइन दी है जिससे यह स्कूटर ज्यादा बड़े सेगमेंट को टारगेट कर सके, जिसमें युवाओं से लेकर महिलाएं और ज्यादा उम्र के लोग भी शामिल हैं. इसकी डिजाइन पहले के डिजाइनों से ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न है और यह एक यूनिसेक्स स्कूटर है. यह लड़के और लड़कियों दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसके फुट रेस्ट और एग्जॉस्ट साइलेंसर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे बॉडी के साथ अच्छी तरह से मिल गए हैं.

स्कूटर में हैंडल और बैठने की पोजीशन को ध्यान में रखकर आरामदायक डिजाइन किया है, जिससे लंबी यात्रा के दौरान चालकों को जल्दी थकान नहीं होती. इसमें 110 सीसी का इंजन है जो 8वीएचपी की पावर और 8एनएम का टॉर्क देता है. यह इसके सेगमेंट के लिहाज से ठीक है. इसका बेस्ट पार्ट है फ्यूल के लिए कैप सीट के नीचे न लगाकर बाहर लगा होना. इसमें पेट्रोल पंप पर स्कूटर से नीचे उतरकर सीट खोलने का झंझट नहीं है. इसे कार की तरह चाबी से खोला जा सकता है. बाइक की तरह टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और गैस फिल्ड रियर सस्पेंशन दिया गया है. 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स हैं. ज्यादा फ्यूल इकॉनमी पाने के लिए इको लैंप दिया गया है, जो आपको इको फ्रेंडली स्कूटर चलाते समय मदद करता है. हाइबीम के स्विच के साथ पास स्विच भी दिया गया है, जो स्कूटर सेगमेंट में पहली बार है. टीवीएस ने जुपिटर के रूप में एक मॉडर्न और अडवांस फीचर्स वाला प्रॉडक्ट पेश किया है, लेकिन इसका मुकाबला काफी मजबूत खिलाड़ियों के साथ है. जुपिटर की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 44,514 रुपये रखी गई है. ■

स्पाइस ने लॉन्च किया स्मार्टफोन कीमत मात्र 4299 रुपये

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों में अच्छे और सस्तेफोन फोन बनाने की होड़ मची हुई है. स्पाइस ने भी इसी सेगमेंट में एक नया फोन लॉन्च किया है. स्पाइस ने इसको स्मार्ट फ्लो मेटल 4एक्स का नाम दिया है. स्मार्ट फ्लो मेटल 4एक्स (एमआई–426) में बहुत सारी खूबियां हैं. इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस फोन को ऑनलाइन मात्र 4,299 रुपये खरीद जा सकता है. हालांकि इस फोन को आधिकारिक रूप से देश में लॉन्च नहीं किया गया है.

स्मार्ट फ्लो मेटल 4एक्स की खास बांते

प्रोसेसर – 1 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर
ऑपरेटिंग सिस्टम – 4.2 जेली बीन
डिस्प्ले – 4 ईंच टीएफटी एलसीडी, 480X800 पिक्सल रिजोल्यूशन
कैमरा – 3.2 मेगापिक्सल रियर, 1.3 मेगापिक्सल फ्रंट
मेमरी – 256 एमबी रैम
स्टोरेज – 512 एमबी इनबिल्ड, 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है.
बैटरी – 1450 एमएएच

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

भारत को युवाओं का देश कहा जाता है. दुनिया की 13 प्रतिशत आबादी फुटबॉल के ग्लैमर से अब तक अछूती है. भारत जैसे देश में क्रिकेट को धर्म का दर्जा प्राप्त है जो स्थिति ब्राजील में फुटबॉल की है कुछ ऐसा हाल ही भारत में क्रिकेट का है. जिस तरह ब्राजील में हर कोई फुटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना संजोता है उसी तरह भारत में हर कोई क्रिकेट खिलाड़ी बनने का सपना देखता है. ऐसे में भारत में फुटबॉल की जड़ें जमाना आसान नहीं होगा.

फीफा क्यों है भारत पर मेहरबान

भारत में आईपीएल की शुरुआत ने खेल जगत की तस्वीर बदल कर रख दी. आईपीएल ने भारत को दुनिया के एक बड़े खेल बाज़ार के रूप में स्थापित कर दिया. फीफा जैसी खेल संस्था किसी भी तरह भारत में फुटबॉल को स्थापित करके दुनिया के सबसे बड़े और उभरते खेल बाज़ार का दोहन करना चाहती है.

नवीन चौहान

दुनियाभर में भारत की छवि एक ऐसे देश के रूप में स्थापित हो रही है जहां खेलों को विशेष महत्व दिया जाने लगा है. क्रिकेट के अलावा दूसरे खेल भी धीर-धीरे भारत में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं. लेकिन दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल की स्थिति यहां जस की तस बनी हुई है. पारंपरिक रूप से भारत में जिन जगहों फुटबॉल खेली जाती रही है उन जगहों को छोड़ दें तो फुटबॉल गलियों और नुक्कड़ों में खेले जाने वाले खेल में तब्दील नहीं हो सका है. यहां उसका सीधा मुक़ाबला क्रिकेट से है. भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने की दिशा में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा काम करती दिख रही है. उसकी पहल पर भारत को 2017 में होने वाले अंडर-17 विश्वकप की मेजबानी मिल गई है. फीफा भारत के वर्ष 2022 में दोहा में होने वाले सीनियर फुटबॉल विश्वकप के लिए क्वालीफाई करने की संभावनाओं को साकार करने की दिशा में भी काम करता दिख रहा है. इसके इतर एआईएफएफ देश में फुटबॉल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए आईपीएल की तर्ज पर खेली जाने वाली फुटबॉल लीग के आयोजन के लिए पुरजोर कोशिश करता दिख रहा है जिसमें रिलांयस जैसे भारत के बड़े कॉर्पोरेट घराने रुचि दिखा रहे हैं. इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ियों को यूरोपीय लीग में खेलने का मौका मिल रहा है. कोका कोला जैसी कंपनियां भी भारत में फुटबॉल के विकास के लिए उतावली दिख रही हैं. इसके पीछे कोई सकारात्मक सोच नहीं है बल्कि कार्पोरेट घरानों का फायदे का गणित दिखाई दे रहा है. आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है. यूरोप में खेली जाने वाली फुटबॉल स्पर्धाएं भारतीयों को समसामयिक फुटबॉल से जोड़ने में कामयाब तो हुईं लेकिन वे उन्हें फुटबॉल के मैदान तक नहीं ला सकीं. इस वजह से वह फीफा अब दूसरे प्लान पर काम करने लगा है. फुटबॉल को भारत में क्रिकेट जैसा लोकप्रिय बनाने के लिए वह अंडर 17 विश्वकप जैसी प्रतियोगिताओं का सहारा लेता दिख रहा है और इसी राह पर चलकर वह भारत को फीफा विश्वकप के मेन ड्रा में भी पहुंचाना चाहता है.

फीफा की भारत में फुटबॉल के विकास की योजना कोई सामाजिक सरोकार को लेकर नहीं बनाई गई है बल्कि यह एक दीर्घकालिक निवेश है. भारत में फुटबॉल के विकास के मद्देनजर फीफा ने 2011 में अपना दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय, जो श्रीलंका में वर्षों से कार्यरत था, नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है. यह इस बात का सूचक है कि फीफा भारत में चल रही योजनाओं पर सीधे तौर पर नजर रखना चाहता है जिससे कि कम से कम समय में भारत में फुटबॉल को ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय बनाया जा सके. एशिया में फीफा की वरीयता सूची में भारत पहले नंबर पर है. फीफा भारत में यूथ ओरिएन्टेड फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है. द विन इन इंडिया विथ इंडिया नाम से चलाए जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत फीफा ने भारत के सात विभिन्न जोनों में तकनीकी (टेक्निकल) सेंटरों और आठ कृत्रिम टर्फ के निर्माण के लिए 80 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं. इसके अलावा फीफा ने वर्ष 2012 में प्रोजेक्ट गोल के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरू में चार क्षेत्रीय अकादमी के निर्माण के लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया. इन आधारभूत कार्यक्रमों के अलावा फीफा कोचों को प्रशिक्षित करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. क्षेत्रीय अकादमियों में जनवरी 1999 के बाद जन्म लेने वाले खिलाड़ियों को जगह दी गई है जिससे की वे भविष्य में भारतीय फुटबॉल को शिखर पर ले जाने में अपना योगदान दे सकें. एक मुख्य अकादमी के अलावा पांच अतिरिक्त अकादमियों के 2013 में खोले जाने की योजना थी इन अकादमियों का मुख्य लक्ष्य एएफसी कप और फीफा विश्व कप जैसी प्रतियोगिताओं के लिए सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों को तैयार करना है. इंफ्रास्ट्रकचर उपलब्ध कराने के अलावा भारतीय युवा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने का अनुभव देना भी जरूरी है वह भी तब जब भारत की अंडर-16 राष्ट्रीय टीम 2007 और 2011 में एएफसी टूर्नामेंट में क्वालीफाई करने में सफल रही है. इसके लिए भी फीफा काम कर रहा है. इसी कड़ी में भारत को 2017 में होने वाले अंडर -17 विश्वकप का मेजबान बनाया गया है. इसके अलावा भारत 2015 और 2016 में सीनियर स्तर पर होने वाली क्लब चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए भी अपनी दावेदारी पेश करने जा रहा है. इस बात की पूरी संभावना है कि फीफा भविष्य के फायदों को ध्यान में रखते हुए मेजबानी करने का मौका भारत को दे.

भारत को युवाओं का देश कहा जाता है. दुनिया की 13 प्रतिशत आबादी फुटबॉल के ग्लैमर से अब तक अछूती है. भारत जैसे देश में क्रिकेट को धर्म का दर्जा प्राप्त है जो स्थिति ब्राजील में फुटबॉल की है कुछ ऐसा हाल ही भारत में क्रिकेट का है. जिस तरह ब्राजील में हर कोई फुटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना संजोता है उसी तरह भारत में हर कोई क्रिकेट खिलाड़ी बनने का सपना देखता है. ऐसे में भारत में फुटबॉल की जड़ें जमाना आसान नहीं होगा. युवाओं के जिस पूल से फुटबॉल खिलाड़ी निकालने हैं वो क्रिकेट के दीवाने हैं. जब तक युवाओं को उनका करियर पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में फलता-फूलता नहीं दिखाई देगा तब तक वे फुटबॉल को गंभीरता से नहीं लेंगे और उसकी तरफ रुख नहीं करेंगे. चीन दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है जहां फुटबॉल लोकप्रिय हो चुका है. इस सूची में भारत का नाम ही मिसिंग है. भारत जैसे दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देश में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने की अपार संभावनाएं हैं. फीफा के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी है. क्योंकि भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाए बिना वह रेवेन्यू में इज़ाफा नहीं कर सकता है. यूरोप और अमेरिकी देशों के खेल बाजार में सेचुरेशन की स्थिति आ गई है. दुनिया का हर एक खेल संगठन भारत की ओर रुख कर रहा है. ये उनकी मजबूरी है. दुनिया के कई देश एक साथ मिलकर भी भारत जितना बड़ा खेल बाज़ार उपलब्ध नहीं करा सकते हैं. इसलिए वे भारत को हर मामले में सर्वोच्च वरीयता देने लगे हैं. इसी वजह से भारत को अंडर-17 विश्वकप की मेजबानी दिए जाने की पहल फीफा के आलाधिकारियों ने ही की थी.

खैर, भारत को 2017 में होने वाले अंडर-17 फीफा विश्वकप की मेजबानी मिल गई है. जब सारी दुनियां की नज़रें 2014 में ब्राजील में होने वाले विश्वकप के संभावित विजेता के ऊपर टिकी हुई है. तब भारत के 2022 में कतर में होने वाले फीफा विश्वकप में क्वालीफाई करने पर अटकलें लगने लगी हैं. भारत ने मेजबानी की दौड़ में शामिल अन्य देशों दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और उज्बेकिस्तान को पीछे छोड़ा और प्रत्येक दो वर्ष में होने वाले 24 देशों के इस टूर्नामेंट के आयोजन का अधिकार पाया. मेजबान देश होने के कारण भारत अपने इतिहास में पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग लेगा. यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत इस मौके को विश्व फुटबॉल पटल पर स्थापित करने के लिए उपयोग कर पाएगा? क्या फीफा का पहला दांव सफल होगा? अंडर-17 विश्व कप के आयोजन में अभी तीन साल हैं. इन तीन सालों में भारत को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, साथ ही खिलाड़ियों का एक ऐसा पूल बनाना है जो पेशेवर भी हों और प्रतिभाशाली भी जो कि ब्राजील, जर्मनी और स्पेन जैसी टीमों के साथ दो-दो हाथ करने का माद्दा रखते हों और भारत को फुटबॉल के शिखर पर भी पहुंचा सकें. जिससे न केवल देश के लोगों के दिलो-दिमाग पर छाए रहने वाले क्रिकेट का मायाजाल भंग हो और भारतीय युवा विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल की ओर रुख करें.

देश में फुटबॉल का कायाकल्प करने की प्राथमिक जिम्मेदारी अखिल भारतीय फुटबॉल संघ (एआईएफएफ) की है जिसके कंधों पर भारतीय फुटबॉल के विकास का पूरा भार है. भारत सरकार उसका केवल बाहर से सहयोग कर सकती है. लंबे इंतजार के बाद हाथ में आए इस मौके को किस रणनीति के तहत एआईएफएफ किस तरह उपयोग करता है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वह तीन साल के थोड़े से वक्त में किस तरह इस आयोजन को सफल बना पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा. भारत को इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी छह से आठ शहरों में करनी होगी. नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, मडगांव, कोच्चि और बेंगलुरु आदि शहर मेजबान हो सकते हैं. क्योंकि इन शहरों में पहले से ही फुटबॉल के मैदान हैं. उपलब्ध खेल मैदानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना, नई सुविधाएं डेवलप करने से बेहतर विकल्प है. लेकिन मैंगलोर में फुटबॉल मैच से ठीक पहले दर्शक दीर्घा का ढह जाना भी पहले से स्थापित इंन्फ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करता है. नई सुविधाएं विकसित करने की बात सामने आते ही राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान हुए घोटालों की तस्वीर सामने आ जाती है, जहां समय रहते कोई भी काम पूरा नहीं हो सका था. अंडर-17 विश्वकप की तैयारी के लिए जो वक्त है वह राष्ट्रमंडल खेलों की तुलना में बेहद कम है.

फीफा को भारत में फुटबाल के विकास की अपार संभावनाएं नज़र आती हैं. फीफा का मानना है कि यदि भारत इस टूर्नामेंट का आयोजन करेगा, तो स्वाभाविक रूप से इस खेल को देश में लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी. भारत के लिए मेजबानी हासिल करने की राह आसान नहीं रही. जनवरी में भारत की शुरुआती बोली नामंजूर कर दी गई, क्योंकि फीफा सरकार से कई विषयों पर स्पष्ट गारंटी चाहता था. सरकार से गारंटी मिलने के बाद एक प्रकार से पूर्वनियोजित तरीके से भारत को मेजबान घोषित कर दिया गया.

फीफा के अलावा अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल क्लबों ने भी भारतीय बाजार पर कब्जा करने का फैसला किया है. मैनेचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल जैसे क्लबों ने भारत में फुटबॉल स्कूल खोले हैं. मैनेचेस्टर युनाइटेड ने वर्ष 2011 में मुंबई में और आर्सेनल ने दिल्ली में फुटबॉल प्रशिक्षण स्कूल खोले हैं. कुछ यूरोपीय क्लबों ने पहले से कार्य कर रहे फुटबॉल स्कूलों के साथ समझौते किए हैं. स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने कोलकाता में फुटबॉल अकादमी खोलने का निर्णय लिया है. पिछले साल अक्टूबर में लीवरपूल ने महाराष्ट्र के पुणे में फुटबॉल स्कूल की शुरुआत की है, जो कि सर्वसुविधायुक्त है. यह स्कूल 18 से 19 वर्ष तक के भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करेगा. बायर्न म्युनिख और चेल्सी जैसे क्लबों में भी भारत में निवेश करने संबंधी बातें हो रही हैं.

भारतीय खिलाड़ी भी विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में भारतीय टीम के गोलकीपर सुब्रतो पॉल किसी यूरोपीय प्रथम श्रेणी टीम की ओर से खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं. उन्हें डेनमार्क के वेस्ट्रज्जालैंड क्लब की ओर से खेलने का मौका मिला है. इस क्लब को एफसी वाइकिंग्स के नाम से भी जाना जाता है. पिछले साल भारतीय कप्तान सुनील क्षेत्री को भी पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब लिस्बन की ओर से बी लीग में खेलने का मौका मिला था. यह एक तरह से अंतरराष्ट्रीय भारतीय फुटबॉल स्टार बनाने की कवायद है जिसे धीरे-धीरे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है. एक साथ बहुत से क्लबों में भारतीयों की उपस्थिति कई सवाल खड़े कर सकती है. इसलिए इस योजना पर धीरे-धीरे काम हो रहा है.

कुछ सालों से दुनियाभर के अधिकांश खेल आयोजन ब्रिक्स देशों(ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) में हो रहे हैं. जैसे कि 2008 के ओलंपिक चीन के बीजिंग में, 2010 में राष्ट्रमंडल खेल भारत के नई दिल्ली में, 2010 के एशियाई खेल चीन के ग्वांगजू में, 2010 में फीफा विश्वकप दक्षिण अफ्रीका में, 2014 में शीतकालीन ओलंपिक सोची (रूस) में, 2014 का फीफा विश्वकप ब्राजील में, 2018 का फीफा विश्वकप रूस में, 2016 के ओलंपिक रियो डि जेनेरियो ब्राजील में आयाजित हो रहे हैं. दुनिया में खेलों का पहिया इन्हीं पांच देशों के इर्द गिर्द होकर गुजर रहा है. इसलिए बड़े खेल आयोजनों के लिए भारत को तैयार करना पश्चिमी देशों की मजबूरी है. क्योंकि 2004 में एथेंस ओलंपिक के आयोजन के बाद ग्रीस की अर्थव्यवस्था के लड़खड़ा जाने के बाद यूरोपीय देश इस तरह के आयोजनों से बचते दिख रहे हैं. कम समय अंतराल पर एक देश को दोबारा इन खेलों का मेजबान भी नहीं बनाया जा सकता है. इसलिए भारत को जल्दी ही बलि का बकरा बनाने के लिए नीतिगत तौर पर तैयारी हो रही है. राष्ट्रगौरव के नाम पर खेलों का आयोजन करना देश के लोगों के लिए कैसा होता है, इसे ब्राजील में साफ तौर पर देखा जा सकता है. ब्राजील में फुटबॉल विश्वकप और ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था भारत जैसे देश को प्रतियोगिता का मेजबान बना सकने में सहायक हो सकती है, लेकिन खेल का स्तर सुधारने के लिए व्यापक बदलाव करने होंगे. फीफा किसी तरह इस बात को सुनिश्चित करने में लगा है कि भारत फुटबॉल के मैदान में एक बार फिर से अपने चरम पर या उससे बेहतर स्थिति में पहुंचे. दोनों परिस्थितियों में दोनों पक्षों की जीत होगी. फीफा भारतीय फुटबॉल के उत्थान के नाम पर भारतीय बाज़ार का दोहन करने की तैयारी में जुटा है और भारत फुटबॉल की दुनिया में अपने सितारों को चमकते देखना चाहता है. यही दोनों को भारतीय फुटबॉल के कायाकल्प के लिए प्रेरित कर रहा है. यहां सबके अपने स्वार्थ हैं. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
16
06 जनवरी 2014–12 जनवरी 2014

2014 कैलेंडर

JANUARY 2014

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

FEBRUARY 2014

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

MARCH 2014

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

APRIL 2014

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

MAY 2014

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

JUNE 2014

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

JULY 2014

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

AUGUST 2014

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

SEPTEMBER 2014

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

OCTOBER 2014

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

NOVEMBER 2014

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

DECEMBER 2014

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

वर्ष के प्रमुख अवकाश

- 14 जनवरी मकर संक्रांति/ ईद-उल-मिलाद
- 26 जनवरी गणतंत्र दिवस
- 27 फरवरी महाशिवरात्रि
- 17 मार्च होली
- 13 अप्रैल महावीर जयंती
- 18 अप्रैल गुड फ्राइडे
- 01 मई मजदूर दिवस
- 14 मई बुद्ध पूर्णिमा
- 29 जुलाई ईद-उल-फितर
- 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
- 18 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी
- 29 अगस्त गणेश चतुर्थी
- 02 अक्टूबर गांधी जयंती
- 03 अक्टूबर विजयदशमी-दशहरा
- 06 अक्टूबर ईद-उल-अज़हा (बकरे-ईद)
- 23 अक्टूबर दीपावली
- 04 नवंबर मुहर्रम
- 06 नवंबर गुरुनानक जयंती
- 25 दिसंबर क्रिसमस

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 10 अक्टूबर–16 अक्टूबर 2011

www.chauthiduniya.com

Acres of priceless lifestyles for the matchless few!

Swimming Pool | Gym | Spa | Club House | Play School | Modern Shopping Complex | Hospital | Auditorium

SAIL CITY

A GIFT TO RANCHI

Behind DPS / Opp. Vidhan Sabha

Club House with Garden | Grand Entrance

TOTAL 1719 UNITS

Project approved by SBI, AXIS, UCO ,LIC, HDFC, IDBI

Model Flat & Club House Ready

2/3 BEDROOM FLATS

KASHISH DEVELOPERS LIMITED

Corporate Office : 87, Old A.G. Colony, Kadru, Ranchi - 834002, Jharkhand
Tel : 0651-2341269 - (5 Lines) Fax : 0651-2341273
Patna Office : 12A, Patliputra Colony, PATNA-13
Ph : 0612-2260220 (2 Lines), Tel Fax : 0612-2260223
E-mail : info@kashishgroup.com : www.kashishgroup.com

For Booking : 8873002015/16/17/18/19, 9470520015/16/17/18/19

भोज की सियासत

फोटो– संजय कुमार

सरोज सिंह

बिहार भाजपा इन दिनों एक हसीन सपने को साकार करने में रात दिन जुटी है. दरअसल, पिछले चुनाव में मिले जनता के समर्थन ने भाजपा को हसीन सपने देखने का हक़दार बना दिया. केंद्र व बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाले इस सपने के केंद्र में संगठन की ऐसी मज़बूती है, जो हर लिहाज़ से परिणाम देने वाली हो. इस सपने को साकार करने के लिए भाजपा ने भोज की सियासत शुरू की है. भाजपा ने बहुत ही संजीदगी से इस भोज की सियासत का तानाबाना बुना है और दीनदयाल उपाध्याय की जयंती यानी 25 सितंबर को इसका आगाज़ किया.

माना जा रहा है कि भाजपा के चिंतकों ने बिहार के सामाजिक और राजनीतिक तानेबाने पर पिछले दिनों बेहद गंभीर चिंतन किया. राय बनी कि सवर्णों में पार्टी के प्रति आकर्षण बरक़रार है और यह आगे भी जारी रहेगा. भाजपा ने अपनी कमज़ोर कड़ियों को मंथन शिविरों में जमकर तलाशा. राय बनी कि पार्टी को दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों के बीच जमकर काम करना चाहिए. बिहार में सत्ता में आने के बाद भाजपा इन वर्गों में खुलकर काम नहीं कर पाई थी. ख़ासकर महादिलतों की बस्तियां तो एजेंडे से ग़ायब ही रहीं. ऐसा इसलिए भी हुआ कि नीतीश कुमार ने जब महादलित आयोग का गठन किया तो ऐसा संदेश गया कि इस पूरे तबक़े को जदयू ने पेटेंट करा लिया. इसका लाभ भी पिछले चुनाव में जदयू को मिला. इसी बात को मन में बैठाए भाजपा पूरे पांच साल चुप रही, लेकिन अब वह महसूस करने लगी कि महादलितों के बीच जाकर उनसे सीधा संपर्क करने का समय आ गया है. ऐसा इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि नरेंद्र मोदी के नए अवतार ने जदयू–भाजपा की गांठों को कमज़ोर करना शुरू कर दिया है. बाहर दोनों दलों के नेता जो बोलें, पर अंदरख़ाने इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे–जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे–वैसे गठबंधन की राह कठिन होती चली जाएगी और नरेंद्र मोदी के बिहार पहुंचते ही पर्दा उठ जाएगा.

दअसल इसी पृष्ठभूमि में भाजपा अपनी सारी तैयारियों को अंजाम दे रही है. दलित व अल्पसंख्यकों पर भी भाजपा की पैनी नज़र है. इनके लिए भी कई नए कार्यक्रम शुरू करने की योजना है. भाजपा नेता किरण घई कहती हैं कि महादलितों के बीच जाना पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है. हम चाहते हैं कि समाज का हर अंग आगे बढ़े और समाज की मुख्यधारा से जुड़े. प्रदेश महामंत्री मंगल पांडेय की मानें तो भाजपा का यह कार्यक्रम किसी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए नहीं है. वास्तव में भाजपा को उनके दर्द का अहसास है और पार्टी की कोशिश है कि उनके जख्मों पर मरहम लगाया जाए. सहभोज से महादलितों के दिलों में विश्वास पैदा होगा और उन्हें लगेगा कि वे भी विकास की पूरी प्रकिया में सहयोग कर सकते हैं. लेकिन राजद के वरिष्ठ नेता नवल यादव इसे ढकोसला क़रार देते हैं. उनका मानना है कि महादलितों के दर्द से भाजपा का कुछ लेना देना नहीं है. जदयू पर दबाव बनाए रखने के लिए यह सब किया जा रहा है. दरअसल, भाजपा में दो गुट हो चुके हैं. एक आडवाणी का और एक नरेंद्र मोदी का. यह सारा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी को मज़बूत करने के लिए किया जा रहा है.

उधर, आडवाणी की रथयात्रा का शुभारंभ पहले गुजरात से होने की बात थी, लेकिन बाद में बिहार के सिताब दियारा को तय किया गया. राजनीतिक विश्लेषक इसे भी भाजपा की बिहार में अपनी ताक़त बढ़ाने की क़वायद के तौर पर देख रहे हैं. माना जा रहा है कि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बिहार को भाजपा कितना तवज्जो दे रही है. भाजपा ने इस रथयात्रा के शुभारंभ के मौक़े पर नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया है. भाजपा के कुछ नेता मान रहे थे कि शायद नीतीश कुमार इस न्योते को न मानें, लेकिन नीतीश राजनीति का रुख़ अब बख़ूबी पहचानना सीख गए हैं. उन्होंने बिना देर किए न्योता स्वीकार कर लिया. अगले दिन जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि जदयू के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे. माना यह जा रहा है कि जदयू की सोच यह रही कि भाजपा को अपने बलबूते अपनी ताक़त दिखाने का मौक़ा न दिया जाए. भीड़ उमड़ी तो संदेश जाएगा कि यह नीतीश का करिश्मा है. हालांकि नीतीश के इस फ़ैसले से जदयू के कुछ मुस्लिम नेताओं में नाराज़गी है, पर वे खुलकर बोलने से बचना चाहते हैं. फ़िलहाल दोनों ओर से तैयारी है और कोशिश आगे निकलने की है.

feedback@chauthiduniya.com

दरौंदा उपचुनाव

टिकट वितरण का नीतीश फॉर्मूला

धनंजय मिश्र

दरौंदा विधानसभा उपचुनाव में राजग और राजद आमने–सामने हैं. जदयू तो इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए है. दरअसल, विगत विस चुनाव में इस सीट से जदयू नेत्री जगमातो देवी भारी मतों से जीती थीं, उनके निधन के बाद जदयू इस सीट को दोबारा पाना चाहता है. इसलिए जदयू प्रत्याशी कविता सिंह के नामांकन के दौरान राजग के कई मंत्री और वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे, जबकि अपने पसंदीदा उम्मीदवार परमेश्वर सिंह को राजद का टिकट दिलाने में सफल रहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह यह ऐलान कर चुके हैं कि यह चुनाव परमेश्वर सिंह नहीं, बल्कि मैं ख़ुद लड़ रहा हूं. प्रभुनाथ सिंह का इस क्षेत्र में पहले से ही सबल जनाधर रहा है. परंतु गत वर्ष जदयू से नाता तोड़कर वह राजद में शामिल हो गए. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज़ प्रभुनाथ सिंह इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए हैं.

पिछले लोकसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह हार गए और राजद प्रत्याशी उमाशंकर सिंह सांसद बन गए. दोनों इस क्षेत्र का लंबे समय से प्रतिनिधित्व भी करते रहे हैं. दोनों बाहुबली हैं और घोर विरोधी भी. उमाशंकर सिंह भी यह ऐलान कर चुके हैं कि वह परमेश्वर सिंह का समर्थन नहीं करेंगे. परमेश्वर की जीत के प्रश्न पर वह असंभावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि परमात्मा ही जाने! दरौंदा के प्रबुद्ध मतदाता कविता सिंह को टिकट देने के नीतीश के निर्णय पर कहते हैं कि नीतीश कहते कुछ हैं और करते कुछ. सुशासन पर बिहारियों को कितना भरोसा है, यह दीगर बात है. पर संभवत: सुशासन पर स्वयं उनका भरोसा कम होता जा रहा है. मतदाताजन अनेक सवाल उठाते हैं. क्या गंदगी से गंदगी साफ़ हो सकती है. इसके लिए तो स्वच्छ जल की ज़रूरत होती है. तब फिर नीतीश स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट देने से परहेज़ क्यों कर रहे हैं? क्या वह उस पुरानी राजनीति के अभी भी आदी हैं कि लोहा ही लोहा को काटता है. इस नीति से वह बिहार में राजनीतिक अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण को कैसे ख़त्म करेंगे, जबकि वह इसके ख़ात्मे का ऐलान करते रहे हैं. वह यह भी कहते हैं कि दिवंगत विधायक जगमातो देवी कम पढ़ी–लिखी होने के बावजूद सूझ–बूझ वाली प्रौढ़ महिला थीं. वह राजनीति में कैसे आईं, इसको जानते हैं.

वर्ष 2005 के रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव की बात है. इसके पहले जगमातो देवी का राजनीति से दूर–दूर का कोई नाता नहीं था. सो वह तब चर्चित भी नहीं थीं. हां, उनके छोटे सुपुत्र अजय सिंह चर्चित ज़रूर थे. इसका मुख्य कारण यह था कि वह राजद शासनकाल के दौरान सीवान ज़िले के दक्षिणांचल में व्याप्त अपराधक्रमों में कुख्यात अपराधी के रूप में जाने जाते थे. वह कुछ वर्षों तक इस क्षेत्र के दुर्दांत ख़ान ब्रदर्स के कथित शार्गिद भी थे. उसी दौरान ख़ान ब्रदर्स यानी कुख्यात अयूब–रईस दोनों सहोदर भाइयों से उनका कुछ मनमुटाव हो गया. भयवश अजय सिंह ने ख़ान ब्रदर्स से अलग होकर अपना अलग एक छोटा गिरोह तैयार कर लिया. इस दरम्यान दक्षिणांचल के इस दियारा क्षेत्र में ख़ान ब्रदर्स गिरोह का आतंक दिनोंदिन बढ़ता जा रहा था. जिस गिरोह के आतंक से ख़ासकर अधिकांश हिंदू भयभीत रहते थे. उसी दौरान 2005 में रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव में कोई दलीय टिकट न मिलने पर ख़ान ब्रदर्स के पिता एवं सेवानिवृत पुलिस पदाधिकारी कमरूल हक़ बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी दंगल में कूद पड़े. वह इसी विस क्षेत्र के सिसवन प्रखंड के ग्यासपुर गांव के निवासी हैं. हिंदुओं को लगा कि कमरूल हक़ अगर चुनाव जीत गए और विधायक बन गए तो उनके बेटों का आतंक और बढ़ जाएगा. इसलिए उन्हें हराने के लिए हिंदुओं ने एकजुट होकर अजय सिंह की माता जगमातो देवी को भी निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करा दिया. उस चुनाव में वह जीत गईं, लेकिन राजग की बिहार में बनती सरकार और सत्ता–सुख, सहयोग, सुरक्षा के निहितार्थ उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया. ग़ौरतलब है कि वह भावुकतावश नीतीश कुमार को अक्सर बेटा कहती थीं और नीतीश मंद मुस्कान बिखेरते हुए विधायक माताश्री का यह संबोधन स्वयं के लिए संभवत: आशीर्वाद समझते थे. यह नाता सुदृढ़ होता गया. उसी दरम्यान नए परिसीमन बनने से

– शेष पृष्ठ संख्या 18 पर –

बाढ़ के दिनों में इस क्षेत्र में अधिकांश पुरुष मज़दूरी के लिए बड़े शहरों में पलायन कर जाते हैं, वहीं घर गृहस्थी की ज़िम्मेदारी महिलाओं को संभालनी पड़ती है.

ठंड में बच्चों का ख़ास ख्याल रखें: राय

मौसम बदलने के कारण बच्चों में अनेक बीमारी हो सकती है, अत: उनकी उचित देखभाल ज़रूरी है. पूर्णिया के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. हरिनंदन राय का कहना है कि मौसम में परिवर्तन के कारण बच्चे विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं. जैसे-कोल्ड डायरिया व निमोनिया आदि. इनसे बचाव के लिए आस-पास की सफ़ाई, कपड़े, नाख़ून की सफ़ाई, साफ़-सुथरे बिस्तर का उपयोग, गर्म कपड़े से ढक कर रखना और उबला हुआ पानी पिलाना चाहिए. बच्चों को बदलते मौसम की धूप में ले जाने से परहेज़ करना चाहिए...

डॉ. हरिनंदन राय

नीरज कुमार सिंह

गया ज़िला परिषद
चार वर्षों से वेतन नहीं मिला

सुनील सौरभ

मंत्रियों के रिश्तेदारों को मिली बियाडा की ज़मीन : ललन सिंह

नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ बग़ावत का झंडा बुलंद करने वाले मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह अब जनता की अदालत में राज्य सरकार को बेनक़ाब करने का अभियान शुरू करेंगे. दिशाहीन और कमज़ोर विपक्ष से निष्कंटक राज भोग रही नीतीश सरकार को घेरने के लिए किन मुद्दों के सहारे ललन सिंह सरकार की पोल खोलेंगे, जानने की कोशिश की चौथी दुनिया संवाददाता दिव्या कुमारी ने. प्रस्तुत है प्रमुख अंश.

बिहार सरकार सांसद निधि पर सवाल उठा रही है, क्यों?

सरकार सवाल उठा नहीं रही है, बल्कि कमीशन मांग रही है. बिहार सरकार देश की इकलौती ऐसी सरकार है, जो सांसद निधि में कमीशन मांग रही है. सरकार विकास योजनाओं में प्रति सांसद मिलने वाली पांच करोड़ की राशि में दस फ़ीसदी अतिरिक्त राशि की मांग कर रही है और कहती है कि दस प्रतिशत कमीशन नहीं मिला तो योजनाओं का...

अपनी रिपोर्ट में साफ़ कहा है कि मात्र 68 करोड़ के वास्तविक वाउचर सरकार ने दिए हैं तथा ग्यारह हज़ार करोड़ के नक़ली और जाली वाउचर जमा कराए गए हैं. सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा को सौंपी गई है. पचास हज़ार करोड़ की वित्तीय अनियमितता है और सरकार वित्तीय अनुशासन का राग अलाप रही है.

दुर्बलता के ख़िलाफ़ युद्ध करना होगा

साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा. पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता. इसे भगाओ, जितना शीघ्र सम्भव हो, रक्तशोषणकारी अवसाद-उत्पादक वैमपायर(एक तरह का जन्तु, जो सुप्तावस्था में किसी जीवजन्तु का रक्त चूसता है) को स्मरण करो. तुम साहसी हो, स्मरण करो तुम शक्ति के तनय हो, स्मरण करो तुम परमपिता की सन्तान हो. पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तभी समझा जायेगा कि धर्मराज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार हुआ है.

थोड़ी सी भी दुर्बलता रहने पर तुम ठीक-ठाक अकपट नहीं हो सकोगे, और जब तक तुम्हारे मन-मुख एक नहीं होते तब तक तुम्हारे अन्दर की मलिनता दूर नहीं होगी...

सुन्ना सिंह

कुशेश्वर वासियों को
बाढ़ का इंतज़ार रहता है

इस प्रखंड के हर घर में नाव उपलब्ध है और तो और आज भी शादी-विवाह में मोटरसाइकिल की जगह दहेज में नाव दी जाती है. एक ख़ास बात यह है कि यहां की महिलाएं और बच्चे भी नाव चलाने एवं तैराकी में पारंगत होते हैं.

बाढ़ को जहां उत्तर बिहार का अभिशाप माना जाता है, वहीं कुछ स्थानों पर बाढ़ का न आना भी अभिशाप बन गया है. दरभंगा ज़िला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुशेश्वर स्थान की अजीब कहानी है. यह स्थान मिथिलांचल का महत्वपूर्ण धार्मिक...

है. दरभंगा ज़िले में कुशेश्वर स्थान पूर्वी और पश्चिमी प्रखंड बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है. कोसी नदी का क़हर लगभग 6 से 8 महीनों तक यहां के जनजीवन को प्रभावित करता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि यहां के लोगों के लिए बाढ़ क़हर नहीं वरदान साबित हो रही है. जहां एक ओर बाढ़ का पानी आता है और...

नवीन चौधरी

मवेशी बचाओ घास ट्रेन

राजेश सिन्हा

अभी तक आपने राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के विषय में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि खगड़िया-सहरसा के बीच मवेशी बचाओ घास ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ सरपट दौड़ रही है. इस ट्रेन पर सफ़र करना आम यात्रियों के लिए भले ही दुख भरा अनुभव रहा हो, लेकिन उत्तर बिहार के बाढ़ ग्रस्त इलाक़े के लोगों के लिए मवेशी बचाओ घास ट्रेन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही है. बाढ़ की विनाशलीला से परेशान लोग किसी तरह अपने पेट की आग तो बुझा ले रहे हैं, लेकिन मवेशियों के लिए चारा लाना...

कारण चारे की व्यवस्था कर पाना पशुपालकों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है. बरौनी सहित अन्य इलाक़ों से घास लाकर किसी तरह वे पशुओं को ज़िंदा रख पा रहे हैं. उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बाढ़ आने के बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण कर यह ऐलान कर दिया कि सभी बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत वितरण का आदेश दे दिया गया है. पशुओं को चारा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया है. लेकिन हक़ीक़त यही है कि बाढ़ प्रभावितों के बीच न ही पर्याप्त राहत की व्यवस्था की गई है और न ही पशुओं को चारा उपलब्ध कराया गया है. खगड़िया और सहरसा के कई इलाक़ों में इन दिनों बाढ़ के कारण चारों तरफ़ पानी फैल गया है. इससे कई पशुपालक तो अपने पशुओं के साथ सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं, लेकिन जो बच गए हैं उनके लिए...

इंदिरा आवास योजना में घपलेबाज़ी का विरोध
मुखिया जी को महंगा पड़ा

इंदिरा आवास योजना उन ग़रीबों के लिए बनाई गई है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है. पंचायत स्तर पर उन ग्रामीणों का चयन किया जाता है जो इस योजना के अंतर्गत मकान पाने के हक़दार होते हैं. इसके लिए लिस्ट बनाई जाती है जिसमें लाभार्थियों के नाम शामिल किए जाते हैं. बस इसी लिस्ट में असली हेर-फेर होती है. और सच की आवाज़ बुलंद करने वालों के ख़िलाफ़ साज़िश भी शुरु हो जाती है.

राजेश एस कुमार

मामला इंदिरा आवास योजना में चल रही घपलेबाज़ी का है. गया ज़िले के टिकारी प्रखंड अंतर्गत केसपा पंचायत में इंदिरा आवस योजना के अंतर्गत जिन लोगों की सूची बनती है, उसमें अनियमितताएं बरती जा...

कि इंदिरा आवास योजना में ठगी के चलते पंचायत सेवक पर प्राथमिकी दर्ज करने पर उनको धमकी मिल रही हैं. धमकाने वालों में पंचायत समिति सदस्य सुबोध कुमार, उपमुखिया पति अमित कुमार तथा अलीपुर के थाना प्रभारी इंद्र देव ठाकुर के नाम का ज़िक्र किया गया है. नरेंद्र ने जनता दरबार में ख़ुद को धमकी देने की बात कही ही थी कि उसके कुछ...

दरौंदा उपचुनाव
टिकट वितरण का नीतीश फॉर्मूला

- पृष्ठ 17 का शेष -

...असमर्थता महसूस कर रहा था, क्योंकि अजय पर अनेक आपराधिक मामले थाने और न्यायालयों में लंबित हैं. दूसरी ओर अजय की बदौलत इस चुनाव में जदयू की जीत दर्ज कराने को आतुर जदयू के ही कुछ वरीय नेताओं ने ज़ोर देकर भारतीय सनातन धर्म, पंथ, संस्कृति और परंपरा के विरुद्ध पितृपक्ष में ही 17 सितंबर को महेंद्र नाथ मंदिर में अजय और कविता की शादी करा दी. राजनीति का यह नया करिश्मा लोगों ने देखा-सुना और अचरज भी व्यक्त किया. इस क्षेत्र के आम मतदाताओं का कहना है कि इस उपचुनाव में कांटे की लड़ाई कविता सिंह और परमेश्वर सिंह के बीच ही होने की प्रबल संभावना है. हालांकि विगत विस चुनाव की भांति इस बार भी आम मतदाता राजद के साथ ध्रुवीकृत होते नहीं दिख रहे हैं. ख़ासकर प्राय: सवर्णजन अभी-भी-राजद से दूरी बनाए हुए हैं. दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव का पुरातन माय समीकरण राजद के साथ तेज़ी से गोलबंद और सशक्त होता जा रहा है. हालांकि प्रभुनाथ सिंह के कारण राजद प्रत्याशी एवं कराड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया परमेश्वर सिंह को भी सवर्णों के अच्छे-ख़ासे वोट मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है. मतदाताओं के मध्य यह भी चर्चा है कि परमेश्वर स्थानीय नेता हैं. वह दरौंदा प्रखंड अंतर्गत दौन छपरा गांव के वासी हैं, जबकि जदयू की प्रत्याशी कविता सिंह के पति अजय सिंह रघुनाथपुर प्रखंड के नंदा मुड़ा गांव के हैं, जो इस क्षेत्र के लिए बाहरी हैं. मतदाताओं का यह भी कहना है कि कविता सिंह विधायक बन गईं तो असली विधायकी तो उनके कुख्यात पति अजय सिंह ही करेंगे. इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी एवं प्रसिद्ध चिकित्सक कालिका शरण सिंह भी अपना भाग्य...

Wishing you a Happy Durga Puja — Oriskon Pharma Pvt.Ltd. — ASRFEN-P — ECTALOPAM — SILIPLEX — ACOBA CAP/SYP/INJ — Carbo-XT — AREX — MENSOSET — MUSTAL

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT — FREE — 410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001

Enjoy with Nature — MOULDED FURNITURE — NATURE — 1 YEAR GUARANTY — Contact : 9386595926, 9334115955

यशराज बिल्डर्स की नई पेशकश

Yash Raj Holiday Joy of Life....! Homes

NH-33 (रांची–पटना रोड) National Highway पर बिरसा जैविक उद्यान के समीप

1500 प्लॉट, सिम्पलेक्स एवं डुप्लेक्स की विश्वस्तरीय सर्व सुविधायुक्त आवासीय कॉलोनी

3.51 लाख से PLOT शुरु

9.51 लाख से मकान शुरु

*Condition Apply.

Our Amenities :

- Commercial Complex
- Community Hall
- Club House
- Gym
- Garden and Children Park
- Play School
- Swimming Pool
- Security

ARIEL VIEW

Yash Raj Enterprises Pvt. Ltd.

AN ISO 9001-2008 CERTIFIED COMPANY.

Excellence in Real Estate

Promoter / Developer / Marketer / Service Provider

1st Street, Karamtoli, Ranchi-8, Ph.: 9234680786, 9234601786, 9234602786, 9234603786, Dhanbad & Bokaro : 9234674786, Jamshedpur : 9234699786, Hazaribag : 9234676786, Palamau : 9234675786, Khalari : 9234697786, Gumla : 9234698786

Helpline : 9263187111 / 222/333, 0651-6570601 • E-mail : yashraj221@gmail.com • Website : yashrajenterprises.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

06 जनवरी 2014–12 जनवरी 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

राहत कैम्पों में सियासी पैंतरेबाजी

अजय कुमार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगों के अभिशाप से समाजवादी पार्टी मुक्त नहीं हो पा रही है. मुजफ्फरनगर और शामली में साम्प्रदायिक हिंसा के लम्बे दौर के बाद आज की तारीख में जिंदगी भले ही ढर्रे पर चलती दिख रही हो, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है. छोटी-छोटी बात पर लोगों का गुस्सा सड़क पर आ जाता है तो राहत कैम्पों में जीवन बसर कर रहे शरणार्थियों से जुड़ी दर्दनाक खबरें भी सुर्खियां बनना बंद नहीं हुई हैं. कैम्पों में रहने वाले दंगा पीड़ितों को राशन, गरम कपड़ों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई व्यवस्था जैसी तमाम परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है. सरकार और प्रशासन की लापरवाही से दर्जनों बच्चों की जीवनलीला समाप्त हो चुकी है. ऐसा नहीं है कि राहत शिविरों में रहने वालों का कोई हमदर्द नहीं है, लेकिन बिना स्वार्थ के उनके लिए कोई काम नहीं करना चाहता है. मदद के नाम पर कोई राजनीतिक रोटियां सेंकता है तो कोई पैसे का बंदरबांट करता है. राहत के पैसे और सामान में सेध लगाने वालों की संख्या भी कम नहीं है. स्थिति यह है कि आज कोई भी साहस करके सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता है. अगर कोई मुंह खोलता भी है तो इसे मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाता है.

मौजूदा हालात पर नजर डाली जाए तो आज की तारीख में राहत कैम्पों में सिर्फ पीड़ित ही नहीं रह रहे हैं. अगर कुछ पीड़ित हैं तो कुछ ऐसे लोग भी यहां जुट गए हैं, जो सरकारी मुआवजे की लालच में यहां आकर बस गए हैं. चुनावी मौसम में कुछ न कुछ मिल जाने की उम्मीद ने समाजवादी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. यही वजह थी कि जिस दिन अखिलेश सरकार ने दंगा पीड़ितों को पुनर्वास के लिए पांच लाख रुपये देने की घोषणा का ऐलान किया, उसी दिन यहां सैकड़ों नये कैम्प लग गए थे. यह तथ्य भी चौंकाने वाला है कि कुछ कैम्प निजी स्तर पर चलाए जा रहे हैं. यह कोई नहीं जानता है कि निजी स्तर पर राहत शिविरों का संचालन किसकी शह पर हो रहा है. दंगा पीड़ितों के लिए आने वाला पैसा कई लोगों की जेब भरने का साधन बना हुआ है. इसलिए ऐसे लोग तो यही चाहते हैं कि शरणार्थी शिविर चलते रहें.

निश्चित तौर पर राहत कैम्पों की सियासत की आग से आज समाजवादी सरकार और इसके नेताओं के हाथ झुलस रहे हों, लेकिन इस आग को हवा देने वाले भी यही हाथ थे. इसने आग बुझाने की बजाए राजनीति ज्यादा की. अखिलेश सरकार दंगा पीड़ितों की समस्याओं को दूर करने की बजाए उन लोगों को लाल बत्ती बांटकर संतुष्ट करने में ज्यादा लगे रही, जो दंगों को लेकर सरकार को घेरे हुए थे. हालांकि यह काम सरकार ने अपनी मर्जी से कम और मुलायम की मर्जी से अधिक किया था. मुलायम की शह पर ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं को लाल बत्ती बांटी गई थी. सपा प्रमुख की मजबूरी यह है कि उन्होंने कभी देश-प्रदेश के लिए राजनीति नहीं की. वह मुसलमानों, पिछड़ों और खासकर यादवों का ही ढिंढोरा पीटते रहते हैं. इस कौम के लोग और नुमांइदों को सपा राज में कानून से ऊपर छूट मिल जाती है. कई बार तो यह भी देखने में आता है कि अपने वोट बैंक की खातिर मुलायम राष्ट्रहित को भी तरजीह नहीं नहीं देते हैं. उन्हीं के कारण प्रदेश में जातिवादी राजनीति की जड़ें मजबूत हुई हैं. आज भले ही मुलायम राहत कैम्पों में दंगा पीड़ितों की नहीं, कांग्रेस और भाजपा के षड़यंत्रकारियों की मौजूदगी की बात कर रहे हों, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब

> **मौजूदा हालात पर नजर डाली जाए तो आज की तारीख में राहत कैम्पों में सिर्फ पीड़ित ही नहीं रह रहे हैं. अगर कुछ पीड़ित हैं तो कुछ ऐसे लोग भी यहां जुट गए हैं, जो सरकारी मुआवजे की लालच में यहां आकर बस गए हैं. चुनावी मौसम में कुछ न कुछ मिल जाने की उम्मीद ने समाजवादी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. यही वजह थी कि जिस दिन अखिलेश सरकार ने दंगा पीड़ितों को पुनर्वास के लिए पांच लाख रुपये देने की घोषणा का ऐलान किया, उसी दिन यहां सैकड़ों नये कैम्प लग गए थे. यह तथ्य भी चौंकाने वाला है कि कुछ कैम्प निजी स्तर पर चलाए जा रहे हैं.**

शायद ही होगा कि अगर कैम्प में कोई दंगा पीड़ित नहीं रह रहा है तो फिर अखिलेश सरकार राहत शिविरों में उनके बच्चों की मौत की जांच कमेटी बना कर क्यों करा रही है? इतना ही नहीं, अगर राहत शिविरों में कांग्रेसी और भाजपाई रह रहे हैं तो फिर सपा सरकार उन पर पानी की तरह पैसा क्यों बहा रही है? होना तो यह चाहिए था कि मुलायम के बयान को ध्यान में रखकर कैम्प में रहने वालों की जांच राज्य सरकार कराती. यह कहकर समाजवादी पार्टी के नेता बच नहीं सकते हैं कि मुलायम सिंह के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था. असल में समाजवादी नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वह अपनी साख कैसे लौटाए. पश्चिम में न तो जाट और न ही मुसलमान इन पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि सपा का यह मजबूत गढ़ है. मुलायम की मजबूरी ही है, जो वह दंगा प्रभावित लोगों से मिलने अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं.

राहत कैम्पों को लेकर मुलायम का बयान गलत है तो कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी भी इस माममें में दूध के धुले नहीं हैं. वह दूसरी बार यहां आए थे. इससे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने यहां का दौरा किया था. तब भी राजनीति हुई थी और इस बार भी राहुल गांधी कैम्प में बच्चों की मौत से दुखी लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने नहीं आए थे. उनका मकसद एक बार फिर राजनीतिक रोटियां सेंकना ही था. वह सपा सरकार को कटघरे में खड़ा करके मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहते थे. इसमें वह सफल रहे. राहुल के दौरे और मुलायम के बयान के बाद एक सुर में तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं का सपा के खिलाफ मोर्चा खोलना कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है. मुस्लिम धर्मगुरु और जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिन्द के सैयद महमूद मौलाना मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना जिमामुद्दीन, दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना बुखारी, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास, लखनऊ ईदगाह के इमाम फरंगी महली आदि तमाम मौलानाओं ने एक सुर में मुलायम के बयान को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि राहत शिविरों में रह रहे लोग खौफजदा हैं और डर के कारण वे अपने घर नहीं जाना चाहते हैं. इनका सियासत से कोई वास्ता नहीं है. सपा को मुस्लिम विरोधी बताते हुए मौलाना तौकीर रजा और सपा सरकार के एक अन्य मुस्लिम सलाहकार का अपने पद से इस्तीफा देना भी सपा के लिए मुसीबत भरा साबित हुआ. ताज्जुब की बात यह है कि भाजपा भी राहत कैम्पों की राजनीति में हाथ सेंकने में लगी है. वह सपा और कांग्रेस दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर रही है. भाजपा के उपाध्यक्ष अब्बास नकवी ने सपा नेताओं की मानसिकता और राहुल गांधी के दौरे को सेक्युलर टुरिज्म करार देकर दोनों की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोदी को मस्जिद से सलाम, सपाई हलकान

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई है. हर पल कोई न कोई नेता जनता की अदालत में हाजिरी लगा रहा है. सभी अपना-अपना राजनीतिक किला मजबूत करने को आतुर हैं. खासकर सपा और भाजपा कुछ ज्यादा ही उतावली नजर आ रही हैं. इसी उतावलेपन में राजनीतिक शिष्टाचार को भूल कर सपा वाले तो उसी दिन अपनी सभाएं रखने का नया इतिहास बनाते जा रहे हैं, जिस दिन मोदी उत्तर प्रदेश में रैली कर रहे होते हैं. मोदी की आगरा में रैली थी तो समाजवादी नेताओं ने भी इसी दिन बरेली में जनसभा कर डाली. यह संयोग हो सकता था, लेकिन यह नजारा दूसरी बार तब देखने को मिला, जब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वाराणसी में शंखनाद रैली करने पहुंते तो सपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में विकास रैली कर डाली, जबकि बदायूं की रैली की तारीख 21 दिसंबर तय थी और मोदी को 20 दिसंबर को वाराणसी में रैली करनी थी. दोनों की ही जनसभाओं में भीड़ जुटी. पिछली बार समाजवादी नेताओं ने मोदी की आगरा रैली से अपनी बरेली रैली की तुलना करते हुए इसे बीस करार दिया था और मुलायम सिंह यादव ने तो मंच से ही घोषणा कर दी थी कि आगरा में मोदी की रैली में मुश्किल से 10-20 हजार की भीड़ होने की जानकारी उनके पास आई है. इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, जो गलत नहीं है.

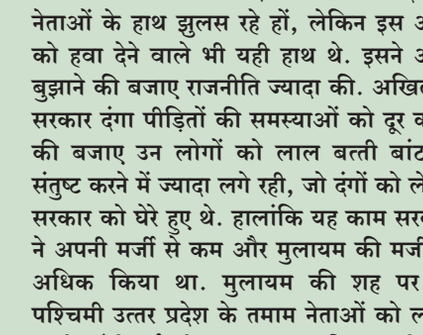

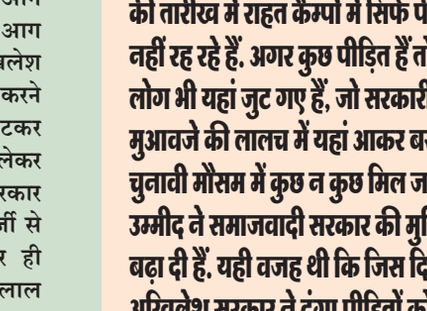

सपा और भाजपा दोनों ही दलों के नेता जनता के सामने लोकलुभावन बाते कर रहे हैं, लेकिन सपा के सामने मजबूरी यह है कि उसके पास जनता को सपने दिखाने के लिए कुछ नहीं है. उसकी सरकार है. वह कितना काम कर रही है? उसके काल में साम्प्रदायिकता की स्थिति क्या है? कानून व्यवस्था के हालात कैसे हैं? यह किसी से छिपा नहीं है. वह जनता की कसौटी पर खरी उतर रही है या फिर नहीं, यह बहस का मुद्दा सपा के लिए तो हो सकता है, लेकिन जहां तक बात आम जनता की है तो उसे नहीं लगता है कि अखिलेश सरकार की छवि सपा की पिछली सरकारों से कुछ अलग है. कई मामलों में न चाहते हुए भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार मुलायम सरकार जैसी ही चल रही है. यही वजह है कि समाजवादी नेताओं की बातों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है. कांग्रेस के साथ गुजारा गया समय सपा के माथे पर कलंक का टीका जैसा प्रतीत हो रहा है. देश में मंहगाई, भ्रष्टाचार, सीमा पर तनाव जैसे तमाम मुद्दे हैं, जिसमें सपा भी कांग्रेस के बराबर की भागीदार है, भले ही सपाई इससे पीछा छुड़ाने की जितनी भी कोशिश करते हैं. यही वजह थी कि बदायूं की विकास रैली में जुटे सपा नेता जनता के बीच कुछ नया नहीं कह पाए. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहचान तो घोषणा मंत्री के रूप में होने लगी है. वह जहां भी पहुंचते हैं, वायदों की बिसात बिछा देते हैं. बदायूं में भी उन्होनें ऐसा ही किया तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव राज्य की समाजवादी सरकार की तमाम नाकामियों के बाद भी सीएम अखिलेश की तरीफ करते रहे. सपा की विकास रैली में मोदी को कोसने और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का भी खूब तानाबाना बुना गया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि समाजवादी पार्टी केन्द्र की मनमोहन सरकार के कई गलत निर्णयों में तो साथ खड़ी रही, लेकिन जब लोकपाल जैसा अहम फैसला केन्द्र ने लिया तो सपा ने उसके साथ खड़े होने का मौका गवां कर अपनी फजीहत कर ली.

दूसरी तरफ नरेन्द्र मोदी वाराणसी में सधे लहजे में जनता को लुभाते रहे. मोदी का जिस तरह से बाबा भोले नाथ की नगरी वाराणसी में स्वागत हुआ, वह समाजवादी सरकार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा. मोदी जब बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गए तो मंदिर से सटे ज्ञानवापी मंदिर के नमाजियों ने उनका स्वागत किया. उनके ऊपर पुष्प बरसाए. जानकार तो यहां तक कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद किसी से छिपा नहीं है. कहा यह भी जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद से कभी भी ऐसे किसी नेता का स्वागत इस तरह नहीं किया गया, जैसा मोदी का हुआ. नमाजियों के इस अप्रत्याशित व्यवहार से उनको अपना वोट बैंक समझने वाले समाजवादी परेशान दिखे. मोदी संकट मोचन मंदिर भी गए, लेकिन यहां उनके जाने के बाद समाजवादी पार्टी के चंद नेताओं ने गंगा जल से मंदिर की सीढ़ियां धोकर यह जता दिया कि अभी भी सपा की सोच में मोदी को लेकर जहर भरा हुआ है.

बहरहाल, मोदी ने वाराणसी के महत्व को समझते हुए उन सभी मुद्दों को छुआ, जो यूपी की जनता को हमेशा कचोटते रहते हैं. गंगा की गंदगी की बात की. किसानों की समस्याओं पर रोशनी डाली. बेरोजगारों और गरीबों का दर्द बांटा. उत्तर प्रदेश में राम राज्य का सपना साकार होने की खुशी जाहिर की तो स्थानीय समस्याओं, खासकर इस व्यवसाय से, जिससे बड़ी संख्या में मुसलमान जुड़े हैं, इसे भी मुद्दा बनाया. पॉवरलूम कारीगरों का दुख-दर्द बांटते हुए इसके लिए राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि पॉवरलूम कारीगरों को आधुनिक तकनीक नहीं प्रदान की जा रही है. मोदी की रैली में अपार जनसमूह देख कर सपा की बदायूं रैली से भी इसकी तुलना की गई. मोदी ने लखनऊ और दिल्ली की सफाई पहले करने का आह्वान करके कांग्रेस और सपा दोनों को घेरा. भीड़ और जनता की नब्ज टटोलने जैसे दोनों ही मामलों में मोदी सपा नेताओं से बीस साबित हुए. ■

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

मुलायम को छवि की चिंता, नेता बिगाड़ने में मस्त

संजय सक्सेना

समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की हनक और धमक अब पहले जैसी नहीं रह गई है. सरकार और संगठन दोनों ही जगह उनके आदेशों की नाफरमानी हो रही है. सपा सरकार के मंत्रियो और जनप्रतिनिधियों ने तो शायद कसम ही खा ली है कि उन्हें अपने हित साधने हैं. संगठन और सरकार की छवि धूमिल होती है तो होती रहे, वह अपना ढर्रा नहीं बदलेंगे. ऐसा नहीं है कि सरकार और संगठन की बदनामी छोटे नेता ही करा रहे हैं, बल्कि सपा के बड़े-बड़े सूरमा भी बदनामी और बदमाशी के इस 'हवन' में घी डालने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. कहीं बाहुबल से तो कहीं बदजुबानी से, यह नेता पार्टी और सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा प्रमुख मुलायम सिंह सत्ता हासिल करने के दिन से ही अपनी पुरानी 'इमेज' बदलना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. सपा सरकार और संगठन में अंधेरगर्दी और गुंडागर्दी बढ़ रही है. सपा आलाकमान चिंतित है, लेकिन बुद्धिजीवी इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ज्यादा कसूरवार मानते हैं. इन लोगों का कहना है कि जब अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों को और बाबू सिंह कुशवाहा जैसे भ्रष्टाचारियों को पार्टी गले लगाएगी तो यह सब तो होगा ही.

वोट बैंक की राजनीति के कारण सपा आलाकमान पार्टी में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त कर रहा है. नेतृत्व की यह कमजोरी सपा के मिशन 2014 के मार्ग में रोड़ा बन जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए. प्रदेश में चौतरफा हालात बिगड़ रहें हैं, लेकिन इसके आका तमाम नाकामियों के लिए विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करने में लगे हैं. बीते दिनों सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 111वीं जयंती पर चौधरी साहब की राजनीति से सबक लेने के बजाए विपक्ष पर हमला बोला तो यह कयास लगने शुरू हो गए कि मुलायम में अपना पहले जैसा दमखम नहीं रह गया है. वह सपा के दामन के दाग साफ करने के लिए विपक्ष पर कीचड़ उछाल कर अपना ही अहित कर रहे हैं. बात मुलायम के पिछले दिनों बयान की कि जाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस, भाजपा और बसपा नेता समाजवादी पार्टी के खिलाफ षडयंत्र कर रहे हैं, जिससे साम्प्रदायिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है, समझ से परे है. वह साम्प्रदायिक शक्तियों से लड़ने में अपने आप को सक्षम बताते हैं तो सवाल खड़ा करते हैं कि गुजरात में मुस्लिमों का कत्लेआम कराने वाले को देश कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकता है. इस पर सवाल भी खड़ा करते हैं. वहीं, यह दावा भी करते हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस और भाजपा की नहीं, तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और इसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल होने के कारण निर्णायक भूमिका निभाएगी.

श्री यादव ने यह बातें अगर अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास जताने के लिए कही हों तो समझ में आता है. उनका हक है कि अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें, लेकिन उन्हें इस बात को भी समझना होगा कि देश के लिए जितनी खतरनाक साम्प्रदायिकता है, इससे कम तुष्टिकरण की राजनीति भी नहीं है. मुलायम कहते हैं कि जनता को भटकाने की साजिशें हो रही हैं. कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए वह कहते हैं कि बिना पूर्व सूचना शामली के एक कैम्प में जाकर बेवजह एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है. समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर-शामली के पीड़ितों की जितनी मदद की, उतनी कभी किसी सरकार ने नहीं की. समाजवादी पार्टी सरकार ने मकान बनाने के लिए 5-5 लाख रुपये, सामान खरीद के लिए 2-2 लाख रुपये दिए. मृतकों के आश्रितों को नौकरी दी. कांग्रेस और बसपा राज में हुए दंगा पीड़ितों को किसी ने न्याय नहीं दिया. मुलायम के दावे में दम है और यह हकीकत है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा पीड़ितों के कैम्प सियासत का अखाड़ा बन गए हैं, लेकिन सपा की प्रदेश सरकार वोट बैंक की राजनीति की वजह से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने से बच रही है, जो राहत कैम्पों पर राजनीति कर रहे हैं. कायदे से तमाम सुविधाएं हासिल करने के बाद भी वहां से नहीं हटने वालों को खदेड़ देना चाहिए, जो सरकार नहीं कर पा रही है.

कोई एक मोर्चा नहीं, सभी मोर्चों पर अखिलेश सरकार और समाजवादी पार्टी की थू-थू हो रही है. यही वजह थी कि 23 नवंबर को सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव पार्टी मुख्यालय में नौजवानों का आह्वान कर रहे थे कि वे फिर विधानसभा चुनावों की तरह साइकिल यात्राएं करके जनता के बीच जाएं और समाजवादी पार्टी सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाएं. वहीं, वह यह नसीहत भी दे रहे थे कि वे बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने के लिए संकल्पित हों. तभी दिल्ली में समाजवादी सरकार बनाने का सपना पूरा होगा. कार्यकर्ता अपने आचरण और व्यवहार में विनम्रता रखें और अन्याय के विरोध तथा सच्चाई के साथ चलें. मुलायम ने यहां तक कह दिया कि पार्टी की छवि खराब करने वालों की अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर कतई बर्दाश्त नहीं होगी. गुंडई की, तो पार्टी से निकाल दूंगा, लेकिन अफसोस, जिस समय वह अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे, ठीक उसी वक्त उनका सीतापुर जिले के सिधोली क्षेत्र का एक विधायक मनीष रावत एक शिक्षिका को फोन पर मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा था. इस शिक्षिका को प्रधानपति मदनगोपाल ने जान से मारने की धमकी देते हुए गाली-गलौज की थी, जिस पर शिक्षिका ने मुकदमा लिखा दिया था. दबंगई का आलम यह था कि विधायक जी ताल ठोंककर कह रहे थे कि मैंने शिक्षिका को फोन किया था. कहा था कि मुकदमा हो चुका है. इतना बड़ा मामला नहीं है. प्रधानपति की सजा पूरी हो चुकी है. सुलह कर लो. विधायक जी का कहना था कि मुझे यहीं राजनीति करनी है. इसलिए प्रधानपति की मदद करना मेरी मजबूरी है. तुम बाहर की हो. इस जिले का कोई विधायक पहली बार किसी को धमकाने के चक्कर में बदनाम नहीं हुआ है. इससे पूर्व सपा के एक अन्य विधायक महेन्द्र गोवा में रंगेलियां मनाते पकड़े जा चुके हैं. जौनपुर के विधायक और मंत्री पारसनाथ यादव का बेटा भी मारपीट के एक मामले में फंस हुआ है. उसने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जिला महासचिव महावीर यादव को जमकर पीटा था. हाल में ही सपा में शामिल होकर टिकट पाने वाले बाहुबली अतीक अहमद भी दबंग व्यवहार के कारण पिछले दिनों सुर्खियां बटोर चुके हैं. यह सिलसिला लम्बे समय से चल रहा है. विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद से ही सपा नेता बेकाबू हो गए थे. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अब तो राजनीतिक पंडित तो दावा भी करने लगे हैं कि मुलायम को सपा नेताओं की दबंगई के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन

शिवनाथ चतुर्वेदी

सुगंधित फूलों व आकर्षक पत्तियों से सजा भव्य पंडाल. यहां न तो जाति-धर्म की बेड़ियां थीं, न ही अमीरी-गरीबी का फर्क. अगर कुछ था तो प्रेम व भाईचारा. यह नजारा बल्भ नीतीश सेवा संस्थान, अमृतपाली द्वारा प्राथमिक विद्यालय अमृतपाली (बलिया) के प्रागंण में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह का रहा. इस विवाह समारोह में एक साथ 21 जोड़ों ने पूरे रीति-रिवाज से एक-दूजे के बंधन में बंध गए. वैदिक मंत्रोचार के बीच सात फेरे लेकर सभी ने सात जन्मों तक साथ जीने-मरने की कसमें खाई.

बारात रामलीला मैदान से पूरे शानो-शौकत के साथ उठी. बैंड बाजा की धुन पर थिरकते बारातियों के बीच दूल्हे राजा राजसी ठाट के साथ चल रहे थे. जब बारात प्राथमिक विद्यालय पहुंची तो वहां आयोजक डॉ हरेराम के नेतृत्व में बारातियों का स्वागत हुआ. फिर जोड़ों को मंडप स्थल तक ले जाया गया. वहां वर-वधू के परिजन पारम्परिक रीति-रिवाजों को निभाते हुए कन्यादान किया. हर जोड़े ने अग्नि को साक्ष्य मान कर फेरे लिए. उन्हें आशीर्वाद देने के लिए बलिया पुलिस अधीक्षक राजू बाबू सिंह व अन्य विशिष्ट जन भी पहुंचे थे. पुलिस अधीक्षक राजू बाबू सिंह ने कहा कि सामूहिक विवाह समाज को जोड़ने एवं मजबूर लोगों को सम्मान दिलाने का आयोजन है, जिसे बढ़ावा देने की जरूरत है. इसके बाद विदाई बेला आई, जिसमें हर किसी की आंखें अपनों से बिछड़ने के गम में नम हो गई. आयोजन समिति की ओर से सबको गृहस्थी में उपयोग आने वाली वस्तुएं देकर विदा किया गया. इस पल का गवाह बनने के लिए हजारों लोग जुटे थे. शादी के बाद डॉ हरेराम ने सभी को संस्था की ओर से विवाह का प्रमाण पत्र भी दिया. ■

मोदी से अब भयभीत नहीं होता मुसलमान

अजय कुमार

क्या मुसलमानों के बीच भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेन्द्र मोदी सधे हुए कदमों से अपनी स्वीकार्यता बढ़ा रहे हैं. यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है. भले ही मोदी विरोधी इस बात को न स्वीकारें, लेकिन हकीकत को लम्बे समय तक दबाया या छिपाया नहीं जा सकता है. अब मोदी अपने को हिन्दू हृदय सम्राट कहलाना पसंद नहीं करते हैं. भले ही उन्हें इस्लामिक टोपी पहने से परहेज हो, लेकिन उनके भाषणों में अब पवित्र मक्का से लेकर गरीब पॉवरलूम कारीगर तक, सब समाहित रहते हैं. उन्हें वालेकुल सलाम कहने से भी परहेज नहीं है. उनकी रैलियों का नजारा भी धीरे-धीरे बदलने लगा है. मुसलमान भले ही उनको वोट न दे, लेकिन उनकी बात सुनने में इसे कोई परहेज नहीं लगता है. अब उन्हें कुछ राजनीतिक दलों और कठमुल्लाओं का डर नहीं सताता है, जो मोदी के माथे पर साम्प्रदायिक का ठप्पा लगाने को आतुर रहते हैं. ऐसा लगता है कि जिस तरह से बहुसंख्यक समाज ने पंडितवाद को हासिये पर डाल दिया है, वैसे ही मुस्लिम समाज मौलानाओं को किनारे करके अपनी जिंदगी के फैसले करना चाहता है. अब इसके लिए मौलाना और धर्मगुरुओं की महत्ता धार्मिक मामलों तक सीमित रह गई है. यही वजह है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली सफलता ने मुस्लिम हितों से सरोकार रखने वाले तमाम उलेमाओं की उलझनें बढ़ा दी हैं. तमाम उलेमा इस सफलता का श्रेय भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को देने में लगे हैं, पर्दे के पीछे से ही सही. वहीं कुछ एक तो खुल कर मोदी के समर्थन में आ गए हैं. वे उत्तर प्रदेश की सियासत पर इसके पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन करने में लगे हैं.

दारूल उलूम वक्फ के मौलाना अब्दुल्ला जावेद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भाजपा को फिर खड़ा कर दिया है. वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह खुद की उदार छवि भी तेजी के साथ पेश करते दिख रहे हैं. मौलाना जावेद भाजपा को हाल में मिली जबरदस्त सफलता के पीछे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भूमिका मानते हैं. वो कहते हैं कि जिस तरह दिल्ली के मतदाताओं में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की अपील है, वैसी ही अपील उत्तर भारत के मतदाताओं के बीच मोदी की भी दिखती है. इसका कारण भी वह बताते हैं. चाहे कांग्रेस हो अथवा सपा-बसपा जैसे तमाम राजनीतिक ताकतें, उन्होंने मुसलमानों के विकास की ओर कभी ध्यान नहीं दिया और मुस्लिमों को धर्म और भाजपा के हौवे में उलझाए रही. इसी के चलते न केवल मुसलमान पिछड़ गया, बल्कि समाज में सलीके से घुल-मिल भी नहीं पाया.

मुसलमानों का एक बड़ा तबका मानता है कि भाजपा नेतृत्व ने नरेद्र मोदी का जिस रणनीति के तहत इस्तेमाल किया, वह अचूक है. मोदी के नेतृत्व में लड़ रही भाजपा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों को अपने पक्ष में मोड़ने की कूबत रखती है. भले ही उनके खाते में मुसलमानों का वोट बड़े वोट बैंक के रूप में न जाए. मुस्लिम बुद्धिजीवी मानते हैं कि कई राज्यों में भाजपा का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से होगा. इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है. यहां सपा का जनाधार और लोकप्रियता, दोनों का ग्राफ तेजी से न केवल गिरा है, बल्कि उसके गिरने का क्रम आगे भी जारी है. मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद मुसलमानों का भरोसा सपा से टूटा है. ऐसे में कुछ संख्या में मुस्लिम बसपा के साथ जा सकते हैं. मायावती किस तरह से अपनी चाल चलती हैं, इस पर भी उनकी कामयाबी का दारोमदार होगा.

बात भाजपा की कि जाए, तो मोदी ने कम से कम ऐसे हालात तो बना ही दिए हैं कि अब उनके खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक डर के मारे किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं झुकेगा. इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है. भाजपा के बदले रुख का ही नतीजा है, जो आज मुसलमानों का एक धड़ा भाजपा से संवाद बनाने की बात कहने लगा है. भाजपा से बातचीत करने के हिमायती उत्तर प्रदेश मुस्लिम मजलिस के प्रांतीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता बदर काजमी कहते हैं कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि राजस्थान में मुसलमान और जाट वसुंधरा राजे का समर्थन कर रहे हैं. इसके साथ ही काजमी जोड़ देते हैं कि उनकी इस राय से कट्टरपंथी मुस्लिम सहमत नहीं थे, लेकिन राजस्थान के नतीजों ने उन्हें गलत और हमें सही साबित कर दिया. राजस्थान में भाजपा के तीन में से दो अल्पसंख्यक उम्मीदवार विजयी रहे, जबकि कांग्रेस के एक को छोड़कर सभी मुस्लिम उम्मीदवार परास्त हो गए.

मौजूदा हालात यह है कि मोदी को लेकर मुसलमानो में भी दो फाड़ हो गया दिखता है. देवबंदी मुस्लिमों की दो धाराएं विपरीत दिशाओं में चल रही हैं. दारूल उलूम के हदीस के वरिष्ठ उस्ताद और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी धड़े को कट्टर मोदी विरोधी माना जाता है. अरशद मदनी के विरोध की वजह से ही मौलाना गुलाम मोहम्मद वास्तानवी को दारूल उलूम के मोहतमिम का पद खोना पड़ा था. मौलाना अरशद मदनी केन्द्र में कांग्रेसी विचारधारा के हैं. उनके सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ अच्छे संबध हैं. वह यूपी की सपा सरकार के हिमायती भी हैं. वहीं, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव मुजफ्फनरगर दंगों के बाद से मौलाना अरशद मदनी पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रहे हैं. मुजफ्फरनगर के हालात को समान्य बनाने के उद्देश्य से मेरठ जोन के आईजी का अतिरिक्त प्रभार देकर भेजे गए आगरा के आईजी आशुतोष पांडेय का दो बार देवबंद जाकर मौलाना अरशद के साथ एकांत में लंबी मंत्रणा करना, यह दर्शाने के लिए काफी है कि सपा को उन पर कितना भरोसा है.

एक तरफ मौलाना अरशद कांग्रेस और सपा खेमें में खड़े हैं तो दूसरी ओर मौलाना महमूद मदनी, जिनको नरमपंथी विचारधारा का माना जाता है, जो राज्यसभा के सदस्य रह भी रह चुके हैं, वह कांग्रेस से काफी नाराज हैं. मदनी चुनाव पूर्व राजस्थान का दौरा कर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार को अकलियत का दुश्मन घोषित कर आए थे. बताते चलें कि कई कांग्रेसी नेता मदनी पर मोदी और भाजपा समर्थक होने के आरोप भी जड़ चुके हैं, जो नतीजे राजस्थान में निकले हैं, जाहिर है महमूद मदनी को इससे जरूर राहत मिली हो. सपा, बसपा और कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरुओं का ही नहीं, मुस्लिम जनता का भी विश्वास उठता जा रहा है और मोदी इसे सुनियोजित तरीके से अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए वह गुजरात दंगों को इतिहास के पन्नों में लपेट कर वालेकुल सलाम की राजनीति पर विश्वास करने लगे हैं. अगर ऐसा न होता तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर से पूजा-अर्चना करने के चंद मिनटों के भीतर मंच पर पहुंचे मोदी के माथे का टीका साफ दिखाई देता. मोदी के नाम से अब मुसलमान को डर नहीं लगता है. वह इस हकीकत को समझ गया है कि हिन्दू और मुसलमान लड़-भिड़ कर लम्बे समय तक खुश नहीं रह सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

आम चुनाव में राजनीतिक दल चलाएंगे वादों के ब्रह्मास्त्र

अरविंद राम त्रिपाठी

इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगामी आम चुनाव में आप की धमक, मोदी की चमक और कांग्रेस की सनक से आम मतदाता प्रभावित होगा. यूपी में कहीं कहीं हाथी के चिंघाड़ने की आवाज भी सुनाई देगी तो साइकिल से गांव-गांव बटे बेरोजगारी भत्ते, कन्या विद्या धन और लैपटॉप की गूंज भी सुनाई देगी. भौतिकवादी इस युग में शहरी फैशन से प्रभावित ग्रामीण युवा वर्ग चुनाव परिणाम को किस कदर प्रभावित करते हैं, इसका अंदाजा राजनीतिक दलों को यूपी के विधानसभा चुनाव के परिणाम से लगा लेना चाहिए. जब बेरोजगारी भत्ते और भर्तियों की आस में बेरोजगार युवा वर्ग दलगत, जातिगत और नीतिगत भावनाओं से उठकर लाभ की प्रत्याशा में समाजवादी पार्टी को अभूतपूर्व बहुमत प्रदान कर दिया. हर दलों के पास इस बार के आम चुनाव के लिए भी कुछ लॉलीपॉप मौजूद है, जो वे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे. सभी का दावा बेहतर और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की होगी. भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा यूपी में अब तक लड़ते रहें हैं और उन्हें अच्छा-खासा जन समर्थन भी मिला है.

> **भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है. आम धारणा है कि अटल विहारी वाजपेयी का कार्यकाल अपेक्षाकृत अच्छा रहा है. इसका लाभ बीजेपी को मिलता रहा है. अब मोदी के व्यक्तित्व को भुना कर सत्ता पर काबिज होने की जुगत में कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहें है. हालांकि अभी किसी दल ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन चुनावी सभाओं में मोदी और अन्य नेताओं के वायदों से ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें केवल मोदी के नाम पर ही वोट मिलने की उम्मीद है, अन्य किसी मुद्दे पर नहीं.**

लोकसभा में यूपी से इन चारों दलों के माननीय मौजूद रहें हैं. मौजूदा समय में सपा और बसपा कांग्रेस की मनमोहन सरकार को बाहर से समर्थन दिए हुए हैं या यूं कहें कि सपा-बसपा कांग्रेस के साथी हैं और केंद्र सरकार के हर निर्णय उनकी इच्छा व स्वीकृति से ही हुए हैं तो यह गलत नहीं होगा. आम चुनाव में ये दोनों दल अलग-अलग लड़ेंगे. कदाचित दोनों कांग्रेस से बेहतर सरकार देने का वादा भी करें और कांग्रेस पर खुलकर उलूल-जलूल आरोप भी लगाएं, लेकिन आम मतदाता इतनी भोली भी नहीं है कि इनके मायाजाल को जानती नहीं है. जानती तो सब है, लेकिन कुछ करती नहीं है. आइए, हम भाजपा, कांग्रेस, सपा व बसपा के ब्रह्मास्त्रों का परीक्षण व विश्लेषण करके यह देखें कि इनमें कितनी मारक क्षमता है.

कांग्रेस के पास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, लोकपाल विधेयक, महिला उत्पीड़न के लिए कानून में संशोधन सहित कई अन्य ब्रह्मास्त्र हैं, जो चुनाव में कांग्रेस आम मतदाताओं पर चलाएगी. मनरेगा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है. कस्बों में लगने वाले लेबर मार्केट मनरेगा को मुंह चिढ़ा रहें हैं. मजदूरों का एक ही सवाल होता है कि क्या सौ दिन की दिहाड़ी से तीन सौ पैंसठ दिन पेट भरा जा सकता है. दूसरा सवाल हुक्मरानों की नींद उड़ाने वाली होती है कि जब मार्केट में मनरेगा से ज्यादा मजदूरी प्रतिदिन नगद मिल रही है तो मैं वहां काम करने क्यों जाएं. मनरेगा की मौजूदा हालत यह है कि इसमें वही काम करते हैं, जो किसी काम लायक नहीं होते, वे केवल भ्रष्टाचार की एक कड़ी बनते हैं. कुल मिलाकर यह कहा जाए कि मनरेगा भ्रष्टाचार नामक बीमारी की शिकार हो गई और वर्तमान में वह वेंटिलेटर पर है तो गलत नहीं होगा.

खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के पास भेज रहें हैं. मतदाता इसे कितना वेटेज दे रहें हैं, इसका अंदाजा आप हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों से लगा सकते हैं. भूखमरी दूर करने का शायद कांग्रेस के पास कोई और उपाय नहीं था. कदाचित इसीलिए कांग्रेस लोगों को कम पैसे में बेकारी परोस रही है. इक्कीसवीं सदी में विकसित व सभ्य राष्ट्र की कल्पना करते हुए देश को तरक्की के पथ पर अग्रसर बताने वाले देश के मौजूदा भाग्यविधाता अभी यह नहीं जान पाए कि आम जनता को भोजन की थाली कितने रुपये में मिलती है. भूख से मर रही जनता तो यह मानकर चल रही है कि इनके लिए दिया जा रहा सरकारी राशन बड़े लोगों की ही क्षुधा शांत करेगा.

लोकपाल विधेयक से तकरीबन 35 प्रतिशत जनता को कोई मतलब ही नहीं है. वह जानते हैं कि भ्रष्टाचार की गंगा भी बहती है और लोकपाल भी आदमी ही होगा. गलती इससे भी हो सकती है. कोइ नृप होई हमें का हानि, की सोच वाली जनता न तो लोकपाल को जानती है और न तो जोकपाल को, इसे तो दिन-रात पापी पेट का सवाल ही सताए रहता है.

महिलाओं और मुसलमानों का वोट सहेजने के लिए कांग्रेस काफी प्रयासरत रही, लेकिन इसके उम्मीदों पर तो दिल्ली में ही पानी फिर गया. कांग्रेस की महिला मुख्यमंत्री अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रही. हाल के सालों में बेतहासा बढ़ी महंगाई ने चूल्हा-चौका सबको धक्का देकर अपनी जगह स्थाई कर ली है, जिससे सभी परेशान हैं. यूपी में मुस्लिम मतदाताओं के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस तीन महफूज दल हैं, लेकिन कदाचित वो वोट इसी दल को देते हैं, जो भाजपा को हराने में कामयाब हो सकें. ऐसे में यूपी में कांग्रेस को महिला और मुस्लिम मतदाता से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए. लिंग भेद को बढ़ावा देकर महिलाओं के लिए सख्त कानून बना देने से कांग्रेस इस मुगालते में न रहे कि अब तो महिलाओं का वोट इसे मिलेगा ही. महिला संगठन समाज में फैली बदनामी से कितनी नाराज हैं, इसका परिणाम भी भुगतना होगा. कुल मिलाकर यूपी में कांग्रेस को इस बार कोई लाभ होता नजर नहीं आ रहा है.

भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है. आम धारणा है कि अटल विहारी वाजपेयी का कार्यकाल अपेक्षाकृत अच्छा रहा है. इसका लाभ बीजेपी को मिलता रहा है. अब मोदी के व्यक्तित्व को भुना कर सत्ता पर काबिज होने की जुगत में कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहें है. हालांकि अभी किसी दल ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन चुनावी सभाओं में मोदी और अन्य नेताओं के वायदों से ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें केवल मोदी के नाम पर ही वोट मिलने की उम्मीद है, अन्य किसी मुद्दे पर नहीं. बीजेपी अपने पुराने मुद्दों को तो भूल ही चुकी है, कोई नया मुद्दा इसके पास है नहीं, इसे अगर लाभ मिलेगा तो कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार का, यूपी में सत्तारूढ़ सपा से आम जनता की नाराजगी का, सत्ता परिवर्तन की लहर का. बहरहाल, अगर भविष्य के आइने में झांक कर देखा जाए तो सपा, बसपा को छोड़कर यूपी में भाजपा की टांग खिंचने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है और आम मतदाता एक बार मोदी को भी देखने की मंशा जाहिर करते नजर आ रहें हैं.

> **कांग्रेस के पास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, लोकपाल विधेयक, महिला उत्पीड़न के लिए कानून में संशोधन सहित कई अन्य ब्रह्मास्त्र हैं, जो चुनाव में कांग्रेस आम मतदाताओं पर चलाएगी. मनरेगा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है. कस्बों में लगने वाले लेबर मार्केट मनरेगा को मुंह चिढ़ा रहें हैं. मजदूरों का एक ही सवाल होता है कि क्या सौ दिन की दिहाड़ी से तीन सौ पैंसठ दिन पेट भरा जा सकता है. दूसरा सवाल हुक्मरानों की नींद उड़ाने वाली होती है कि जब मार्केट में मनरेगा से ज्यादा मजदूरी प्रतिदिन नगद मिल रही है तो मैं वहां काम करने क्यों जाएं.**

सूबे में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और विपक्षी बहुजन समाज पार्टी अपने बूते कभी लाल किला पर तिरंगा फहराने की सोच भी नहीं सकते. इनके पास बस इतनी ही सीटें होती हैं कि वे किसी को समर्थन दे दें और दो-चार महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने हिस्से में मांगकर केंद्र में सत्तारूढ़ हो लें और अपना राजनीतिक व्यवसाय चमका लें. थानों पर सपा कार्यकर्ताओं की धमक और हर विभागों में इनकी पूछ से आम मतदाता परेशान नजर आ रहा है. आम कार्यकर्ताओं की तो चांदी है, लेकिन इसका खामियाजा सपा के मिशन 2014 पर पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. मौजूदा समय में सपा व बसपा के पास ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, जिससे प्रभावित होकर आम चुनाव में मतदाता इनके खेमें में गिर पड़े. धर्मनिरपेक्षता का ठीकरा भाजपा पर फोड़कर, जातिवाद, संप्रदायवाद, और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर ये दोनों दल अपनी वैतरणी पार लगाने की जुगत में हैं, लेकिन कांग्रेस की खिलाफत करने की स्थिति में ये दोनों दल नहीं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही कांग्रेस के साथी रहें हैं. सपा बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप और कन्या विद्या धन जैसे अपने जंग खाए पुराने हथियार को चलाएगी और मुस्लिमों को अभियोजन वापसी का हवाला देकर अपने पास लाने का प्रयास करेगी. बसपा अपने परंपरागत मतदाताओं को सहेजकर उन्हें सर्वजन समाज का पाठ पढ़ाकर बहुजन मिलाय स्वजन सुखाय की नसीहत देगी और अन्य जातियों का वोट बटोरने का प्रयास करेगी. सोशल इंजीनियरिंग का ब्रह्मास्त्र चलाएगी, लेकिन कदाचित चार राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम और यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम से तो यही लगता है कि आम मतदाता जोड़-तोड़ को नकार चुकी है और किसी न किसी को पूर्ण बहुमत देगी. यह सही भी है और समय की मांग भी कि आम मतदाता किसी एक दल को पूर्ण बहुमत प्रदान करें. तभी मजबूत लोकतंत्र, सशक्त सरकार, निष्पक्ष और जनता के प्रति जवाबदेह सरकार बन सकती है.

यूपी में लोकतांत्रिक कांग्रेस, स्वर्ण समाज पार्टी, पीस पार्टी, अपना दल जैसे कई दलों का दलदल भी है, जिसमें कुछ प्रतिशत मतदाता गिर पड़ते हैं. आम चुनाव के लिए इसे नकारात्मक वोट माना जा सकता है. यूपी जैसे बड़े राज्य में आम आदमी पार्टी कितना दम दिखा पाएगी और कितना लाभ प्राप्त करेगी, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आम लोगों का मानना है कि यूपी की जनता अब इन दलों के दलदल में गिरने वाली नहीं है और केंद्र के लिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में फिट, शक्तिशाली, मजबूत और बिना बैशाखी की सरकार बनाना चाहती है. अगर ऐसा होता है तो यूपी की जनता बधाई की पात्र होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

फूड डिपार्टमेंट भ्रष्ट अधिकारियों के हवाले

प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

जनपद पीलीभीत में फूड डिपार्टमेंट को एक भ्रष्ट अधिकारी चला रहा है, जिसका नाम है अशोक कुमार मिश्रा. यह महानुभाव जिला खाद्य निरीक्षण अधिकारी के पद पर तैनात हैं. अशोक कुमार मिश्रा ने इस पूरे साल में अब तक केवल 65 दुकानों के सैम्पल ही भरे हैं. सवाल यह उठता है कि क्या पूरे पीलीभीत में केवल 65 दुकानों पर ही मिलावटी सामान मिलता है. इनमें से कितने दुकानों पर कार्रवाई हुई, यह तो बाद की बात है, लेकिन यह सच है कि पूरे पीलीभीत जनपद में हजारों की संख्या में खाद्य पदार्थों की दुकानें कुकुरमुत्तों की तरह जगह-जगह मौजूद हैं. आज के भ्रष्ट तंत्र में 80 प्रतिशत खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है. दूध, मिठाई, दालें, चावल, आटा, मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला या सरसों का तेल, बाजार में खाने की कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं मिल सकती. बाजार में सड़े-गले फल बेचते जगह-जगह ठेले वाले मिल जाएंगे. बाजार में बिना किसी परीक्षण के बकरे या मुर्गे का मीट बिक रहा है. अक्सर मीट या मछली खाने से बीमार लोगों की खबरें सुनने में आती रहती हैं. कभी-कभी यह भी सुनने में आता है कि खोया खाने से या सरसों का तेल खाने से पूरा का पूरा परिवार गम्भीर रूप से बीमार पड़ गया. जनता जब स्वास्थ्य विभाग पर इसका आरोप लगाती है तो स्वास्थ्य विभाग पुराना राग अलापने लगता है कि फूड प्वॉयजनिंग से लोग बीमार हुए हैं या विभाग यह कह कर पल्ला झाड़ लेता है कि इनकी मौत फूड प्वॉयजनिंग से हुई है. दुख की बात यह है कि जिला खाद्य निरीक्षण अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा का मोबाइल फोन अधिकतर व्यस्त या बन्द रहता है. यह श्रीमान अपने ऑफिस, जो कलेक्ट्रेट जनपद पीलीभीत में स्थित है, पर कभी नहीं मिलते हैं. इस बाबत जब चौथी दुनिया की टीम ने उनसे जानकारी मांगी तो आश्चर्यजनक जवाब मिला कि हम अधिकतर फील्ड में रहते हैं, जिस कारण हम कार्यालय में नहीं मिल पाते. अब सवाल यह उठता है कि जो अधिकारी महीने के 25 दिन फील्ड में रहता हो तो इसके द्वारा केवल 65 दुकानों से सैम्पल क्यों एकत्रित किए गए. यह विचारणीय है और यही सवाल उनके भ्रष्ट होने का प्रमाण भी है. चौथी दुनिया की टीम ने जब सैम्पल भरने के साल भर के टारगेट के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि हमारे विभाग को ऐसा कोई भी टारगेट नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा कि चाहे हम एक सैम्पल भरें या 100, यह हम पर निर्भर करता है. उन्होंने यह भी कहा कि न ही उन्हें कार्यालय में बैठने का कोई आदेश है. उन्होंने बताया कि हमारे सबसे बड़े अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट हैं, जो कि रोज अपने कार्यालय में बैठते हैं. उन्होंने बताया कि करीब 800 दुकानों के लाइसेंस इस साल बनाए गए हैं. कैम्प लगाकर दुकानदारों के पंजीकरण किए जा रहे हैं. चौथी दुनिया की टीम ने जब जिले में सर्वे कर दुकानदारों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि लाइसेंस शुल्क 100 रुपये की जगह 300 रुपये लिए गए हैं. सुविधा शुल्क न देने पर चालान करने की धमकी दी जाती है. इसी विभाग के एक कर्मचारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि अशोक कुमार मिश्रा काफी शातिर व्यक्ति हैं. अगर हमलोग किसी दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते या छापा मारते हैं तो पीछे से ये उस व्यक्ति से सौदा कर मामले को रफा-दफा कर देते हैं और इससे मिली अवैध रकम को खुद ही हड़प जाते हैं. विभाग के लोग उनसे काफी भयभीत रहते हैं. इसका कारण यह है कि अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को अपनी राजनीतिक पकड़ का वास्ता देकर ये धमकाते हैं कि अगर मेरे विरुद्ध मुंह खोला तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे. इस आतंक के कारण कोई उनके विरुद्ध मुंह नहीं खोलता है. ■

अजय कुमार, लखनऊ ब्यूरो प्रमुख कार्यालय का पता : जे-3/2 डॉलीबाग़, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन -(0522) 2204678/09415005111